भारतीय मजदूर संघ

स्वर्ण जयन्ती

(1955–2005)

50

महामंत्री प्रतिवेदन

14वाँ अखिल भारतीय अधिवेशन

3, 4, 5 अप्रैल 2005

रामलीला मैदान, दिल्ली

हमारे मार्ग दर्शक

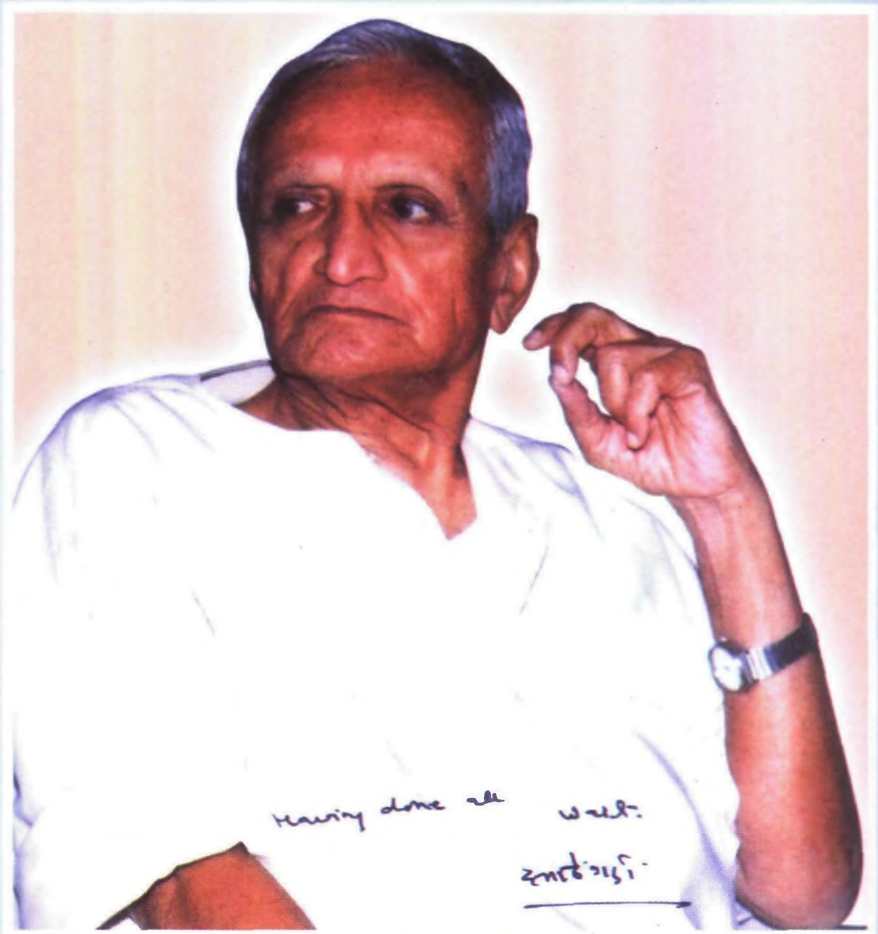

श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ीजी

जन्म	देहान्त
10 नवम्बर 1920	14 अक्टूबर 2004

अजात शत्रु स्व. दत्तोपंत ठेंगडी

महाराष्ट्र प्रदेश के वर्धा जिले के आर्वी नामक गाँव मे 10 नवम्बर 1920 को जन्मे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, एवं स्वाभाविक रूप से, संघ दृष्टि से जुडे देश–विदेश के 50 से अधिक संगठनों के प्रेरणा स्रोत दत्तोपंत ठेंगडी के 14 अक्टूबर 2004 को देहत्याग के समचार ने करोडो राष्ट्र प्रेमी नागरिकों को द्रवित कर दिया। संघ की ध्येयनिष्ठा पद्धति में यद्यपि व्यक्तिनिष्ठा का कोई स्थान नहीं, किन्तु ठेंगडी जी के द्वारा साधे गए लक्ष्यों और कार्यो को स्मरण करके कार्यकर्ताओं का शोकाग्रस्त होना स्वाभाविक है। उनकी दैहिक बंधन से मुक्ति एवं हमारी यह अनुभूति कि वे अब कभी नहीं मिलेंगे, उनके विराट स्वरूप की झलक देती है। वे एक मौलिक चिन्तक, दृष्टा, संगठक, विचारक, अर्थ–समाज शास्त्री, एवं प्रखर वक्ता थे। उनका आत्मलोपी, विनम्र और आत्मीयता से भरा स्वभाव उनसे मिलने वाले लोगों को तुरन्त यह आभास करा देता था कि वे उन्हीं के है, और समाज के एक उपयोगी घटक है। इसप्रकार अनगिनत अति साधारण लोगों को उन्होंने देखते ही देखते सुपात्र बना लिया था।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूज्य गुरूजी ने जब यह देखा कि देश के श्रमिक जगत को राजनेताओं ने अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है और सभी ट्रेड यूनियनें या तो राजनीति की चेरी हैं, या पदत्त विषम परिस्थितियों में यह मान लेने को बाध्य है कि उनके जीवन का लक्ष्य केवल रोटी, कपडा और मकान प्राप्त कर लेना है। वकालत की पढाई के बाद प्रचारक बने प. पू. गुरुजी ने ठेंगडी जी को श्रमिक क्षेत्र में काम खडा करने का दायित्व सौंपा उस समय जिन ट्रेड यूनियनों का वर्चस्व था उनकी निष्ठाएँ परस्पर संघर्ष पर आधारित विदेशी विचारधाराओं से जुडी हुई थी। ठेंगडी जी को अपने मध्य पाकर स्वदेशी विचारधारा के श्रमिक संगठित हो गए और यह निश्चय कर लिया कि राष्ट्रहित की मर्यादा का पालन करते हुए, श्रमिकों के सर्वांगीण हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि ठेंगडी जी के मार्गदर्शन में एक राष्ट्रवादी श्रमिक संगठन खडा किया जाय। वर्ष 1955 की 'तिलक जयन्ती' के दिन (23 जुलाई) को ऐसे कुछ कार्यकर्ता भोपाल मे एकत्र हुए और 'भारतीय मजदूर संघ' का गठन हुआ। देखते ही देखते भारतीय मजदूर संघ के रूपी पौधे ने एक वटवृक्ष का रूप ले लिया। आज इसकी 4400 यूनियनों 84 लाख सदस्य हैं, और सरकारी आंकडों के अनुसार वह देश का सबसे बडा श्रमिक संगठन है।

भारतीय मजदूर संघ के अतिरिक्त ठेंगडी जी ने भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण

मंच, सर्वपंथ समादर मंच, पर्यावरण मंच एवं सामाजिक समरसता मंच की भी स्थापना की थी, जिनकी जडे पूरी तरह स्वदेश में हैं। प्रायः इन सभी संगठनों का व्याप भी बढते जा रहा है। इनके अतिरिक्त वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सहकार भारती, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद. भारतीय विचार केंद्र एवं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के संस्थापक सदस्य थे। कम से कम 17 अन्य कामगार संगठनों के संरक्षक, 5 संस्थाओं के सहयोजित सदस्य तथा कम से कम 31 अन्य सुविख्यात संगठनों से वे जुडे थे। 12 वर्ष तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। आफ्रिका, एशिया, अमेरिका तथा युरोप के 29 देशोंकी यात्राएँ की। हिन्दी, अंग्रेजी तथा मराठी भाषाओं मे कम से कम 42 पुस्तकें, तथा 10 महत्त्वपूर्ण पुस्तकोंकी भूमिकाएँ लिखी। देश–विदेश में पठित एवं बहुचर्चित 7 शोध–पत्र लिखे। राष्ट्रीय श्रमनीती एवं भारतीय श्रमिकों का राष्ट्रीय माँग पत्र तैयार करने जैसे अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यो मे उनका योगदान अतुलनीय रहा। उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगोत्री से श्रीराम शीला पूजन के अभियान का श्रीगणेश किया था। कानपूर में श्रीराम कार–सेवा को लेकर सत्याग्रह, तथा महामना मालवीय जयन्ती समारोह प्रारम्भ करने एवं पुणे मे दीनदयाल मेमोरियल अस्पताल चलाने में उनका योगदान महत्त्वपूर्ण था। डा. हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार एवं सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट द्वारा डाक्ट्रेट की मानव उपाधि से भी उन्हे सम्मानित किया गया। चीन के सरकारी निमंत्रण पर 28 अप्रैल 1985 को बीजिंग रेडिओ ने उनके भाषण का प्रसारण भी किया।

ठेंगडी जी के चिन्तन के अनुसार देश के आधुनिकीकरण के लिए उसका पश्चिमीकरण आवश्यक नहीं। मार्क्सवाद के अर्थ पर आधारित वर्गभेद या वर्ग संघर्ष के हिंसामूलक सिद्धांत के खोखलेपन को उन्होंने पुरुषार्थ चतुष्टय की व्याख्या के माध्यम से उजागर किया। खेतिहर मजदुरों, रिक्शाचालकों, जूते गाँठने वालों एवं घरेलू कामकाजी लोगों, जैसे असंठित श्रमिक क्षेत्रों में लोकप्रिय संगठन खडे करने का श्रेय ठेंगडी जी को ही जाता है। समता नहीं, ममता के आधार पर उन्होंने देश में न्यूनतम और अधिकतम आय का अनुपात 1:19 रखने का सुझाव दिया था। ठेंगडी जी ने देश के आर्थिक विकास और विकास को सतत गतिशीलता प्रदान करने के लिये एक 'त्रिसूत्रीय' सिद्धांत 'राष्ट्र का औद्योगीकरण, उद्योगों का श्रमिकीकरण, श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण का प्रतिपादन भी किया था। उनके कार्यो के महत्त्व को ध्यान मे रखते हुए भारत सरकार ने उन्हे 'पद्माविभूषण' सम्मान से सम्मानित करने का प्रस्ताव किया था, जिसे उन्होंने यह कह कर सविनय अस्वीकार कर

दिया कि जब तक उनसे श्रेष्ठ डा. हेडगेवार एवं पूजनीय गुरूजी को भरतरत्न से सम्मानित नही किया जाता तबतक उनके द्वारा सम्मान स्वीकार करने का कोई अर्थ ही नहीं।

निःसन्देह, वह दिन दूर नही जब भारतीय इतिहास भारतीय दृष्टि से लिखा जाएगा तो भारत को परम वैभव सम्पन्न राष्ट्र बनाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन भारतमाता के चरणों पर अर्पित करने वालों की सूची में ठेंगडी जी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। प. पू. डा. हेडगेवार के पदचिन्हों के जीवनभर अनुयायी रहे दत्तोपंत ठेंगडी जी के विषय में भी यह सूक्ति उपयुक्त है।

ध्येय को ही देव कहकर हृदय मंदिर में बसाया ।

देवता के युगपदों पर अर्घ्य जीवन का चढाया।

दि. 3, 4 एवं 5 अप्रैल 2005 को रामलीला मैदान, दिल्ली पर संपन्न अखिल भारतीय त्रैवार्षिक अधिवेशन के अवसर पर महामंत्री का प्रतिवेदन

स्वर्ण जयंती 2004–05

(स्थापना 23–07–1955)

भारतीय मजदूर संघ
राम नरेश भवन, तिलक गली, चुना मण्डी,
पहाड गंज, नई दिल्ली 110 055.
दूरभाषः 2358 4212, 2356 2654 फैक्सः 2358 2648

दि. 3, 4 एवं 5 अप्रैल 2005 को रामलीला मैदान (नई दिल्ली) में संपन्न अखिल भारतीय त्रैवार्षिक अधिवेशन के अवसर पर महामंत्री का प्रतिवेदन —

आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष, चौदहवे अखिल भारतीय ऐतिहासिक त्रैवार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन समारोह के प्रमुख अतिथि तथा केंद्रीय श्रममंत्री आदरणीय श्री. के. चंद्रशेखर रावजी, भारतीय मजदूर संघ के मंचपर उपस्थित मान्यवर पदाधिकारी, अन्य केंद्रीय श्रम संघठनों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधिगण विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में कार्यरत महानुभाव, भारत के चौथे मशहूर शहर दिल्ली के नागरिक तथा भारतीय मजदूर संघ की 50वी जयंती मनाने के लिए भारी संख्या में भारत के कोने कोने से आए हुए सहृदय प्रतिनिधी, निरीक्षक तथा इस संगठन के प्रति आत्मीयता जताने आए हुए प्यारे बंधुओं और बहनों,

देश का सबसे बडा श्रमिकों का संगठन भारतीय मजदूर संघ हर्ष और उत्साहभरे वायुमंडल में आप सबकी उपस्थिती में स्वर्णजयंती का यह एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं चिरस्मरणीय समारोह मना रहा है। आप सभीका हृदय से स्वागत करते हुय मैं हर्ष उल्लास तथा गर्व का अनुभव कर रहा हुँ।

सारे श्रमिकों के दीपस्तंभ रहे भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक, महामंत्री स्व.श्रध्देय श्री. दत्तोपंत ठेंगडीजी चंद महिनो पहले ही हम से बिछुड गये है, अधिवेशन के इस सादगीपूर्ण और सुशोभित पंडाल को उन्हीं का नाम दिया गया है।

गरीब तथा कर्मचारी वर्ग के लिए निरंतर कार्य करने वाले एक और आधारस्तंभ स्व. श्री.राजकृष्ण भक्तजी भी हमसे चल बसे। इन्होंने श्रमिक क्षेत्र की, विशेषतः भारतीय मजदूर संघ की आजीवन सेवा की है। अतः इन्हें भावभीनी श्रध्दांजली अर्पित करना हमारा एक परम कर्तव्य है।

विगत 3 सालों में याने 2002 से लेकर 2005 तक जिन महान हस्तियों को हमने खो दिया उनका स्मरण करना और उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना उचित होगा। उन्हीं के संजोये सपनों को पूरा करने का हम प्रयत्न करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी स्मृतियाँ भी उनके कार्यकाल के समान ही हमें प्रेरित करती रहेंगी। दलित तथा श्रमिक वर्ग की समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण योगदान देनेवाले इन हस्तियों को भारतीय मजदूर संघ का महामंत्री होने के नाते श्रध्दांजली अर्पित करता हूँ।

श्रध्दांजली

ऐसे अनेक महानुभाव थे जो अपने कर्तृत्व की परछाइयाँ पीछे छोड गए है। भारतीय मजदूर संघ को अधिकतम सदस्यताप्राप्त तथा विस्तार प्राप्त अग्रणि श्रमसंगठन बनाने के समुचित प्रयासों में इनका श्रेष्ठत्व हमेशा प्रतीत होता है। स्थापना काल से ही भारतीय मजदूर संघ की ध्वजा थामकर श्रमिकों के लिए दृढता से बरसो तक परिश्रम करते हुए एक सच्चे कार्यकर्ता के नाते किसी पद या प्रतिष्ठा से परे रहकर एक बंधुभाव दिल में लेकर अंतिम क्षणतक निरपेक्ष सेवा करते रहे। ऐसे – कोमलसिंग परिहार, अंबिका प्रसाद, आर. एल.एन. राजू, हरीभाई हिरानी, शंभूसिंह खमेसरा, रासबिहारी मैत्र, परितोषदा पाठक, चरणसिंहजी, ऋषिराज शर्मा और अन्य।

जिन्होंने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य के लिए रा.स्व.संघ को अपनी निष्ठा अर्पित की। मातृभूमि की सेवामें सर्वस्व समर्पण किया। ऐहिक सुखोंको त्यागकर जो आजीवन प्रचारक रहे। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय स्व. रज्जूभय्याजी, मोरोपंत पिंगलेजी, चमनलाल जी, केशवराव गोरे जी, उत्तर पश्चिम क्षेत्र के ब्रम्हदेवजी, आंध्रप्रदेश के गणपतराव ब्रहमपूरकर, झारखंड के वसंतराव आगाशे तथा गुजरात के मधुकरराव भागवत, महाराष्ट्र शिवरायजी तेलंग, प्रल्हादजी अभ्यंकर, दामुअण्णा दाते व उत्तरक्षेत्र के क्षेत्रीय संघचालक जितेंद्रवीर गुप्ता, श्री शिव प्रसादजी, कृष्णदासजी, कृष्ण चन्द्रजी गांधी, विजयजी, भिमसेन चोपड़ा, नीलकण्ठ त्रिवेदी, रामभाऊ जी वेदी, गणेश देवजी शर्मा, सरोज मोंडल, काशीनाथ मिसकिन, कृष्णास्वामीजी, कौशल किशोरजी।

इनके साथ साथ

एन.ओ.बी.डब्ल्यू.के संस्थापक स्व. आबाजी पुराणिक, उपाध्यक्ष स्व. श्रीपादजी देशपांडे, डॉ. एम. जी. बोकरे, सर्वपंथ समादार मंच के नागपूर के अखिल भारतीय अध्यक्ष आदरणीय जाल. पी.जीमी जैसे कई महान हस्तियो को भी मैं भावभीनी श्रध्दांजलि अर्पित करता हूँ।

अ.भा.वि.परिषद के स्व. गौरीशंकर जी, वनवासी कल्याण आश्रम के भास्करराव कलंबी जिन्होंने केरल में रा. स्व.संघ का प्रचार व प्रसार करने में अपना सर्वस्व लुटा दिया था। श्री. मिश्रीलालजी तिवारी, वनवासी कल्याण आश्रम के महामंत्री, स्वाध्ययीयोंके गुरू पांडूरंगशास्त्री आठवले जी, महंत रामचरणदास महाराज, भाजपा के भूतपूर्व अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे जी, भारतके पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्माजी, पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी.नरसिंहरावजी, पूर्व उपराष्ट्रपती

कृष्णकांत और बी.डी. जत्ती, राज्यपाल सिकंदर बख्त, पूर्व गृहमंत्री श्री. शंकरराव चव्हाण, लोकसभा के पूर्व सभाध्यक्ष जी. एम.सी. बालयोगी, सीताराम केसरी, राजेश पायलट, आर. के. कुमारमंगलम्, माधवराव सिंदिया जी, जितेंद्रप्रसाद, बिजू पटनायक, वीरेंद्रकुमार संकलेचा, कृष्णलाल शर्मा, जे.एच.पटेल, जी.के. मुपनार, इंद्रजीत गुप्ता, चित्तबासू, जम्मू के सांसद विष्णुदत्तजी, आंध्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजयभास्कर रेड्डी आर्गनाईजर के संपादक तथा भाजपा नेता स्व. के. आर. मलकानी, पत्रकार मो. ग. तपस्वी, गुजरात के भाजपा नेता हिरेन पंड्या, नेता बलवंतराय मेहता, स्तम्भ पत्रकार बी.एन.लेले., दैनिक जागरण के नरेंद्र मोहन, रामभाऊ गोडबोले जी, भारतीय जनसंघ के भूतपूर्व अध्यक्ष उत्तमराव पाटील, तथा नागपूर के श्रीकंचीं जिचकर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीस श्री वी.एम. तारकुण्डे जैसे कई राजनैतिक नेता अपने कार्य व कर्तृत्वकी यादें पीछे छोडकर चल बसे हैं इन सबका स्मरण करना उचित होगा।

त्रिपुरा में आतंकवादियों का करारा विरोध करते हुए जिन 4 प्रचारकों ने अपनी जानें गवायीं तथा जो बेगुनाह लोग आतंगवादियों के हमलों में कशमीर, आसाम तथा ईशान्यपूर्व भागों में मारे गय उन सबकी आत्मा को शांति मिले ऐसी मै प्रार्थना करता हुँ।

- कारगील की लडाई में जो जवान शहीद हुए।
- भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, आतंकवादियो द्वारा किए गए हमलों में जिन वीरो ने अंततक झूझते हुए अपने प्राणोंकी बलि चढाई ।
- 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप के चपेट में जिनको अपने प्राणोंसे हाथ धोना पडा।
- गोधरा कांड में मारे गए निरपराध रामसेवक तथा इसके पश्चात गुजरात राज्य में दंगाफसाद के शिकार हुए सारे सामान्यजन।
- अमरनाथ यात्रा के दौरान दहशतवादियों की गोलियों का शिकार हुए सारे यात्रीगण।
- गुजरात के अक्षरधाम के स्वामीनारायण मंदिर में 24 सितंबर 2002 को आतंकवादियों ने जिन महिलाओं तथा बच्चों की निर्मम हत्या की।
- अमरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कार्यरत बेगुनाह लोग वैश्विक आतंकवाद का शिकार हुए।

- त्सुनामी लहरों की चपेट में आए हुए विश्व के समस्त दिवंगत आत्माओं आदि।
- इन सभी के साथ कई अपरिचित देशभक्त, प्रदेशों के नेता, निरपराध लोग इनको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते है।

इनके प्रति आदर जताने तथा भगवान से इनकी आत्माओं के लिए शांति माँगने हेतु अब हम सभी दो मिनट मौन खडे रहेंगे और प्रार्थना करेंगे।

ओमशांति शांति शांति :।

परिचय

लगभग 3 दशकों के बाद आज हम वही ऐतिहासिक शहर दिल्ली याने पुराने इंद्रप्रस्थ में चौदहवॉ अखिल भारतीय अधिवेशन के लिए एकत्र हुए है। भारतीय मजदूर संघ का पहला अ.भा. अधिवेशन 12 व 13 अगस्त 1967 को दिल्लीमें ही हुया था। उस उत्साहपूर्ण घटना ने हम सबको नई शक्ति व दिशा दी जो आज भी बरकरार है। इसका सबूत भारतभर में भारतीय मजदूर संघ एक अग्रणी संगठन बना है। विगत काल में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ घटी थी जिनका प्रत्यक्ष हमारे संगठन से संबंध बना था। हम सभी उन घटनाओंमे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल भी थे। भारत को आज मिला हुआ तूल दर्शाता है कि इन सारी घटनाओं का ब्यौरा हम जरूर लें।

भारत में अब तक जिन श्रमजीवी संगठनों ने कार्य किया था वे समाज को एक ताकत में बाँधे रखने में असफल रहे अतः समाज का विश्वास वे खो चुके थे। उनके ध्येय भी साफ नजर नही आते थे। उन सारी कमियों की पूर्तता भारतीय मजदूर संघ ने कर दी। सफेदपोश तथा श्रमजीवी लोगों में इसके प्रति विश्वास प्राप्त हुआ। धीरे धीरे सारे देशमें भा.म.संघ ने अधिकतम सदस्यता के साथ मान्यता प्राप्त होने का सम्मान पाया। यह केवल एक योगायोग है।

आदरणीय ठेंगडीजी – एक दीपस्तंभ

भारतीय मजदूर संघ को अपनी यह जो पहचान मिली है, नाम मिला है, उसका सारा श्रेय इसके संस्थापक महामंत्री स्वर्गीय श्रध्देय दत्तोपंत ठेंगडीजी को ही हम अर्पित करते है।

उनके अथक परिश्रम, निःस्वार्थ सेवा, समय समयपर किया हुआ मौलिक मार्गदर्शन इसका सार याने भारतीय मजदूर संघ की भारत के नभ में फहरती ध्वजा है। संगठन के विस्तार में ठेंगडीजी के साथ जिन आदर्श तथा अनुभवी कार्यकर्ताओंने अपना व्यक्तिगत जीवन भुलाकर कुशल साथ दिया पर आज वे हम में नही रहे उनमें अग्रणी है – संस्थापक अध्यक्ष स्व. बालासाहेब कांबले, दादा मुखर्जी, नरेशचंद्र गांगुली, मनहरभाई मेहता, तथा राजकृष्ण भगतजी, इनको भी हम आदरपूर्वक स्मरण करते है ।

श्रध्देय ठेंगडीजी के परमशिष्य रामनरेश सिंहजी उपाख्य बडे भैया का भी संगठन के इतिहास में अपना अमिट स्थान बना हुआ है।

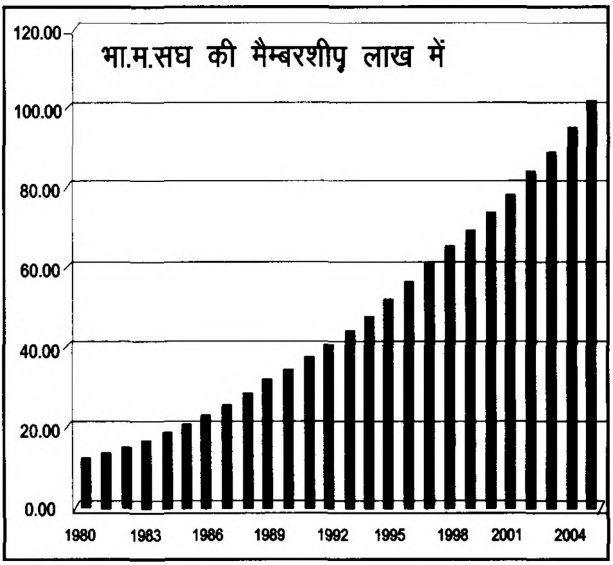

उनके ऐसे कई सह कार्यकर्ता थे जिन्होंने खून पसीना सिंचकर संगठन को मजबूत किया, उनके नाम की सूचि बहूत बडी है – स्व. जुमडेजी, बाळासाहेबसाठे, देशपांडेजी, जी. एस. गोखलेजी, मनोहर पाठक, सर सुखानंदनासिंहजी, रासबिहारी मैत्र, यह सूचि उदाहरण के तौरपर है पर सर्वसमावेशक नही है।

उनके कार्य व पवित्र स्मृती से संगठन को बल मिलता रहेगा। आज इस संगठन के हजारो कार्यकर्ता संगठन को और मजबूत बनाने के लिए तन मन धन से काम कर रहे हैं।

भारतीय मजदूर संघ के 50 वर्ष

50 वर्षा में भारतीय मजदूर संघ ने जो महत्वपूर्ण सफलता हासिल की उसमें से कुछ सुनहरे अंश का जिक्र करना आवश्यक है।

1. पहला दशक (1955 से 1965) –

दि. 23/7/1955 को भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। प्राथमिक अवस्था में कार्यकर्ताओ को अन्य मजदूर संगठनों का करारा विरोध सहना पडा, व्यंग्य सुनना पडा। दूसरी तरफ सरकार, अन्य संगठन तथा मजदूर का गुस्सा भी सह लेना पडा।

उन दिनों में कार्यकर्ताओंके पास न,कोई आर्थिक स्रोत था, ना ही मनुष्यबल। विरोधी ताकतों का मुकाबला करने के लिए न पर्याप्त कानूनी ज्ञान और न ही कोई सुविधायें थी।

भा.म.संघ के कार्यकर्ताओंकि तीव्र इच्छा, एकता कि ताकत, और इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जानेंको दुर्दम्य ध्येय ने ही उनको परिस्थिती के खिलाफ जुझने का बल दिया।

इसी दौरान 1962 में चीन ने तथा 1965 में पाकिस्तान ने भारतपर हमले बोल दिये थे। अपनी संपूर्ण शक्ति तथा निष्ठा कार्यकर्ताओंने भारतमाता के चरणोपर अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रीय मजदूर मोर्चा का गठन किया। भा.म.संघ ने ऐसे कई मुददे उठाना शुरू किय था, जिन मुददो के बारे में अन्य श्रम संगठनों ने विचार भी नही किया था। उदा. भारत सरकार ने महँगाई भत्ते के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रसारित किया था। भा.म.संघ ने इसका अध्ययन अभ्यास किया व कहा कि इसकी कार्यपध्दती में कई दोष व गलतियाँ है व इसमें आवश्यक सुधार लाने की ठोस माँग की।

शुरू में इंटक, हिंद मजदूर सभा तथा अन्य संगठनों ने इसका प्रखर विरोध किया पर बादमे सहमति दर्शाई। इस मुददे को प्रमुखता से रखते हूये 20 अगस्त 1963 को मुंबई बंद घोषित किया और सफल भी हुआ। सरकार ने लकडावाला समिती गठित की और उपभोक्ता मूल्य सुचकांक पर फेरविचार अभ्यास कर आवश्यक सुधार लाने के निर्देश दिए। इस तरह भा.म.संघ मजदूरों का विश्वास बटोरता रहा।

इसी दशक में भा.म.संघने 7 अखिल भारतीय महासंघो का गठन किया।

1. भारतीय वस्त्र उद्योग महासंघ.
2. अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ
3. भारतीय इंजिनियरिंग मजदूर संघ
4. भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ
5. भारतीय रेलवे मजदूर संघ
6. अखिल भारतीय शुगर मिल मजदूर संघ
7. अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ

भा.म.संघ ने "सब को बोनस" यह माँग की व प्रभावी मुद्दो संमेत स्पष्ट किया कि "बोनस यह विलंबित वेतन नही है।"

2. दूसरा दशक (1965 ते 1975) –

12 व 13 अगस्त 1967 को भा.म.संघ का पहला अधिवेशन संपन्न हुआ। उसके 7 महासंघ भी साथ थे। 541 पंजीकृत युनियन थी। तो सदस्य थे 2,45,902। भारतीय श्रम अन्वेषण केंद्र मुंबई तथा भारतीय चीनी (शक्कर) उद्योग अन्वेषण केंद्र लखनऊ ये दो युनिट कार्यरत हुए थे।

19 सितंबर 1968 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ भारतीय रेल्वे मजदूर संघ, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के मजदूरों को सस्पेंड किया गया, कोई टर्मिनेट हुए तो कई मजदूरों को जेल भैज दिया गया ।

अंग्रेजों की तरह भारत सरकार ने इस आंदोलन को कुचल डाला। विचारो–परांत भारतीय म.संघ ने जनवरी 1969 में यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन के पास ले जाने का प्रस्ताव रखा। स्वाभाविक ही अन्य केंद्रिय मजदूर संगठनों ने इस प्रस्ताव को पुष्टी दी।

आखिर 1969 में ही सरकारने जस्टीस गजेंद्र गडकर की अध्यक्षता में पहली नॅशनल कमिशन ऑन लेबर गठित की। भा.म.संघ के दत्तोपंत ठेंगडीजी, मनहरभाई मेहता, मिटकरी तथा गजाननराव गोखले इन सबने बारीकी से अभ्यास कर " लेबर पॉलिसी " नामक दो खंडो के पुस्तक में अपने विचार लिखकर कमिशन को प्रस्तुत किये।

22 सितंबर 1969 को भा.म. संघ के 50 हजार मजदूर व कर्मचारियों ने नॅशनल चार्टर

ऑफ डिमांडस् उस समय के राष्ट्रपती महामहिम श्री. व्ही.व्ही. गिरी के सामने रखा। इसमें केवल मजदूरो के हक व कर्तव्य नही बल्कि समूची मानवता का भी दृष्टिकोण था।

दिल्ली के पहले अधिवेशन के दौरान दिल्ली तथा उत्तरप्रदेश मे ही प्रदेश समिती बनाई गई। दूसरे कानपूर के अधिवेशन के बाद ही पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक मे प्रदेश समितियों का गठन हो सका। अब पंजीकृत युनियनों की संख्या हुई 899 और सदस्य संख्या बढकर 456103 हुई ।

घरेलु कामगारों की ना अपनी कोई पहचान थी, न सहारा, अतः मुंबई में 1971 में उनकी समस्याओं को सुलझाने हेतु घरेलु कामगार संघ की स्थापना हुई। 60 हजार से भी ज्यादा घरेलु कामगार बडी रॅली में शामिल हुए। वह समय था 22 व 23 मई 1972, भा.म. संघ का तीसरा अधिवेशन। अब पंजीकृत युनियन थी 1043 तो कार्यकर्ता सदस्योंकी तादात बढकर 5,67,465।

भारतीय रेल्वे मजदूर संघ ने रेल्वे हडताल की पर अहिंसात्मक पध्दती से। उनकी भूमिका थी कि हडताल के दरम्यान हम में से कोई भी राष्ट्रीय संपति को जरा भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगे।

अब भा.म.संघ के पास देशभर के मजदूर व कर्मचारी आकृष्ट होने लगे। नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ इन्शुरन्स वर्कर्स ने भी भा.म.संघ में शामिल होकर साथ निभाने का प्रण किया।

18 से 20 एप्रिल 1975 को अमृतसर में जो चौथा अधिवेशन हुआ तब तक 1313 युनियन व सदस्योंकी संख्या 8,39,423 हो गयी थी।

3. तिसरा दशक (1975 ते 1985) –

श्रीमती इंदिरा गांधीजी ने 26 जून 1975 को भारत मे आपातकाल घोषित किया। 4 जुलाई 1975 को रा. स्व. संघ पर पाबंदी तथा भाषणाधिकार व संगठित होने का अधिकार भी छिन लिया था । भारत के इतिहास में यह काला दिन माना जाता है । सुस्थापित अन्य मजदूर संगठनोंने चुपचाप स्विकृतीदी भा.म.संघ के कार्यकर्ताओंको गिरफतार किया गया, जेल में डाला गया, 100 से भी ज्यादा मिसा के तहत जेलमें बंद हुए।

लोकसंघर्ष समिती की स्थापना की गई। भा.म.संघ, सीटू, हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर किसान पंचायत ने मिलकर परिपत्रक जारी किया। आपातकाल के बावजूद भी भा. म.संघ की इस दशक में भारी वृध्दी हुई। जयपूर मे पाचवाँ अधिवेशन 21 से 23 अप्रिल 1978 को संपन्न हुआ। इसके पहले 6 से 26 जून 1977 को ठेंगडीजीने 63 वे अंतराराष्ट्रीय मजदूर अधिवेशन में भाग लिया। अब 1555 युनियन समेत सदस्यता 10 लाख से भी ज्यादा बढ गयी। 1980 में भा.म.संघ का रजत जयंती वर्ष था। भारतभर में रजत जयंति तथा विश्वकर्मा दिन मनाया गया। जिसमें अन्य मजदूर संगठनों के नेतोओं को भी आंमत्रित किया था।

7, 8 मार्च 1981 को भा.म.संघ का 6 वा अधिवेशन कोलकत्ता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की विशेषता थी कि संगठन का महिला विभाग स्थापन हुआ।

4 जून 1981 को 8 मजदूर संगठनों ने भा.म.सघ समेत सरकार की मजदूर विरोधी नीती के खिलाफ संगठित होकर लड़ने हेतु राष्ट्रीय अभियान समिति की स्थापना की।

9 से 11 जनवरी 1984 को हैदराबाद में 7 वा अधिवेशन हुआ था। भा.म.संघ ने घोषित किया कि अब हमें आर्थिक स्वतंत्रता का युध्द पाश्चात्य साम्राज्यवाद के खिलाफ लडना है। इसी साल संगठनद्वारा क म्युटरीकरण का भी विरोध किया गया। संगठन का उद्देश्य स्पष्ट था। मजदूरों के हितैषी युनियनों ने इसका स्वागत किया परंतु मजदूरों को विस्थापित करने वाली युनियनों ने इसका विरोध दर्शाया। अन्वेषण, सुरक्षा, अन्तरिक्ष का अभ्यास, समुद्रविज्ञान जैसे क्षेत्रों मे कम्प्युटर का उपयोग करने में भा.म.संघ को कोई आपत्ती नही थी। फिर भी इस मुद्दे पर सभी की एक गोलमेज परिषद बुलायी जाए और उसमें विचार, चर्चा मंथन करके संगणकीकरण का एक मापदंड तथा स्वरूप निश्चीत किया जाय ऐसी माँग की।

31 दिसंबर 1980 के सदस्या सत्यापन में भारतीय मजदूर संघ की सदस्यता 12,11355 हुई इसके मद्दे नजर भारत सरकारने 1984 में घोषित किया कि इंटक के बाद यह दुसरी सबसे बडी श्रम संगठन हो गई है।

इसके तुरंत बाद भा.म.संघ को अंतरराष्ट्रीय फोरम में प्रतिनिधीत्व करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1985 में अखिल चीन मजदूर युनियन फेडरेशन के निमंत्रण पर एक पांच

सदस्यी प्रतिनिधि मंडल चीन गया जिसमें सर्वश्री ठेंगडीजी, मनहरभाई मेहताजी, ओमप्रकाश अग्गीजी, श्री. वेणुगोपालजी, श्री.रासबिहारी मैत्र जी शामिल थे। बीजींग रेडीओपर चीन के मजदूरों को संदेश सुनाने का सौभाग्य श्री. ठेंगडीजी कों प्राप्त हुआ।

4. चौथा दशक (1985 ते 1995)

यह दशक चिरस्मरणीय रहा। 1986 में 10 केंद्रिय मजदूर संगठन इकठ्ठा हुए और सभी को मिलकर एक समान बैठक हुई। जिसमें राष्ट्रीय एकता, निःशस्त्रीकरण, वांशिक भेदभाव जैसे मुद्दोपर चर्चा की गई। विश्वशान्ति को ध्यान में रखते हुए बैठक पर भा.म. संघ का विशेष प्रभाव रहा। बंगलोर में 26 से 28 डिसेंबर 1987 को भा.म.संघ का 8 वाँ अधिवेशन संपन्न हुआ था। 1989 में रूस का विघटन हुआ और 1990 में नई आर्थिक नीति की धोषणा हुई और उदारतावाद, निजीकरण और खुले बाजार का पुरस्कार किया गया। नोव्हेंबर 1990 में डब्ल्यू एफ टी यू का विश्व अधिवेशन मॉस्को में हुआ। भा.म.संघ को इस अधिवेशन में विशेष आमंत्रित किया था। इस अधिवेशन में श्री. प्रभाकरजी घाटे ने दुनिया के सामने भा.म.संघ की गैर राजनितिक भूमिका स्पष्ट की।

इस अधिवेशन में सारे मजदूर संगठनों ने संकल्प किया कि इसके आगे कोई भी संगठन किसी भी सरकार, नियोक्ता(मालिक) या किसी गुट के दबाव में काम नही करेगा।

21 व 22 फरवरी 1991 में बडोदा (गुजरात) में 9वाँ अधिवेशन संपन्न हुआ। तथा 18 से 20 मार्च 1994 में धनबाद में 10वाँ अधिवेशन संपन्न हुआ था। एप्रिल 1994 में सर्वपंथ समादार मंच की स्थापना भी हुअी।

26–12–1996 को भारत सरकार ने भारतीय मजदूर संघ को 1989 की सदस्यता जांच के अधार पर प्रथम स्थान की धोषणा की। भारतीय मजदूर संघ की सत्यापित सदस्यता 31 लाख 17 हजार 324 हुई।

5. पाँचवा दशक – (1995 ते 2005)

दिनोंदिन बढते हुये प्रदुषण को तथा उसके पर्यावरण पर होनेवाले दुष्परिणामोंका गंभीरता से विचार कर भा.म.संघ ने 1995 में पर्यावरण मंच की स्थापना की। प्रकृति की हम रक्षा करेंगे तथा उसे नष्ट होने से बचाएँगे ऐसा प्रचार करने का प्रण संगठन ने किया।

28 से 30 अक्तूबर 1996 को भोपाल में 11वाँ अधिवेशन संपन्न हुआ तथा 12वाँ अधिवेशन 15 से 17 फरवरी के दौरान नागपूर में हुआ यह तो आपको ज्ञात होगा।

सारे दिल्लीवासियों का ध्यान आकर्षित हुआ 16 अप्रैल 2001 को करीब 2 लाख कर्मचारीयोंकी रॅली दिल्ली के रास्तोपर से गुजरी थी। इस रॅली की अंतमें रामलीला मैदानपर सभा हुई। मुल उद्देश्य था कि भारत सरकार को विश्व व्यापार संगठन से होनेवाले गंभीर खतरोंका परिचय कराया जाए। डब्ल्यू टी ओ मोडो,तोडो या छोडो की घोषणा दिल्ली के आकाश तक गूँज उठी।

जून 2001 में द्वितीय श्रम आयोग में भा.म.संघ ने हिस्सा लिया। इसके चेअरमन रविंद्र वर्मा थे, वामपंथी मजदूर संगठनो ने इस आयोग का बहिष्कार किया।

23 से 25 फरवरी 2002 को तिरूअनंतपुरम में संगठन का 13वाँ अधिवेशन संपन्न हुआ। इसी साल 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का सप्ताह जनचेतना अभियान मनाकर भारतभर के कर्मचारी, किसान तथा सामान्य जनोंको जागृत किया कि प्रगतिशिल देशों का शोषण विश्व व्यापार संगठन की आड में विकसित राष्ट्र कर रहे है।

विश्व व्यापार संगठन ने 10 से 14 सितंबर के दौरान कॅनकून मेक्सिको में अधिकारीयों की सभा का आयोजन किया। मगर भा.म. संघ ने इसके पहलेही 23 जुलाई से 9 अगस्त के मध्य जनजागरण अभियान तालुका स्तरपर सफलतापूर्वक संपन्न किया था । दिल्ली के रामलीला मैदान पर दि. 2 सितम्बर 2003 को महाधरना का आयोजन किया जिसमें भारतीय किसान संघ व स्वदेशी जागरण मंच भी शामिल थे।

वैश्विक परिदृश्य

औद्योगिक क्रांति के बाद का कालखण्ड, भारत पर विदेशी उपनिवेश, विश्व युद्ध के दुष्परिणाम, महाशक्ति बनने की होड़ एवं इस हेतु हथियारों के व्यापार की अंधी दौड़, सोवियत संघ का विघटन, पूरे विश्व पर अमेरिका द्वारा स्वघोषित नीतियों का लादना, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक एवं विश्व व्यापार संगठन द्वारा आर्थिक उपनिवेशवाद के शिकंजे में विकासशील देशों को कसना, उपभोक्ता वर्चस्व बढ़ाकर बाजार हस्तक्षेप को बढ़ाना, तकनीकि ज्ञान का बोझ एवं पर्यावरण विनाश ये सभी ऐसे प्रमुख घटनाक्रम हैं जिनकी पृष्ठभूमि में ही वैश्विक परिदृष्य का मूल्यांकन उचित होगा।

आज विश्व मुख्यतः विकसित एवं विकासशील देशों के समूह में विभाजित है। विकसित देश आर्थिक वर्चश्व बनाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा को विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन का निर्माण विकसित देशों द्वारा किया गया। इनके माध्यम से विकासशील देशों के ऊपर दबाव डालकर उन्हें बाजार केन्द्रीय अर्थव्यवस्था अपनाने को बाध्य किया जाता है। इतना ही नहीं सामाजिक और सांस्कृति क्षेत्रों में व्यापार के अनैतिक मापदंडों के द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ाया गया है।

आर्थिक दृष्टि से दुर्बल तथा विकासशील देशों का सार्वभौमत्व नष्ट करने और खुद की आर्थिक सत्ता उन देशो पर स्थापित करने हेतु जी –7 देश विशेषतः अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से प्रयत्न कर रही है। अर्जेटिना पर गुजरे आर्थिक संकट से सभी देश सजग हो गये। ऐसी स्थिति में भा.म. संघ के दावे व सोच खरी उतरी है।

हमारे गत अधिवेशन से आतंकवाद का भारी बोलबाला हो रहा है। लाखों निर्दोष नागरिक इससे हताहत हुए हैं। अमेरिका भी जागृतिक व्यापार केंद्र व पेंटागान पर हुए हमलों से कतर गई है। उसकी ताकत पर सवाल उठ रहे थे। अंततः अमेरिका ने निराशा वश ओसामा बिन लादेन को पकड़ने हेतु अफगानिस्तान पर सैनिकी आक्रमण किया। तालिबान सरकार को हटाकर कामचलाऊ सरकार की स्थापना की।।

मित्रो आपको ज्ञात है भारतका एक हवाई जहाज का काठमांडू से अपहरण किया गया था।अपहरणकर्ताओंको तालिबानी सरकार ने आश्रय दिया था। अमरिका पर तथा हमारी लोकसभा पर हुए हमले इन्हीं आतंकवादियों ने किये थे। इस्लामिक आतंकवाद से दुनिया भर के सारे देश ग्रस्त है। मित्रो इन्होनें तब तक हमारा साथ नही दिया जबतक वे खुद इसका शिकार नही हुऐ थे। आज सारा विश्व इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो गया है। दुख की बात यह है कि इस संवेदनशील विषय पर एकमत हमारे देश में नहीं दिखाई देता । अपने अपने वोट बैंक कायम रखने के लिए इस विषय को नजरअंदाज किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप आतंकवाद पनप रहा है। उग्रवाद के खिलाफ जनसामान्य की मानसिकता बनाना हमारा दायित्व है।

विश्वभर में खेती उत्पादन का मूल्य गिर रहा है। विश्व व्यापार में मंदी के आसार हैं। अमरिका की कूटनीती यह है कि एक तरफ अपने किसानों को खेती एवं उद्योगों के लिए अनुदान देरहा है तथा दूसरे देश ऐसा कोई अनुदान अपने किसानों को न दे इसलिए सतर्क भी है। वैश्विकरण के नामपर पश्चिमी अमीर देश नीचे दर्जे का माल एशियाई और अफ्रिकी

देशों में भेज रहे है। किंतु उन देशों से आयात होने वाले माल पर प्रतिबंध लगा रहे है।

विश्व के देशों का एक ओर ध्रुवीकरण होने के कारण तटस्थ देशों का गुट खंडित हुआ है। अमरिका के वर्चस्व से दूर रहने के लिए तथा अपने सामूहिक हितोंका संरक्षण व संतुलन करने के लिए विश्वके तीसरे दर्जे के देशों को एकजुट होना अत्यंत आवश्यक है। भारत इन देशों का नेतृत्व करने में सक्षम है। अमीर देशों के बनाये चक्रव्यूह में हम न फंसे इसकी सावधानी बरतने की अत्यंत आवश्कता है।

डब्लू.टी.ओ., आय.एम.एफ, और वर्ल्ड बैंक इन तीन संस्थाओं द्वारा अधिकांश देशों में स्थापित आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप गरीबों का शोषण व अमीरों का पोषण होता दिखता है। ये नीती अधिकांश लोगों को विनाश की राहपर ले जा रही है। संपत्ति का असंतुलित वितरण होने से अमीर और गरीबोंके बीच दूरी और बढ रही है। अंततः नौकरी के अनुकूल मौके घट रहे है और बेरोजगारी बढ़ रही है।

डब्लू.टी.ओ. के अंतर्गत मंत्रियों की दो स्तर बैठके हो गई। विकसित और विकासशील देशोंकी दूरी बढेगी ऐसा प्रतीत होता था। परंतु लंदन में हुए सम्मेलन में विकासशील देशों के मंत्रीयों ने जो रवैया अपनाया इससे अनुमान होता है कि डब्लू.टी.ओ. की ताकत घटने लगी है। विगत पचास सालो मे यह एक नया अनुभव है।

राष्ट्रीय परिदृश्य

पिछले पचास सालो में इस प्रायद्वीप मे जनतंत्र मजबूत हुआ। भारत की जनता ने चीन तथा पाकिस्तानी आक्रमण का अनुभव किया। उसके बाद दो साल तक तानाशाही जैसा आपत्काल भी देखा। आय विषमता, बेरोजगारी, बढती हुई आबादी, भ्रष्टाचार, विद्रोह, युद्ध व आतंकवाद इसका भी भारतीयोंको अनुभव मिला। इन विषम परिस्थितियों को झेलने के बावजूद भी भारतीय जनता का हौसला नही टूटा है। एक पक्षीय सरकारी कामकाज की अग्निपरीक्षा भी सहजता से दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के 40 साल बाद अब संयुक्त सरकार का अनुभव मिल रहा है। हर एक पक्ष अपने खुद के कार्यक्रम पर जोर देता है। साझा सरकार में रहने के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रमपर वह समाधान मानता है। इसी कारण हर राजकिय पक्ष नवीन आर्थिक निती के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक के तैयार आर्थिक कार्यक्रम को मानती है।

दि. 3/7/91 को नरसिंहरावने प्रथमतः नई आर्थिक नीती व नई औद्योगिक नीती का निर्धारण किया। इसके अंतर्गत विदेशी निवेश के लिए भारतीय व्यापार के सारे दरवाजे मुक्त करने का /खोल देने का प्रस्ताव भी था। ऐसी सोच होने लगी कि हमारी प्रगति में कार्यालयी बिलंब एक बड़ी रुकावट बना है। इससे निपटने के लिए लाएसन्स राज हटाया गया और रुपये का अवमूल्यन किया गया तो हमारा निर्यात बढ़ सकती है और विदेशी कर्ज चुकाया जा सकता है अबतक ये रकम 100 बिलीयन डालर से भी ज्यादा थी।

आर्थिक परिदृश्य

विश्व आर्थिक स्तरपर यूरो स्थिर व संतुलित हुआ और अमेरिकन डालर को उसने पीछे डाल दिया।

विश्व व्यापार संगठन की सिएटल में जो मंत्रियोंकी बैठक हुई उसमें संकेत मिले कि विकासशील देश एक हो गए है, अमेरिका का बढता प्रभाव तथा विकासशील देशों के लिए बनाये गये दुर्भाग्यपूर्ण प्लॉन इसलिए उनको एकत्र लाने के लिए था। हाल ही में दोहा तथा कानकून में अमेरिका के कहनेपर बैठक की कालावधि एक दिन के लिए और बढाई थी। वर्ष के अंतमें हाँगकाँग मे होनवाली बैठक में क्या दृश्य खड़ा होनेवाला है यह स्पष्ट रूपसे दिखाई देता है ।

बहुत समय तक पिछड़ी अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होने लगी है। पहले छः महीने में ही प्रमुख क्षेत्रों मे अनुकूल संकेत मिले है। इस प्रगति को कायम रखकर समतल व न्यायपूर्ण रखना आवश्यक है। मूलभूत सुविधाएँ जैसे सड़क, संचार, आवास, बिजली, ग्रामीण विकास इनमें सरकार को खुदकी स्पष्ट भूमिका निभानी होगी। साथ में मानव संसाधन का भी पूर्ण उपयोग करना भी जरूरी है।

एल पी जी का धोरण सर्वथा हमारे लिए घातक उद्देश्यों से भरा हुआ है। जैसे कि उदारीकरण का अर्थ था उद्योगों को सरकारी नियंत्रण से दूर रखना। किंतु निजीकरण व वैश्विकरण के उद्देश्यों को गंभीर रूपसे विरोध करना जरूरी है। निजीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेशों का एकाधिकार निजी एकाधिकार में बदल जाना बहुत खतरनाक है। जैसे आय पी सी एल को रिलायन्स ग्रुपने कार्यभर सँभाल लिया। लाभ कमाने वाले युनिटोंका तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का निजीकरण नहीं करना चाहिए। देश हित को महत्व देते हुए इस नीतीपर तुरंत विचार करना जरूरी है।

वैश्विकरण का उद्देश्य भारत के लिए बहुत जोखिमपूर्ण है। इसके तहत सारे क्षेत्र विदेशी निवेश के लिए खोल दिए जायँगे। असमान आर्थिक परिस्थिती के कारण उद्योगों का स्वामित्व व नियंत्रण विदेशियों के हाथ में जानेकी अत्यंत संभावना है। एवं हम आर्थिक गुलामी की ओर घसीटे जाएँगे।

वास्तव में हमारे यहाँ कुशल निवेशक और उत्तम संचालक हैं। डब्ल्यू टी ओ के अनुसार सारे आयातकर व व्यापार प्रतिबंध को उठाना जरूरी है। इसका समूचे मजदूरोंद्वारा ही कडा विरोध होना आवश्यक है। स्थिति को देखकर भारतीय मजदूर संघ ने इसके नेतृत्व का जिम्मा उठाया है। डब्ल्यू टी ओ की नितियाँ एक और दुष्परिणाम दिखता है कि अमीर तथा गरीबों के बीच की दूरी और बढ रही है। वस्तुतः सरकारके पास गोदामों में अनाज का बफर स्टाक होने के बावजूद भुखमरी की घटनाएँ अक्सर होती है। अब जरूरी है कि आर्थिक सुधारों का लाभ समाज के अंतिम घटक तक जल्द ही पहुँचना चाहिए ।

व्यापार और टॅरिफ

यह संयोग मात्र नहीं है कि ब्रेटन वुड भाइयों तथा लीग ऑफ नेशंस एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृष्य पर उभरे विश्व के मानचित्र पर साम्राज्यों का प्रभुत्व तेजी से कम हो रहा था लेकिन विश्व पर अभी भी विकसित तथा धनी राष्ट्रों का कडा नियंत्रण था। एक तरफ तो गरीब राष्ट्रों को प्रगति एवं समृद्धि के स्वप्न दिखा कर लुभाया जा रहा था वहीं उन स्वप्नों को पूरा करने के लिए उन्हें ऋण लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। धनी राष्ट्रो ने इसमें सीधी सहभागिता के लिए बैंको तथा निधीयों के माध्यम से यह कार्य किया। नव स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभुता को समाप्त करने के लिए पश्चिम ने विश्व बैंक, एशियन बैंक तथा आई एम एफ जैसे माध्यम अपनाए। एक त्रिपक्षीय समन्वय संकाय के रुप में आई एल ओ को इस तरह बनाया गया कि पश्चिम का प्रभुत्व बना रहे।

डब्ल्यू टी ओ के ४ वें दौर के बाद शक्तिशाली व्यापार तंत्र उभर कर आया है। विश्व व्यापार बहुत बढा है और उत्पादन भी कई गुणा बढा है। यहाँ भी व्यापार शर्ते जी–7/8 के पक्ष में तैयार की गई है। विकसित देशों से निर्यात प्राथमिक वस्तुओं, कच्चा माल तथा खनिजों का है, यह कींमत और गुणवत्ता दोनों दृष्टियों से लचीला है वहीं तैयार माल और प्रौद्योगिक अंतरण लचीला नहीं है। निरंतर शोध और विकास के कारण प्रौद्योगिक लगभग हर दूसरे वर्ष बदल जाती है। विकासशील तथा गरीब देशों के लिए इन परिवर्तनों के साथ चलना कठिन है। यह एक अंधी दौड है।

पचास के दशक में भारत के बडे अर्थशास्त्री तथा दक्षिण सहयोग के सचिव डॉ. मनमोहन सिंह जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है, ने दक्षिण – दक्षिण सहयोग की कल्पना की थी। लेकिन भारत द्वारा पहल न होने से यह संभव नहीं हो सका। सभी भारतीयों की आशा तब जगी जब श्री मारन के नेतृत्व में विकासशील देशों ने भारतीयों के लिए रियायतों की मांग की जिससे डब्ल्यू टी ओ की 2001 की मंत्री स्तरीय बैठक गतिरोध के कारण समाप्त हो गई।

यह अधूरा एजेंडा कॉनकून (मेक्सिको) 2003 में आगे बढाया गया जहां भारत के वाणिज्य मंत्री श्री जेतली विश्व नेता के रुप में उभरे। डब्ल्यू टी ओ में जी 120 के रुप में दक्षिण सहयोग की भावना फिर उभरी। दिसंबर 2005 में हांगकांग मे होने वाली अगली बैठक में अंतिम मुकाबले के रुप में तीसरा दौर होगा क्योंकि विरोधी गुटो में मतभेद अधिक गहरे हो गए हैं।

वर्ष 2000 का दक्षिण – पूर्व एशियायी देशों का संकट दर्शाता है कि शक्तिशाली धनवान मौजूदा नीतियों के अधीन किस प्रकार आसानी से दखलअंदाजी कर सकते हैं। विश्व मंदी ने व्यापार तथा वाणिज्य को प्रभावित किया है। भारत ने 4.4: की विकास दर बनाए रखी है। विश्व की विकास दस 2.5: के आसपास रहीं। अब भारत 6.5: की विकास दर की तरफ अग्रेसर है तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना में 7 की वृद्धी दर का अनुमान है।

विदेशी कर्ज

विदेशी कर्ज, जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा था, चुकाने के वायदे पर अर्थव्यवस्था को खोला गया यह लगबग 82 बिलीयन अमरीकी डालर था। अब यह तर्क किया जा रहा है कि विदेशी कर्ज आज भी लगभग उतना होने के बावजूद भी सकल धरेलू उत्पादन लगभग दो गुणा होने से यह इतना खतरनाक नहीं है। यह प्रचार भी किया जा रहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कर्ज से अधिक है इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन कर्ज तो है जो अब बढ कर 102 विलियन अमरीकी डालर हो गया है।

यह तर्क किया जा रहा है कि चूँकि भारतीय करेंसी अमरीकी डालर की तुलना में मजबूत हुई है। इसलिए विदेशी कर्ज स्वतः कम हो रहा है। लेकिन यदि बढते व्यापार घाटे को कम न किया गया तो अंततः खतरा पहले की तरह बना रहेगा।

घाटे के वित्तपोषण की पद्धति अभी भी जारी है और राज्यों के ओवर ड्राफट ने कुछ राज्यों को दिवालियेपन की स्थिति तक पहुंचा दिया है। भारतीयों द्वारा निर्मित वार्षिक राजस्व का बड़ा भाग कर्जशोधन में चला जाता है इसके कारण केन्द्र तथा राज्य सरकारों के पास विकास तथा पूंजी निवेश, सामाजिक सुरक्षा और गरीबोंकी भलाई के लिए बजट में कुछ नहीं बचता है।

ऐसे कई मामलें हैं जहां विकास का पहिया जाम हो जाता है। प्रत्येक राष्ट्रभक्त को यदि भविष्य का रास्ता बनाने का अवसर मिले तो वह तमाम अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों, सैनिक खतरों से भी सामना करने को तैयार होगा। निरंतर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सख्ती से खात्मा करना होगा।

विदेश व्यापार

भारत ने इस आशा के साथ अपने द्वार विदेशी आर्थिक शक्तियों के लिए खोले थे कि उत्पादन बढेगा, निर्यात वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। वर्ष 1991 से अब तक भारत का विदेश व्यापार कभी भी अधिशेष में नहीं रहा है। निर्यात में वृध्दि के साथ साथ आयात भी बढा है इससे घाटा निरंतर कायम है और बढ रहा है। सरल व्यापार संतुलन की खोज जारी है, भारत के सकल धरेलू उत्पादन चीन की तुलना में लगभग आधा है। चीन भारी व्यापार अधिशेष अर्जित कर रहा है। आत्मनिर्भरता के लिए आयात के स्वदेशी विकल्पों की खोज यथा आयात तथा वैकल्पिक उर्जा संसाधन जुटाने के लिए तुरंत नीतियों की तरफ ध्यान देने की जरुरत है।

पुर्ण परिवर्तनीयता

विश्व के नेता विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के माध्यम से दवाब डाल रहे हैं पूर्ण परिर्तनीयता प्रदान की जाए। दक्षिण/पूर्व एशियायी संकट इसके खतरें दर्शाता है। अविकसित देश अमरीका के साथ बँध जाऐंगे।

औद्योगिक परिदृष्य

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के धरेलू बाजार मे प्रवेश से लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग खतरे में है। धरेलू उद्यमियों तथा स्थानीय रोजगार देने वालों की कमी हुई है इससे अपराध दर, पलायन तथा टाला जा सकने वाला शहरीकरण बढा है।

एक और प्रस्ताव के जरिए सीधे विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हटाने की बात की जा रही है ऐसा होने से पूरा धरेलू उद्योग खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए संगठित श्रमिक आंदोलन को दुधारी तलवार का सामना करना है। एक तरफ उन्हें नई चुनौतियों तथा प्रतिस्पर्धाओं के खिलाफ खड़े रह कर अपनी पहचान बनाए रखनी है। वहीं दूसरी ओर वी आर एस या सी आर एस के माध्यम से रोजगार सुरक्षा का हनन जारी है।

इस पृष्ठभूमि में एक सजग राष्ट्रवादी संगठन के रूप में हमारे सामने भारी चुनौती है। हमें अपने सहकर्मियों को शिक्षित करके निजीकरण के प्रयासों के विरुध्द लडाई करनी है। विदेशी तथा निजी बैंको की कमियों को जग जाहिर करने के लिए हमें जागरुकता अभियान चलाना है। हमें सेमिनार, चर्चासत्र तथा सम्मेलन इत्यादि आयोजित करके तथा उनमें विशेषज्ञों को बुला कर मिडिया का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करना होगा।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मौजूदा आवश्यकताओं के अनुसार हमें अपना चिंतन बदलना होगा। यदि हम बदलेंगे नहीं तो विलुप्त हो जाएंगे। बदलाव का अर्थ यह नहीं कि अपने मूल्यों और आदर्शों का परित्याग। हमें पारंपरिक तथा आधुनिक कार्य पध्दतियो को मिला कर उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना होगा। इसलिए संगठित तथा असंगठित मजदूर आंदोलन के प्रतिनिधि होने के नाते हमें आदर्श स्थापित करने होंगे।

श्रमिक परिदृष्य

आर्थिक परिदृष्य के अंतर्गत बताए गए कारणों से देश का श्रमिक आंदोलन विकट स्थिति का सामना कर रहा है। डब्ल्यू टी ओ द्वारा प्रस्तुत चुनौतियाँ ही कम नहीं थी, सरकार भी देश के श्रमिकोंके प्रति गलत धारणाओं का प्रावधान कर रही है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम तथा औद्योगिक संपदा अधिकार सहित अन्य श्रमिक कानूनों में प्रस्तावित संशोधन यह सूचित करते हैं कि संगठित तथा असंगठित क्षेत्र का भविष्य अच्छा नहीं है। डब्ल्यू टी ओ की शर्तो के अनुसार सरकार हायर एंड फायर नीति बना रहीं है तथा विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करने की सोच रहीं है। बालको तथा माडर्न फूडस इसके पहले शिकार रहे जब सरकार ने इनसे पल्ला झाड दिया। पिछले पांच दशकों के दौरान ट्रेड यूनियन आंदोलन में भारी परिवर्तन हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ नामक नई

ट्रेड युनियन शक्ति उभरी है। शुरू में भारतीय मजदूर संघ को कम्यूनिस्ट विरोधी, क्रांतिकारी विरोधी तथा राइट प्रतिक्रियावादी दल बताया गया। धीरे धीरे यह सभी विशेषण खत्म हो गए तथा भारतीय मजदूर संघ का सही रूप में सामने आया। पिछले पांच दशकों के दौरान भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक तथा वर्ग की निस्वार्थ सेवा करने वाली ट्रेड युनियन के रुप में उभरा है। इसमें मात्रा तथा गुणवत्ता दोनों तरह से वृध्दि हुई है। भा.म.संघ के नेतृत्व में राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने श्रमिक वर्ग में जागरूकता उत्पन्न की है तथा भारत के श्रमिकों ने उन विकल्पों को चुना है जो श्रमिक विरोधियों तथा देश विरोधियों के विरोध में उपस्थित थे। जो यह नहीं समझते कि उद्योग की प्रगति में ही श्रमिकों की प्रगति होती है तथा औद्योगिक देशों की संपन्नता उद्योग तथा श्रमिकों के कारण है वे अपनी गलतियों से अकेले हो गए है। भा.म.संघ, माकर्सवाद या समाजवाद में विश्वास नहीं रखता फिर भी यह भारत की सबसे बडी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन है। यह स्वर्ण जयंती वर्ष दर्शाता है कि देश तथा समाज की सेवा मे लगी एक गैर राजनीतिक तथा वास्तविक ट्रेड यूनियन बनाने के समय सिध्द प्रयास सफल हुए है।

श्रमिक क्षेत्र पर एल पी जी का प्रभाव (उदारी करण, निजीकरण तथा सार्वभौमिकरण)

उदारीकरण का अर्थ है कि उत्पादन तथा समाज को सेवा प्रदान करने के कार्य जो आज तक सरकार द्वारा किए जा रहे थे वे निजी क्षेत्र द्वारा किए जाएंगे। सरकारीकरण की क्रिया भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा क्षेत्र तथा वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ प्रारंभ हुई। अब इसके विपरीत निजीकरण की तरफ सोचा तथा किया जा रहा है।

सार्वभौमिकरण का अर्थ है। 1. प्रौद्योगिकी अंतरण 2. पूंजी अंतरण 3. कहीं भी निवेश की आजादी 4. श्रमिकों के आवागमन की आजादी।

लेकिन वास्तव में हमारा आयात हमारे निर्यात से अधिक होता है तथा विकसित देशों ने भारतीय माल के लिए अपने बाजार नहीं खोले हैं। पिछले पांच दशकों के दौरान हमने देखा है कि जब भी पूंजीवाद बढा है तब तालाबंदी के कारण श्रम घाटे का नुकसान बढ़ा है। मुक्त पूंजी निवेश के कारण पूंजी का आगमन बढ़ा है। लेकिन इसके साथ उत्पादन की विदेशी पध्दतियाँ भी आ रही है। भारी मात्रा में मशीनीकरण तथा स्वचालन हुआ है। इसके कारण रोजगार के अवसर निरंतर कम हो रहे हैं। श्रमिक भी प्रौद्यागिकी के बढते स्तर को

अपनाने में सहजता अनुभव नही करते हैं, उनकी रोजगार योग्यता पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। कोरिया में 83 प्रतिशत रोजगार योग्यता है जब की भारत में यह केवल 13प्रतिशत है।

बहुचर्चित राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उपयोग बेरोजगारों को रोजगार योग्य बनाने के लिए नहीं किया जा रहा है। इस निधि का उपयोग वी आर एस के भुगतानों के लिए किया जा रहा है। इस तरह एल पी जी का सर्वाधिक असर श्रमिकों पर हुआ है। इन नीतियों का असर बेरोजगारी के रूप में दिखाई देने लगा है।

ढांचागत परिवर्तनों के कारण बीमार हुए उद्योग सभी के लिए चिंता का विषय है। इन लघु उद्योंगो में काम करनेवाले श्रमिक असहाय हो गए हैं। उन्हें न्यूनतम वेतन, साप्ताहिक अवकाश, कानूनन भुगतान, भविष्य निधि तथा स्वास्थ्य सेवाओं जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। अब बीमार इकाइयों से मजदूर अनिश्चितता तथा अप्रासंगिक होने के कगार पर है। यह क्षेत्र जो संगठित श्रमिकों के 75प्रतिशत हिस्से को रोजगार देता है डूबने के कगार पर है। केन्द्र की यू पी ए सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इस क्षेत्र को सहयोग की बात की गई है।

लेकिन टेरिफ कम करने तथा लघु उद्योग से स्पर्धा कर रहे आयातकों को लुभाने के लिए सरकार की सख्त तथा बेमानी नीतियाँ उद्योग को बर्बाद कर रही है। इसके लिए एकीकृत नीति के पुनः निर्धारण की आवश्यकता है। कुछ लघु उद्योग केवल कर राहत के लिए चल रहे है। इन्हें किसी प्रकार की सहायता करने के बजाए इन पर रोक लगनी चाहिए। कर चोरी करनेवाले उद्योगों को सीधा करने की आवश्यकता है।

भा.म.संघ वर्ष 1993 से यह मांग कर रहा है कि व्यापक नीतियाँ तथा प्राथमिकताएं तय करने और आवश्यक अनुवर्ती कारवाई करने के लिए आर्थिक बातों पर एक गोल मेज सम्मेलन होना चाहिए।जब तक एक प्रौद्योगिकी नीति तैयार नहीं की जाती तब तक इन समस्याओं का समाधान तथा भावी कार्य योजना का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकेगा।

इसके लिए भा.म.संघ विभिन्न मंचों पर अपने विचार रखता रहा है। इस संबंध में भा. म.संघ ने अनेक बार सरकार को लिखाहै। 23/6/04 को भा.म.संघ तथा अन्य ट्रेड युनियनों की एक बैठक भारत के प्रधानमंत्रीजी के साथ हुई थी। इस बैठक में भी यह मुद्दा सामने रखा गया। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के कारण यू पीए के साझा न्यूनतम कार्यक्रम से यह आशा बंधी है कि औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में नया अध्याय खुलेगा। भा.म.संघ द्वारा

पिछले तीन वर्षोंके निरंतर दबाव के कारण कुछ परिवर्तन हुए हैं जैसे :–

1. वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है की नीतियाँ घोषित करने से पहले ट्रेड यूनियनों से चर्चा की जाएगी।
2. साझा न्यूनतम कार्यक्रम आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने का आश्वासन।
3. व्यापक रोजगार कानून बनाने का आश्वासन।

बेरोजगारी, भारत के अस्तित्व को खतरा :

श्रमिको की संख्या 2प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ रही है। जब कि रोजगार के अवसर अनौपचारिक क्षेत्रमें 1प्रतिशत तथा संगठित क्षेत्र में केवल 0.93प्रतिशत की दर से बढ रहे हैं। हर दो वर्ष के बाद प्रौद्योगिकी अधिक रोजगार घटानेवाला होता जा रहा है। भारतीय उद्योग भी आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की संख्या घटाता रहा है। सरकारने वर्ष 1988 से नौकरियाँ बंद कर रखी है। सरकारी / अर्ध सरकारी तथा संगठित निजी क्षेत्र में किसी प्रकार की नौकरियाँ नहीं है। उत्पादन क्षेत्रमें गिरावट हुई है तथा यह क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पादन का 16प्रतिशत है।

भारत में जो बीपीओ बिजनेस आ रहा है, उसमें कमाई की ढेरों संभावनाएं हैं। मौजूदा विदेशी व्यापार की व्यवस्था भारत को मजबूर करेगा कि वह आर्थिक लागत, सामाजिक लागत और व्यापार प्रतिबंधों की कीमत का भुगतान करे। इसलिए भारत को लेन–देन की शर्तें सावधानी से तय करनी होगी। बढ़त की चाहत के साथ चीन ने बहुत मदद पहुंचाई है। आज चीन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लाभ के व्यापार के साथ खुद को स्थापित कर चुका है, लेकिन भारत को अभी यह स्थिति प्राप्त करनी है। सकल घरेलू उत्पादन में निर्माण के क्षेत्र का योगदान भारत में सिर्फ 16 फीसदी है। चीन के मुकाबले लगभग यह आधा है। इसलिए इसमें गुणात्मक बढ़ोतरी जरुरी है। लेकिन उम्मीद की कई किरणें बाकी है और सरकार गंभीरता से कई विकल्पों पर विचार भी कर रही है। बेरोजगारी का मुद्दा आखिर में नीति–निर्माताओं को उद्वेलित करने में सफल रहा है और वह उस पर ध्यान देने लगे हैं लेकिन समाधान भारत में आ रहे निवेश और तकनीक को अपने ढंग से करने में है। बिना ग्रामिण अर्थव्यवस्था को सुधारे अर्थव्यवस्था की समस्या को काबू नहीं पाया जा सकता।

सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में सुधार

दूसरे श्रम आयोग के गठन के बाद सामाजिक सुरक्षा को बहुत अधिक बल मिला है। राजग सरकार के श्रम मंत्री ने अपनीओर से खुद गंभीर पहल की और भारत श्रम सम्मेलन 2003 में सामाजिक सुरक्षा के मामले में एक विस्तृत पैकेज जारी करने पर लगभग सहमति हासिल कर ली। उस पैकेज के तहत अनौपचारिक और असंगठित लाखों लाख मजदूर कम आय वाले स्वरोजगारी को ढेरों लाभ मिल सकता था और उनके पेंशन की भी व्यवस्था हो सकती थी। लेकिन जबसे 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ है, केंद्र में सरकार बदली है, तब से इस मामले पर कोई प्रगति नहीं हुई है। समय बीतता जा रहा हैं। चूंकि यह योजना कुछ खास जिलों में चलाई गई थी, इसजिए इस योजना के आधार पर आगे का रास्ता तय करने में आसानी होगी और खतरों से पहले ही सावधान हो जाएंगे। लेकित मुख्य समस्या फंड उगाने की है। यूपीए की सरकार अपने ही सहयोगियों की राजनीति में उलझी हुई है, उसके पास सामाजिक सुरक्षा के तरफ ध्यान देने का समय ही नहीं है। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में जिस तरह से मजदूरों का पंजीकरण कराया वह अपने आपमें बड़ा सुखद अनुभव रहा है। आवश्यकता है कि सभी जिलों में इस अभियान को चलाया जाए, ताकि जब भी सामाजिक सुरक्षा योजना को कानूरी रुप मिले लोग उसका फायदा उठा सके।

कानूनी पहल

औद्योगिक विकास अधिनियम– 1947 के अनुच्छेद –25 वें संशोधन ने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। राजग की सरकार यह संशोधन करना चाहती थी और तब के वित्तमंत्री ने अपने बजट में भाषण में भी हायर एंड फायर नीति का खाका सामने रखा था। भारतीय मजदूर संघ केंद्रीय मजदूर संगठनों में शायद इकलौता संगठन था, जिसने कर्मचारियों के खिलाफ इस संशोधन के विरोध में जबरदस्त आवाज उठाई थी और जिसके दबाव के कारण ही भारतीय श्रममंत्री ने तुरंत स्पष्टीकरण देकर मामले को सुलझाने की कोशिश की थी। वह एक ऐतिहासिक मोड़ था। विरोध का स्वर इतना ऊंचा था कि पूरे देश में इसे महसूस किया गया और सरकार ने तुरंत फैसले को वापस लिया। भारतीय श्रम सम्मेलन के दो सत्रों में हुए कड़े विरोध के बाद कर्मचारियों का मनोबल भी ऊंचा हुआ। तमिलनाडु सरकार और वहां की कर्मचारियों की हड़ताल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला कि कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया और तुरंत कानून में संशोधन कर दिया। वित्तीय क्षेत्र में

लगातार बढ़तें गैर निष्पादित संपत्तियों ने उद्योग जगत की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है और नीत निर्माता यह सोचने लगे हैं कि कर्जों का प्रतिभूतिकरण करने के लिए कानून बनाया जाए। जमा के रुप में लोगों की गाढ़ी कमाई को वापस लाने का मामला सबके लिए बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन श्रमिकों के बकाए की वसूली के लिए कोई ठोस कानून अभी भी नहीं है। केंद्र सरकार के सामने भारतीय मजदूर संघ ने इस मुद्दे को उठाया और यह मांग की कि प्रतिभूति अधिनियम के लागू होने की स्थिति में अन्य राजस्व उगाही के साथ ही श्रमिकों के भी वैध बकायों की वसूली को भी कानूनी रुप दिया जाए।

इस संबंध में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 105 वें नंबर के बैठक में पास प्रस्ताव में विस्तृत मांग रखी गई है। औद्यौगिक विकास अधिनियम में संशोधन कर दिया गया और एक निश्चित समयावधि के अंदर की गई नियुक्तियों को वैध करार दिया गया। यह एक भद्दा मजाक है। सबको मालूम है कि ठेके पर नौकरी की व्यवस्था पिछले दरवाजे से घुस चुकी है और अब इसको नैतिक आधार भी दे दिया गया है। यह आने वाला समय ही बताएगा कि कितने श्रमिकों का इससे भला होगा। भारतीय मजदूर संघ ने इसलिए इस संशोधन का पुरजोर विरोध किया। सर्वोच्च न्यायालय का एक और फैसला श्रमिकों को झकझोर देने वाला था, जिसमें कहा गया था कि न्यूनतम मजदूरी की सीमा से उपर वेतन उठाने वाले कर्मचारियों को वर्कमैन की श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा और श्रम कानून से उन्हें कोई राहत भी नहीं मिलेगी। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उसने तुरंत न्यूनतम मजदूरी से उपर की सीमा 6500 रुपए प्रतिमाह कर दिया, जिसके कारण श्रमिकों की आफत टल गई। भारतीय मजदूर संघ यह मांग करता है कि यह राशि 10000 रुपए तक की जाएगी, जिसमें बोनस भी शामिल हो। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का मुद्दा अभी भी अधर में लटका हुआ है। भारतीय श्रम सम्मेलन में इस मुद्दे पर लंबी बहस हुई, लेकिन नियोक्ता अभी भी इस मामले पर अड़े हैं। वे अभीभी श्रमिकों को जिम्मेदार, सामाजिक, सहयोगी के रुप में नहीं देखते हैं, इसलिए निदेशक मंडल में उनको शामिल करने से बचना चाहतें हैं। लेकिन यदि इस मुद्दे पर खुली बहस हो तो शायद नियोक्ताओं की मानसिकताओं में थोड़ा बदलाव हो। कृषि श्रमिकों के लिए एक बृहद कानून लघु उद्योग एवं अत्यंत छोटे उद्योगों के भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो भविष्य के श्रम आंदोलनों के एजेंडे में शामिल होंगे।

तात्कालिक कानूनी मुद्दे

बोनस संशोधन बिल 2002 जिसमें उच्च सीमा और योग्यता सीमा को बढ़ाए जाने की बात है को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। असंगठित क्षेत्र मजदूर विधेयक भी ठंडे बस्ते में है। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संबंधित विधेयक, जिसे लाए जाने का वादा किया गया था, उसका कुछ अता पता नहीं है। रोजगार प्रत्यक्ष निर्देश अधिनियम में संशोधन करके इसे श्रम कानूनों से बाहर कर दिया गया। श्रम संगठनों की विभिन्न उद्योगों में मान्यता का मुद्दा भी प्रबंधन तंत्र के हाथों में सौंप दिया गया है, जो अपनी इच्छाओं के अनुसार मनमाने तरीके से फैसले लेते हैं। पिछले चार दशकों में देश के उच्च न्यायालय श्रमिकों के अधिकार के सुरक्षा करने और उन्हें न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं बैंगलोर में पानी की आपूर्ति से संबंधित न्यायालय कें फैसले ने औद्योगिक न्याय की दिशा में एक महत्म्वपूर्ण कदम है। लेकिन एलपीजी सुधार के मामले में परिपाटी उलट दी गई और श्रमिकों के हित के खिलाफ लगातार कई घोषणाएं हुई। हाल ही में गुजरात बिलली बोर्ड से संबंधित फैसला ठेका मजदूरों की दुर्व्यवस्था की पूरी कहानी कहती है। अभी भी इस मामले में कोई राहत नहीं मिली है। यह फैसला सेल के मामले में दिए फैसले के ठीक उलट है, जिसमं सरकारी विभागों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हड़ताल के अधिकार से संबंधित फैसले ने पूरे देशमें विवाद खड़ा कर दिया। इस समय दुबारा सुनवाई की कार्यवाई लंबित है। औद्योगिक विकास अधिनियम में 1600 रुपए की सीमा से संबंधित फैसला भी इसी का उदाहरण है। गुजरात जैसे कई राज्यों के विशेष आर्थिक क्षेत्र में श्रम कानूनों की अनदेखी जानबूझकर की जा रही है। आंध्र प्रदेश ने अपने श्रम कानूनों में संशोधन किया जिसके कारण ठेका मजदूरों के ऊपर काफी प्रतिकूल असर पड़ा।

बंदी एवं हड़ताल

हड़ताल दिनों दिन कम होती जा रही हैं और तालाबंदी बढ़ती जा रही है। अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी यही स्थिति है। जहां सिर्फ दो फीसदी हड़ताल है और 98 फीसदी तालाबंदी। अर्थशास्त्रियों ने हड़ताल से संबंधित एक सूचकांक बनाया है, जिसे वे इंटेलेक्चूयल इंटेटेविटी आफ स्ट्राइक्स का नाम देते हैं। इस सूचकांक के आधार पर यह गणना की जा सकतीहै कि कितने दिनों तक हड़ताल हुई और कितने दिनो तक तालाबंदी हुई। इस सूचकांक के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तालाबंदी के कारण मानव

दिन रोजगार में तीन गुने से भी अधिक की कमी आई। वामपंथियों से जुड़े श्रम संगठनों ने कई संदेहास्पद समझौते किए। इन समझौतों के कारण उन क्षेत्रों पर भारी मार पड़ी जिनसे बहुत सारे लोग रोजगार से जुड़े हुए थे। जैसेकि जूट उद्योग। बंगाल की सरकार ने जुट उद्योग को पूरी तरह कुचल दिया और मजदूरों के साथ जो समझौते हुए वे पूरी तरह से श्रमिको के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारतीय मजदूर संघ ईमानदारी से अपने सिद्वांतों पर खड़ा है। भारतीय मजदूर संगठन ने हमंशा सड़क पर आकर लड़कर मजदूरों का हक दिलाने में विश्वास रखता है न कि किसी समझौते के तहत मजदूरों के जीवन पर ही दांव खेल देता है। औद्योगिक लोकतंत्र के लिए त्रिपक्ष का सिद्वांत बहुत आवश्यक है। द्वितीय वित्त आयोग ने लगभग सभी विवादास्पद मुद्दों पर जो अपना निष्कर्ष दिया है या जो सुझाव दिए हैं यदि वे मजदूरों के हित के खिलाफ हुए तो पूरी तन्मयता से उसके खिलाफ संघर्ष किया जाएगा। सामूहिक बुद्धिमत्ता और सहयोग के आधार पर मजदूरों के हित और उनके विकास के लिए जो रास्ता तैयार किया गया है। हम उसी का पालन करते रहेंगे।

त्रिपक्ष–भारतीय श्रम सम्मेलन

भारतीय श्रम सम्मेलन में तीन महत्वपूर्ण सत्र होने थे, लेकिन 2004 में आम चुनाव होने के कारण यह सम्मेलन नहीं हो सका। मजदूर संघों की परंपरा के अनुसार भारतीय मजदूर संघ ने 2002 एवं 2003 में आयोजित 38 वें सम्मेलन में पांच प्रतिनिधिमंडल एवं सलाहकार दल भेजे। 38 वां सम्मेलन 28–29 सितंबर 2002 को हुआ जिसमें दूसरे श्रम आयोग के रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा हुई। जिन महत्वपूर्ण मसलों पर इस सम्मेलन में विचार हुआ वे हैं: वैश्वीकरण एंव रोजगार सृजन की समस्याएं, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, विनिवेश पर सरकार की नीति, वैश्वीकरण के युग में लघु एवं मझौले उद्योगों की स्थिति और द्वितीय श्रम आयोग। 39 वां सम्मेलन 16–17 और 18 अक्तूबर, 2003 को संपन्न हुआ। इसमें भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें– आर्थिक उदारीकरण और रोजगार सृजन,रोजगार संरक्षण एवं कार्यकुशलता विकास, श्रम सुधार एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूर, सामाजिक सुरक्षा। अनुसूची के अनुसार 40 वां सम्मेलन 29–30 अक्तूबर, 2004 को होना था। 29 नवंबर,2004 को स्थायी समिति की बैठक में सम्मेलन के लिए दो महत्वपूर्ण विशयों का चयन किया गया। उनमें है असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों में संशोधन। चूंकि श्रम सम्मेलन मजदूरों की समस्या पर विचार करने एवं उसका उपाय निकालने का सर्वोच्च मंच है,इसलिए श्रम संसद का गठन लगातार होना चाहिए। अब

जबकि 40 वां सम्मेलन बकाया है और अभी तक इसे बुलाया नहीं गया है। इसका अर्थ है यह सत्र गटर में चला गया है। उनके लिए जो भारतीय श्रम सम्मेलन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। से भी इस सम्मेलन के स्थगन के कारण वे भी अब मूकदर्शक बने हुए हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो अभी छूटे हुए हैं। जैसे विशेष जोन और आर्थिक जोन में स्थापित होने वाले नई औद्योगिक इकाइयां, जहां सरकार ने मौलिक कानून को ही ताक पर रख दिया है। भारतीय मजदूरोंका देश या देश से बाहर पलायन, जिसके कारण उनकी बदहाल स्थिति। विदेशी या विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम वाली कंपनियों में श्रम कानून का पालन बीपीओ उद्योग सेवा क्षेत्र में मजदूरों की समस्या, प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी और उद्योगों का श्रमिकीकरण।

मजदूरो की हित की रक्षा में श्रम संगठनों का योगदान ऐतिहासिक रहा है। लेकिन उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बाद श्रम संगठनों की विश्वसनीयता कसौटी पर आ गई है। सरकार की नीतियां श्रम क्षेत्र में काफी असर डाल रही है।

आर्थिक प्रसंस्करण और विशेष प्रसंस्करण क्षेत्र की समस्याएं

इस समय विश्व में लगभग तीन हजार आर्थिक प्रसंस्करण क्षेत्र हैं, जिनमेंसे 75 फीसदी प्रसंस्करण क्षेत्र अकेले चीन में है। लेकिन इन क्षेत्र में श्रमिकों की हित में सुरक्षा करने वाले कोई कानून नहीं है। उनकी सामाजिक सुरक्षा पूरी तरह खतरे में है और उनका जीवन स्तर काफी नीचे है। लेकिन चीन मेंश्रमिकों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। उनकी शिकायत दर्ज कराने वाला कोई नहीं है और वहां लोगों की इच्छा का कोई मतलब भी नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने व्यापार के क्षेत्र में भारत और चीन को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। विश्व व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ने के लिए दोनों आपस में ही लड़ रही हैं यह उचित नहीं है। सरकार भी चाहती है कि चीन की तरह यहां के मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। केंद्र में आने वाली विभिन्न सरकारें और राज्य सरकारें लगातार विशेष आर्थिक क्षेत्र या आर्थिक प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित कर रही हैं। यह कहने में काई हिचक नहीं कि ये विशेष आर्थिक प्रसंस्करण क्षेत्र मजदूरों के लिए कसाई घर स्थापित हो रहे हैं। मजदूर बुरी तरह फंस चुके हैं। राज्य सरकारें और नियोक्ता मिलकर मजदूरों की सिथिति अत्यंत दयनीय बना चुके हैं। इनको आर्थिक प्रसंस्करण क्षेत्र कहने के बजाय इसे कर्मचारी कैद क्षेत्र और कर्मचारी कसाई घर क्षेत्र कहना चाहिए। श्रमिक संगठनों के सामने बड़ी चुनौती है कि इस क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा की जाए। पिछले पांच दशकों

में भारतीय मजदूर संघ मजबूती का पायदान चढ़ता आया है। दिल्ली में हुए पहले सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ ने जो उपस्थिति दिखाई थी वह उसके वटस्वरुप के बीज मात्र था।

जिम्मेदार सहयोग

संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा की सरकार ने भी सबसे बड़े मजदूर संगठन के नाते भारतीय मजदूर संघ के महत्व को स्वीकारा है। वैसे भी मजदूर संगठनों की जिम्मेदारी और उनकी विश्वासनीयता के आगे सरकार को उसका महत्व देना लाजमी बनता है। भारतीय मजदूर संघ ने हमेशा एक संतुलित आचरण रखा है। और उसी तरह का उसे सरकार से भी मिला है। वैसे भी साझे के सरकार के लिए किसी के खिलाफ बदले की भावना से काम करना काफी मुश्किल है। संयुक्त मोर्चा की सरकार भी मित्रवत और सहयोग का व्यवहार कर रही है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग

केन्द्र सरकार ने पहले श्रम आयोग की रिपोर्ट 1969 में आने के 30 साल बाद दूसरे श्रम आयोग का गठन किया। इस श्रम आयोग ने सिर्फ दो ही मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों को सामिल किया गया। भारतीय मजदूर संघ के साजी नारायण और इन्टेक के संजीव रेड्डी सदस्य बनाये गये। भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हासू भाई दवे संगठन के प्रतिनिधि के रूप में शुरूवात में ही इस आयोग के सदस्य थे। बाद में उनकी जगह पर उपाध्यक्ष साजी नारायण को आयोग में भेजा गया। वामपंथी मजदूर संगठनों को इस अयोग से अलग रखा गया । जिसके कारण उनकी राय व उनका सहयोग आयोग को नहीं मिला। आयोग ने 6 अध्ययन समूह का गठन किया और उनके 6 महत्वपूर्ण विषय दिये। ये विषय थे महिला और बाल मजदूर, सामाजिक सुरक्षा, कानूनों की समीक्षा, असगिठन क्षेत्र, वैश्वीकरण और उसका प्रभाव तथा क्षमता विकास। श्री केशव भाई ठक्कर, श्री एस0एम0 धारप, श्री ओमप्रकाश अग्धी, और कु. मंगलम्बा इन अध्ययन समूहों के सहयोगी बने। इस श्रम आयोग ने 7 अधिनियमों का प्रारूप तैयार किया। जिसपर आगे कार्यवाही अपेक्षित है। भारतीय मजदूर संघ ने इन कानूनों को बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। दूसरे श्रम आयोग की रिपोर्ट 26 जून 2002 को आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्रधान मंत्री को अन्य सदस्यों की उपस्थिति में सौंप दिया गया। उस समय श्रम मंत्री और रक्षा मंत्री भी उपस्थित थे। आयोग के रिपोर्ट में कुछ मजदूरों के हित जुडे सुधार के सुझाव थे। तो कुछ उनके अहित के। मजदूरों के अहित वाले श्रम सुधार के कानून में संसोधन के प्रति भारतीय मजदूर संघ

ने अपनी आपत्ति लगा दी। भारतीय मजदूर संघ की यह आपत्तियां द्वितीय श्रम आयोग की रिपोर्ट का हिस्सा है। और वह इतिहास में दर्ज हो चुकी है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनटेक के प्रतिनिधियों ने मजदूर विरोधी प्रस्तावित कानूनों को अपनी मंजूरी दे दी। मोटे तौर पर 8 ऐसे मुद्दे जिनपर बीएमएस ने अपनी आपत्तियां जताई। ये मुद्दे थे :

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुच्छेद 5 बी में संसोधन का मुद्दा। भारतीय मजदूर संघ ने इसे खत्म किये जाने के प्रस्ताव का विरोध किया और मांग की कि उसके क्षेत्र को और बढाया जाना चाहिए।
2. नियमित मजदूरों को ठेका मजदूर में नहीं बदलना चाहिए।
3. हड़ताल के अधिकार को संरक्षित रखना चाहिए।
4. छुट्टियों के दिवस को किसी भी स्थिति में कम नही किया जाना चाहिए।
5. काम के घंटे को 8 घंटे के बजाय 9 घंटे नहीं किया जाना चाहिए।
6. किसी भी काम को श्रम कानून की परिधि से बाहर नहीं ले जाना चाहिए।
7. बाहरी नेतृत्व और राजनीतिक चंदे का भी विरोध किया गया। सामान्य दर्शन और व्यवहार के आधार पर कुछ तकनीकी शब्द इस्तेमाल किए गये जैसे–श्रम कानुनों में लचीलापन, गुप्त मतपत्र, बोनस की अधिकतम सीमा और काम का अधिकार आदि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक वृहद कानून की अभिकल्पना को मूर्त रूप दिया गया। संसद के पटल केन्द्र में आने वाली सरकारों ने अभी तक बड़े संसोधन की पहल नहीं की है।

ठेकेदारी व्यवस्था का बढता प्रभाव

संसद में श्रम कानून मे जो संसोधन किया गया, वह ठेकेदार व्यवस्था के पूरी तरह हाबी होने की बानगी है। इस संसोधन के जरिये न सिर्फ कर्मचारियों के सिर पर अनिश्चितता की तलवार लटका दी गयी, बल्कि उनके दमन और शोषण का भी रास्ता खोल दिया गया। यही नहीं इस संसोधन ने बिचौलिये के लिए लूट का राजमार्ग भी खोल दिया। ठेके पर मजदूर की व्यवस्था ने नियमित मजदूरों की संख्या में कटौती कराकर रोजगार का अवसर द्वितीय बाजार में भेज दिये। प्राथमिक रोजगार और द्वितीय रोजगार के बीच में एक बहुत ही भारी अंतर है। इस संसोधन ने कर्मचारियों एवं कर्मचारी संगठनों की मारक क्षमता को भी कमजोर कर दिया। इस संसोधन ने मजदूर संगठनों को मजबूर कर दिया कि वे न सिर्फ मजदूरों की रक्षा के लिए ठेका व्यवस्था का विरोध करे बल्कि

प्राथमिक रोजगार के घटते अवसर और खुद मजदूर संगठनों की रक्षा के लिए भी आगे आये। भारतीय मजदूर संघ ने ठेकेदार मजदूर महासंघ का गठन कर इस मसले पर पहल की अब आवश्यकता है कि ठेकेदार मजदूर महासंघ को मजबूत किया जाये ताकि आगे आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाय। पिछले तीन सालों में कुछ ठोस प्राप्ति देखी गयी । लेकिन उससे भी अधिक नुकसान देखा गया जिसकी तुरंत मरम्मत कराने की आवश्यकता है। कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो मजदूर संगठन के आन्दोलन के लिए अन सुलझे मुद्दे हैं।

सदस्यता सत्यापन

पुरानी कानूनी लड़ाई का आखिरी अन्तिम परिणाम निकला, जब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 दिसम्बर 2002 को केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि वह मजदूर संगठनों की सदस्यता संख्या का पुनर्जाच करें भारतीय मजदूर संघ ने 83 लाख 18 हजार 348 सदस्यों की सुची जमा की और अन्य मजदूर संगठनों के सदस्यता संबंधी दावे पर आपत्तियां भी दर्ज करायी। यह मामला कानूनी उलझनों में उलझ कर रह गया औ एक के बाद कई मुकदमें दर्ज हो गये। पुर्नजांच का काम इतना बढ गया कि अन्तिम निर्णय का अभी भी इंतजार हो रहा है। चूंकि भारतीय मजदूर संघ ने सबसे अधिक सदस्यों की दावेदारी की है। और दावे से संबंधित दस्तावेज काफी सुदृढ़ हैं। इस लिए अंतिम परिणाम तो यही आयेगा कि भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है।

आवलोकन

राष्ट्रीय कार्यसमिती की बैठके

त्रिवेंद्रम में हुऐ अधिवेशन के बाद अ. भा. कार्यसमिति के सदस्य निम्नलिखित बैठको मे मिले और प्रस्ताव पारित किये।

1. 101 वी कार्यसमिती : 5,6,7 सितंबर 02 शिमला
   प्रस्ताव क्र. 1 – विनिवेश
   प्रस्ताव क्र. 2 – दूसरा श्रम आयोग

2. 102 वी केन्द्रीय कार्यसमिती : 6, 7, 8 अप्रैल – सतारा (महाराष्ट्र)
   प्रस्ताव क्र. 1 – स्वदेशी जागरण मंच के स्वदेशी आंदोलन में सहभागिता
   प्रस्ताव क्र. 2 – विनिवेश मंत्रालय के बरखास्तगी की माँग

प्रस्ताव क्र. 3 – भविष्य निर्वाह पर ब्याजदर में कटौती का विरोध
प्रस्ताव क्र. 4 – विदेशी निवेश एवं एन्.के.सिंह समिति की सिफारिशों को वापस लेने की माँग
प्रस्ताव क्र. 5 – विश्व व्यापार संघ की नीति के विरोध में आंदोलन
प्रस्ताव क्र. 6 – दूसरा श्रम आयोग
प्रस्ताव क्र. 7 – महिलाओं को काम पर रात के समय बुलाने पर विरोध
प्रस्ताव क्र. 8 – कर्मचारी राज्य बीमा निगम

3. 103 वी केन्द्रीय कार्यसमिति 22, 23, 24 सितम्बर 2003 –विशाखापटनम्
प्रस्ताव क्र. 1– जूट उद्योग
प्रस्ताव क्र. 2– सारकारी कर्मचारियो के हडताल के विरूध्द सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का विरोध
प्रस्ताव क्र. 3–सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना

4. 104 वी केन्द्रीय कार्यसमिति 5,6,7 अप्रैल 2004 – सूरत
कोई प्रस्ताव नहीं

5. 105 वी केन्द्रीय कार्यसमिती बैठक– 4,5,6 अक्तूबर 2004, –पटना
प्रस्ताव क्र. 1– कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधि खाते का निरीक्षण
प्रस्ताव क्र. 2– सरकारी कर्मचारीयोंके लिये छठे वेतन आयोग का गठन
प्रस्ताव क्र. 3– कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधि कार्यालयों के कर्मचारियों के महासंघ की मान्यता वापस लेनेवाले श्रम मंत्रालय के निर्णय का विरोध
प्रस्ताव क्र. 4– विश्व व्यापार संगठन की जिनेवा सभा में भारत सरकार का समर्पण

6. 106 वी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक– 21 व 22 फरवरी 2005– रायपुर
1. असंगठित श्रेत्र 2. पेटेन्ट कानून

क्षेत्र व्यवस्था

सुविधा की दृष्टि से भारतीय मजदूर संघ का कार्य–कलाप पॉच क्षेत्रों मे विकसित किया है यह पाँच क्षेत्र है, उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत तथा पूर्वोत्तर भारत जहाँ क्षेत्र से जुडे प्रदेशों के समन्वित कार्यक्रम होते है, नियमित रूप से बैठकें होती

है। प्रत्येक क्षेत्र ने अभ्यास वर्गोंका आयोजन किया। अनेक कार्यकर्ताओं को इनका लाभ हुआ। सभी क्षेत्र प्रमुखों ने सदस्यता सत्यापन के काम को चुस्ती से अवलोकन किया इसलिए यह काम समुचित रुप से पूरा हुआ।

अभ्यासवर्ग

1. दि. 9 नवम्बर 2003 को सभी महासंघों के महामंत्री, अध्यक्ष और कोषाध्यक्षों की बैठक सौदामिनी सभागृह (पुणे) में संपन्न हुई। सभी महासंघों के पदाधिकारियों ने बैठक में शामिल होकर भा.म.संघ की प्रदेश ईकाईयों से संबंधो सहित अन्य अनेक विषयों की चर्चा में चुस्ती से भाग लिया। दो दिन की इस बैठक का श्रध्देय ठेंगडीजी ने उद्घाटन किया तथा जानेमाने अर्थशास्त्री श्री. रूद्रदत्तजी का अभिभाषण हुआ ।
2. सभी कोषाध्यक्षों के लिए दि. 01 व 02 अगस्त 2004 को 'डॉ. हेडगेवार स्मृति मंदिर, रेशमबाग, नागपुर ' में अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग हुआ। जिसमें लगभग सभी कोषाध्यक्षो की उपस्थिती रही। जिस तरीके से हिसाब किताब रखने की भा.म.संघ को अपेक्षा है उसकी बारीकी से जानकारी दी गयी।
3. अंकलेश्वर में पूर्णकालिन कार्यकर्ताओं का अभ्यास वर्ग आयोजित किया गया। उन्होंने अपने अपने स्तर पर भारी मात्रा में कार्यक्रम किये इनमें से महत्वपूर्ण आंदोलन है।

महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं आन्दोलन

1. 16 अप्रैल 2002 – सार्वजनिक क्षेत्र बंद

तेरहवें अखिल भारतीय अधिवेशन के तुरन्त बाद ही सरकार द्वारा मूलभूत ढाँचे में परिवर्तन के प्रयास के विरोध में भारतीय मजदूर संघ द्वारा दि. 16 अप्रैल 2002 के दिन सार्वजनिक क्षेत्रों में बंद का नारा दिया। इस हडताल में भारतीय मजदूर संघ के साथ ही अन्य श्रमिक संगठन भी शामिल हुए और यह आंदोलन बहुत ही सफल रहा। इस क्षेत्र में कार्यरत भा.म.संघ से संबध्द महासंघ द्वारा 2840 सभाओं का आयोजन किया गया जिसमें हजारो कर्मचारियों के साथ साथ लाखो लोगों को संबोधित किया गया।

2. 25 सितम्बर 2002 से 2 अक्तूबर 2002 – विश्व व्यापार संघ – मोडो, तोडो, छोडो, सप्ताह

भारत सरकार की नीतियों में सुधार लाने हेतु भा.म.संघ की राज्य ईकाईयों ने आपसी

सहयोग से एक महत्त्वापूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख नगरों मे महाजुलूस निकाले जिसमें 4 लाख से भी अधिक कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। प्रदर्शन, मोर्चा (शोभायात्रा), नुक्कड सभाएँ, स्थयात्रा, ग्राम सभाएँ, व्यक्तिगत संपर्क जैसे विभिन्न प्रकारोंसे इस समय आंदोलन किया गया। करोडो वृत पत्र वितरित कर पुस्तिकाओं द्वारा विश्व व्यापार संघ के विषय में शासन को अपनी शोषणपूर्ण सरकारी नीति बदलने पर मजबूर करने का या दबाव डालने वाला गुट बनानेका या वैकल्पिक विश्व व्यापार संघ बनानेका अन्यथा विश्व व्यापार संघ से हट जाने का सुझाव दिया गया। उपरोक्त ढंगसे शासनको अपना रवैय्या सुझावो के अनुसार बदलना पडा। 30 सितम्बर 2002 में लखनऊ में और 2 अक्तूबर 2002 को पुणे में दो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जूलूसों के निकलने के समय स्व. ठेंगडीजी प्रमुख वक्ता थे।

इस पूरे कार्यक्रम की विशेषता यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है। श्रमिक एवं किसानों ने एक दूसरें की मित्रता/सहभागिता पायी

3. 23 जुलाई 2003 से 9 अगस्त 2003 – जिलास्तरीयता प्रदर्शन

भा.म.संघ और भारतीय किसान संघ दोनों ने मिलजुलकर लगभग 400 जगहो पर प्रदर्शन का आयोजन किया तथा ग्रामसभा के माध्यम से 1 करोड 30 लाख से ज्यादा लोगों से संपर्क किया। समाज की जागृति के कार्यक्रम की यह एक बडी उपलब्धि है।

4. 20 सितम्बर 2003

विश्व व्यापार संगठन की 5 वी मंत्रीस्तरीय कॅनकून परिषद की संध्या पर सरकार को कडी नीती तथा सुरक्षा के लिये बाध्य करने के लिये भारतीय किसान संघ के 30 हजार किसान और भारतीय मजदूर संघ के 10 हजार कार्यकर्ता रामलीला मैदान पर एकत्रित हुए।

भारतीय मजदूर संघ के अन्य कार्यो का संक्षिप्त विवरण

सर्वपंथ समादर मंच

हमारे सभासद सभी वर्गों के और धर्म के है। वे सब एक साथ समाज मे विश्वास रखते है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत समाज मे भाईचारे की भावना रखकर वे कार्यरत है। भेद रहित समाज को बनाने हेतू पवित्र मातृभूमी की सेवा मे उन्होने अपना जीवन बिताने का प्रण लिया है।

महिला विभाग

भारत के महिला वर्ग को संगठित और सशक्त बनाने के लिये हमारा महिला महासंघ अच्छा काम कर रहा है। ऐसे कई भाग है, जैसे की, आंगनवाडी, बिड़ी जहाँ महिला श्रमिक बहुत मात्रा में काम कर रही है।

समाज प्रबोधन कर, लिंगभेद, छुआछुत आदि पर विजय प्राप्त करके एक संघ समाज ही राष्ट्र को गौरवशाली बना सकता है । इसी दिशा मे भामसंघ और महिला विभाग कार्यरत है।

पर्यावरण मंच

पर्यावरण मंच की स्थापना कुछ सालों पहले ही हुई है। गुजरात तथा मध्यप्रदेश आदि राज्यों मे ही इसके काम को कुछ गति मिली है।

श्रम संगठन बुलंद आवाज लिए इसमें भरसक कार्य कर सकते है। गैर जिम्मेदार व्यापारी इसके व्यापार में बहुत अमीर हो रहे है। पर्यावरण संतुलन बिगडकर समाज को ही नुकसान पहुँचेगा अतः लोगों मे पर्यावरण के प्रति जागृति लाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को उठानी होगी।

विधि समिति का कामकाज

विगत 3 सालों से भा.म.संघ की विधि समिति कार्यरत है। कामकाज के कुछ मुद्दे :

1 श्रम के कानून के वर्तमान मुद्दों की चर्चा।

2 इस विषय की महत्त्वपूर्ण जानकारी सदस्यों को देना।

3 आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, विदर्भ, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश में संयोजक सहित कानून समिती का गठन हुआ।

4 राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक कानून में सुधार के बारे मे बेंगलूर में 8/9 मार्च 2003 को वर्कशॉप संपन्न हुआ। विविध विषयों पर चर्चा हुअी। (राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट पर मतभेद दर्शाने वाले पत्र के साथ) जैसे वैश्वीकरण का मजदूरों पर होने वाला असर श्रमिक कानून में सुधार के बारे में सरकार द्वारा दिया गया प्रस्ताव, भारतीय श्रम परिषद का संयोजन।

5 भारत मे सामाजिक सुरक्षा का भविष्य इस विषय पर हैदराबाद (आंध्रप्रदेश) में राष्ट्रीय सेमिनार संपन्न हुआ। तत्कालीन श्रममंत्री साहिबसिंह वर्मा उद्घाटक थे। आंध्रप्रदेश के श्रममंत्री, श्री. आर. के ए. सुब्रमण्य डायरेक्टर जनरल ऑफ ई. एस. आई. प्रादेशिक भविष्य निधि के कमिशनर आदि भी सहभागी थे।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

1977 में भा.म.संघ को पहला मौका मिला व जिम्मेदार केंद्रीय श्रम संगठन की पहचान भी मिली । अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला। 1996 से भा. म. संघ प्रतिनिधित्व कर रही है । हमारे प्रतिनिधि जो प्रस्ताव देते है उसकी पुस्तिका अंततः श्रम संगठन द्वारा बनायी जाती है।

विश्व व्यापार संगठन के ट्रेड मेकेनिज़म के चंगुल से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को बाहर निकालने के लिये भा.म.संघ ने प्रयत्न किया। 1994 की बैठक में विकासशील देशों की तरफ से आवाज उठायी। इस विरोध को अब समर्थन प्राप्त हुआ है और महत्त्व भी मिला है । तब से भा.म.संघ भारत की एवं तीसरे जगत की आवश्यकतानुसार मदद कर रही है। यह कार्य विश्व के इतिहास में लिखा जाएगा।

अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन की 90, 91, 92 वी बैठकें जिनेवा मे जून महीने में हुई थी । भा म. संघने अपने प्रतिनिधि एवं एक सलाहकार समेत (8 सदस्य) इनमें प्रतिनिधित्व किया था।

अ) 90 वीं बैठक – 3 जून – 20 जून 2002
श्री. केशुभाई ठक्कर – प्रतिनिधि, श्री. रवि रामन – सलाहकार।
उपस्थिती मुद्दे –

- सहकारिता को बढावा।
- व्यवसायिक दुर्घटनाएँ एवं बीमारियाँ ।
- उत्तम कार्य व अनौपचारिक अर्थव्यवस्था।
- 20 सिफारिशों की वापसी।

इ) 91वी बैठक – 3 जून – 19 जून 2003.
श्री. केशुभाई ठक्कर – प्रतिनिधि, श्री. रवि रामन – सलाहकार उपस्थित मुद्दे –

- प्रौद्योगिकी के जमाने में आजीविका और प्रशिक्षण
- औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थय।
- रोजगार संबंधी रिश्तों को बढावा।
- निरन्तर सुरक्षित रोजगार की गारंटी।

उ) 92 वी बैठक – 1 जून – 16 जून 2004

श्री. हसुभाई दवे, प्रतिनिधि, श्री. रवि रामन, सलाहकार उपस्थित मुद्दे –

- शिक्षा, आजीवन शिक्षा की (मानव संसाधन विकास)
- वैश्वीक अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों के लिए न्यायपूर्ण व्यवहार।
- मत्स्य उद्योग।
- प्रस्ताव।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 92 वी बैठक में 10 ठराव प्रस्ताव हुए।

1. लिंगभेद रहित समानता के आधार पर समान वेतन और प्रसूति सुरक्षा।
2. मत्स्य उद्योग संबंधी कार्य।
3. वैश्वीक अर्थव्यवस्था मे प्रवासी श्रमिकों के लिए न्यायपूर्ण रोजगारी।
4. आर्थिक वृतांत और लेखा जोखा परीक्षण 2002–2003 साल के लिए।
5. इराक को दिये जाने वाले अंशदान का बकाया एवं भुगतान।
6. नये देशों के अंशदान का निर्धारण।
7. 2005 के बजट के लिए अंशदान का निर्धारण।
8. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में प्रशासकीय न्याय पंच का गठन।
9. आइ एल ओ स्टाफ पेन्शन कमेटी पर नियुक्तियां।

भा. म. संघ के प्रकाशन व पत्रिकाएँ

भा. म. संघ दो पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है। हिंदी में 'विश्वकर्मा चेतना' और अंग्रेजी में 'विश्वकर्मा संकेत'। तय हुआ कि दोनों को एकत्रित करके 'विश्वकर्मा संकेत' नामक दोनों भाषाओं मे एक ही पत्रिका निकाली जाए। कार्यकर्ताओं के पास राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की बहुत जानकारियाँ है जो इस पत्रिका द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका के लिए आर्थिक मदद करना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। इसका पाठक वर्ग धीरे धीरे बढ रहा है।

विविध केंद्रिय परिषद तथा समितीयों के रिपोर्ट

भा.म.संघ 26 सरकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे इ पी एफ, सी बी डब्ल्यू ई, इ एस आइ एस इनमे भा.म.संघ के प्रतिनिधि भरसक कार्य कर रहे है। प्रमुख समितियों के कार्य का सारांश रूप

1. ई पी एफ समिती :

अध्यक्ष श्री. हशुभाई दवे, श्री अलमपल्ली वेंकटरामन, श्री. वैजनाथ राय इन्होने इ पी एफ कमेटी मे सक्रिय रूप से भाग लिया। कर्मचारियों के भविष्य निधि पर व्याज की दर 2004–05 के लिए 12प्रतिशत हो इसलिये भा.म.संघ ने बडी बहस छेडी। अन्य संगठन 9.5प्रतिशत पर समाधानी है। सभी ने मिलकर वर्तमान दर 8.5प्रतिशत पर असंतोष व्यक्त किया है।

2. सी बी डब्ल्यू इ :

अभी तक भा.म.सघ के उपाध्यक्ष श्री. केशवभाई ठक्कर इस बोर्ड के चेयरमन थे। केंद्र में सरकार बदल जाने पर (काल से पहले) उनकी जगह पर गैर श्रमिक युनियन के अधिकारी को यह पद सौपा गया। भा.म. संघ ने इसका जमकर विरोध किया। आग्रहपूर्वक माँग की कि इस समिति का चेअरमन श्रमिक संगठन का ही होना चाहिए।

हमारे अखिल भारतीय मंत्री श्री. अमरनाथ डोगरा इस बोर्ड में प्रतिनिधि है। श्री. रवि रामन आइ आइ डब्ल्यू ई में प्रतिनिधित्व करते है। प्रदेश के अनेक अधिकारी तथा कार्यकर्ता सी बी डब्ल्यू की प्रादेशिक कमेटी में प्रतिनिधित्व करते है।

बोर्ड ने पूरा अभ्यास क्रम आर्थिक सुधारों के संदर्भ में बदल दिया। तब श्री. हसुभाई दवे चेयरमैन थे। चार अधिकारियों की उपसमिति में श्री. रवि रामन की भी सहभागिता थी।

3. प्लांटेशन उद्योग :

त्रिपक्षी औद्योगिक समिति की एक बैठक 3.4.2002 को नई दिल्ली में हुई थी। अध्यक्ष मा. शरद यादव (तत्कालीन श्रममंत्री) थे। प्लांटेशन उद्योगों की समस्याओं पर चर्चा हुई। केरल में 20 चाय के बागान बंद हुए। परिणामतः हजारों स्थायी/अस्थायी मजूदर काम खो बैठे। मंत्रीजी की अध्यक्षता में बैठक में मॉनिटरींग सेल तैय्यार करने की माँग की और मंजूर भी हो गई।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा समितिः

भा.म.संघ के 3 प्रतिनिधि इस समिती में नियुक्त है। सुरक्षा, स्वास्थ्य व पर्यावरण आदि विषयों पर अपने विचार प्रकट करने वाली पुस्तिका प्रकाशित की है।

असंगठित क्षेत्र

भा.म.संघ लगभग 38 महासंघों के साथ काम कर रहा है। अब और कुछ संघ (9) इसके साथ शामिल होना चाहते है। ताडी उतारने वाले जंगल रक्षक श्रमिक, मछुवारे, नमक बनाने वाले, वनवासी श्रमिक, पत्थर तोडने वाले बाल मजदूर, जो अपना जीवन स्तर उँचा उठाने की आशा लेकर आए हुए है। स्वास्थ्य विषयक समस्याएँ शिक्षा की समस्याएँ, जंगल में काम करने वाले तथा वनवासीयों की समस्याएँ, कौशल विकास तथा अन्य अनेक समस्याएँ सुलझानी है। गरीबी तथा ऋण की चिंता तो हर क्षेत्र के मजदूरों को सता रही है। ताँगा हॉकने वाले, म्युजियम व ऐतिहासिक वस्तुओं की जानकारी देने वाले मार्गदर्शक, यातायात चलाने वाले सारे चालक–वाहक सब ही भा.म.संघ में शामिल होने को उत्सुक है। मिजोरम व मणिपुर वासी भी हिंदी भाषा से ज्यादा परिचय न होने पर भी भा.म.संघ का गीत गाते है। इस तरह भारत की चारों दिशाओं में दूरदराज तक भा.म.संघ का नाम पहुँचा हुआ है। हजारो लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है और निरन्तर किया जा रहा है। स्फूर्तिदायक इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति व परंपरा, सुजलाम सुफलाम भारत ने अन्य देशों के सामने आशादायक चित्र रखा हुआ है।

भविष्य मे लेने वाले मुद्दे

भा. म. संघ ने प्रधानमंत्रीजी को एक निवेदन दिया है। उसमे नीचे दिये बिंदु आते है। असंगठित मजदूर, बंधुवा मजदूर, ठेकेदारी व्यवस्था, 6 वॉ वेतन आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र मे काम करनेवाले श्रमिकों का वेतन समझोता, निजी क्षेत्र मे काम करनेवाले श्रमिकों का वेतन समझोता, बोनस, ग्रेच्युईटी, भविष्य निर्वाह निधि पर 12 प्रतिशत ब्याजदर ।

समान न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर ही सरकार बनी है। लेकिन सरकारी पद धारण करनेवाले व्यक्ति विश्व की आर्थिक संघटना से संबंधित है। राजग सरकार को सत्ता से दूर रखने के लिये वामपंथी पक्ष भी समान न्यूनतम कार्यक्रम को भूल सकते है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये बडा कार्यक्रम, प्रदर्शन आदि करने होगे। त्रिपक्ष सूत्रों को लेकर यदि सरकार श्रमिकों के हित मे निर्णय लेगी तो हमारा सहयोग मिल सकता है। यदि ऐसा नही होता तो प्रखर विरोध सहना पडेगा।

आकृतिबंध /रचना /पद्धति में बदलाव की आवश्यकता

नये सुधार श्रमिक विरोधी नहीं होने चाहिये – 'रोजगार के अवसर ' विषय पर माँटेकसिंह आहलुवालिया के सुझाव व्यय संबंधी सुधारों पर गीताकृष्णन समिति रेल विभाग के निजिकरण हेतु राकेश मोहन समिति का सुझाव पत्र, नियोजन आयोग की उपसमिती का प्रस्ताव जैसे जो प्रस्ताव पूर्वकाल में विवादास्पद रहें, वह सभी अपनी सिफारिशें देते समय पूँजीवादी ध्येयों का समर्थन करने का एक साधन थे।

यह दुर्भाग्य है कि धारणाओं पर परिणाम करने वाले अनेकों लोगों के दिल में वैश्विकरण के विषय में श्रद्धा स्थान बनाया है। इसी कारण श्रमविषयक सुधारों को लागू किया जा रहा है। इन सुधारों की विशेषता यह है कि वे यहाँ नही बने है, किंतु बाहर से थामे गये है। वे अपनी धारणाएँ, सांस्कृतिक मूल्य एवं परंपराओं पर अधिष्ठित नहीं है। वैश्वीकरण का एक परिणाम यह है कि इससे संगठित क्षेत्र में कमी आई, तथा अनेकों को असंगठित क्षेत्र में ढकेल दिया।

'श्रमशक्ति का बाजार' इन शब्दों से ही प्रतीत होता है कि श्रमिकों को एक वस्तू माना गया है जो खरीदी जा सकती है, जैसे कि सब्जी मण्डी से सब्जी खरीदी जा सकती है। इससे यही प्रतीत होता है कि श्रमिकों को एक इन्सान के रूप में देखने मे सुधार असमर्थ रहे है।

वर्ग संघर्ष का सिद्धांत तथा औद्योगिक परिवार –

पिछली शताब्दी का अधिकतर काल यही दर्शाता है कि श्रम संबंधों का आधार वर्ग संघर्ष ही रहा। पाश्चात्य संकल्पनाओं के अनुसार सामुहिक लेनदेन टूटने की कगार पर पहुँचे औद्योगिक विवादों को सुलझाने का एक तरीका है। वर्ग संघर्ष की संकल्पना के प्रणेताओं को हर एक सामाजिक संस्थान में संघर्ष ही दिखाई देता है। औद्योगिक संबंधो के विषय में प्राथमिक कानून है। पश्चिमी देशों की स्वीकृत धारणाओं के आधार पर बनी हुई औद्योगिक संबंधो की अंग्रेजी संकल्पनाओं का वह परिणाम स्वरूप है। वहाँ औद्योगिक संबंधों का आधार था मालिक–नौकर के संबंध। किन्तु हम औद्योगिक परिवार की संकल्पना प्रस्तावित करते है।

सामाजिक भागीदारी –

सामाजिक भागीदारी की संकल्पना औद्योगिक विकास सें संबध्द तीन वर्ग मानती है,

जैसे धनिक/मालिक, श्रमिक और ग्राहक उद्योग के लाभ और हानि में तीनो का समान दायित्व हिस्सा होना चाहिये। श्रमिकों का व्यवस्थापन में सहयोग एवं सामाजिक भागीदारी कार्यान्वित करनी होगी।

औद्योगिक रुग्णता –

व्यवस्थापन का अपयशही औद्योगिक रुगणता का मूल कारण होता है। प्रचलित प्रवृती यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में सभी खामीयों का दायित्व कर्मियों के कंधो पर ही दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने औद्योगिक रुगणता पर वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया। उनका यह अनुमान है कि 65 प्रतिशत घटनाओंमे रुगणता का कारण बनी है क्षम व्यवस्थापन, केवल 3 प्रतिशत घटनाओं मे श्रमिक और उनके हडताल रुगणता का कारण बने है। लगभग सभी उद्योगों से भारतवर्ष के सभी विभागों से आये हुए लाखों कार्यकर्ताओं के इस जुलूस के जरिये अनुचित रचना का परदाफाश करके सरकार को एक झटका दिया। श्रमिकों की समस्याओं की अनदेखी करना धीरे–धीरे कम होने लगा। अगले ही बरस नीति में संशोधन लाने हेतु डा. एस्.पी.गुप्ता के नेतृत्व में एक विशेष नये गुट की स्थापना की गई तथा डा. मॉटेक सिंह प्रस्तुत रोजगार निर्मिती के अवसरों का रूख लेकर बतायी गयी श्रमिक विरोधी सिफारिशों को कडेपन से हटाया गया।

2004 में शुरू हुई श्रमिक क्षेत्र में चल रही गतिविधियों को /सदस्यता सत्यापन प्रक्रिया के कारण विराम मिल गया। किन्तु इस प्रक्रिया कें पूरे होते ही अभियान फिर से शुरू होगा ।

रोजगार श्रृजन का तंत्र –

व्यवस्थापकों का अवशय श्रमिकों का विस्थापना में परिणत होता है जिसके फलस्वरूप उद्योगों का बंद होना, 'एक्जिट पॉलिसी', स्वेच्छा निवृत्ती, क्षमता घटाना (आँखो में धूल झोंकने के लिये जिसे 'उचित क्षमता लाना ' कहा जाता है) भरती पर पाबंदी, एन्.आर.एफ्. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बंद करना या उनका निजीकरण करना, अनावश्यक कंप्यूटराइजेशन यांत्रिकीकरण या नियमित कामों को ठेका पद्धति में वर्ग करना, 'मुऑवजा–नही तो घर जा' नीति, वगैरेह. अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में रोजगार निर्मिती के अत्यधिक तंत्र की आवश्यकता है। अपना भारत वर्ष एक ऐसा देश है, जहाँ बेरोजगारों की फौज खडी है। आकार /क्षमता घटाने के दिखावेपर कर्मियों के कुछ हिस्से को इस फौज में जोड देना एक अपराध ही होगा। अतः अपने सारे नियोजन एवं सुधार श्रमिकों के विस्थापन पर नहीं,

तो श्रमिकों की अधिक मात्रा में अंतर्भाव पर निर्भर रहना आवश्यक है। इसी कारण सरकार से भारतीय मजदूर संघ हमेशा माँग करता रहा है कि प्रौद्योगिकी विषयक विकास पर गौर करने के लिये एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी आयोग की स्थापना करें। अधिकतम हाथों से अधिकतम उत्पादन अथवा बडे पैमाने पर उत्पादन के बजाय आम जनता की सहायता से उत्पादन यह दोनों नीति वचन आज भी लागू होते है।

कार्य संस्कृति –

श्रम ही आराधना /कर्म ही पूजा है ऐसा कहकर पूरे संसार को कार्य की संस्कृति सिखाने वाला भारत एकमात्र देश है। कर्म का वृत्ती धर्म केवल कर्मचारियो की संस्कृति की ओर संकेत नही करता है, तो इसमें मालिक की प्रवृति भी अंतर्भूत है। केवल संतुष्ट एवं परितुष्ट /समाधानी कर्मचारी ही उद्योग के विकास में सहयोग दे सकता है। मालिक का भी अच्छी कार्यप्रवृत्ती दिखाना आवश्यक होता है। अमेरीका जैसे देशों मे इसे 'कार्पोरेट इथिक्स' (संस्थागत/सामुदायिक नीतितत्व) यह नामाभिधान है। जब मालिक अपने देश में बेपरवाही के तेवर दिखाते है तो कर्मचारियों को कार्यप्रर्वत्ति अपनाने की सलाह देने का उन्हें अधिकार ही कैसे होगा ? अतः कार्यप्रवृत्ती एवं संस्थागत नीतितत्वो के बेजोड मिलाप से एक सुदृढ़ औद्योगिक संस्कृति बनेगी।

डीसेन्ट वर्क –

मर्यादाशील काम के अधिकार का (जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने पुरस्कृत किया है।) संविधान में मूलभूत अधिकार में अंतर्भाव करना चाहीये। मर्यादशील काम में अंतर्भूत हैं उचित वेतन तथा काम करने के लिये उचित सुविधाएँ। न्यूनतम वेतन पर एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिऐ जिसमें स्थानीय फर्क का प्रावधान होगा। स्थान स्थान में रहने वाला परिवर्तन ही श्रमिकों के स्थलांतर का प्रमुख कारण है।

ठेका मजदूर –

नियमित कामों का ठेका नहीं देना चाहीये। ठेका मजदूर पद्धति अपनाने के दो प्रमुख कारण होते है – एक यह की उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता है और किसी भी क्षण उनको निकाल दिया जा सकता है। यह तो शोषण की तत्वप्रणाली पर ही आधारित है। गुजरात विद्युत मंडल के एक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देशित किया उसके अनुसार ठेका मजदूरी के बहाने लाया जा रहा बंधुआपन तोडना जरूरी है।

काम की सुरक्षता –

कई संस्थानो मे अस्थाई कर्मचारी ठेका मजदूर के बहाने कभी कमार 10 वर्षों से भी ज्यादा दिनों तक काम करवाया जाता है काम की सुरक्षता मजदूरों के मूलभूत अधिकारों मे लाना चाहिए।

हडताल करनेका अधिकार –

सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल करने का अधिकार नही है इस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने विवाद पैदा किया है। हडताल का अधिकार छीनने संबधी कोई भी चाल अलोक तांत्रिक है। हडताल के अधिकार को सीमित रखना या किसी वर्ग क्षेत्र को श्रमिक कानूनों से छुटकारा देने से पहले श्रम संगठनों से विचार विमर्श करके स्वयं निर्बंधनात्मक, वैकल्पिक व परिणामकारक रूप से परीशीलन करने का तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

वेतन –

भा.म.संघ ने प्रस्तावित किया है कि 1. न्यूनतम वेतन का उत्पादकता से कोई संबंध नहीं होना चाहीये। 2. न्यूनतम वेतन से ज्यादा वेतन के लिये उत्पादकता संगठनों से चर्चा का विषय होगा। 3. जब तक प्रत्यक्ष वेतन और जीवनमान वेतन में अंतर रहेगा, बोनस प्रलंबित वेतन रहेगा। अतः बोनस पर अधिकतम सीमा रखना अनुचित होगा।

काम का अधिकार –

काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रुप में सविधान में संमिल्लित करने की मांग भा.म.संघ ने की है।

असंगठित क्षेत्र के लिए सर्वसमावेशक कायदा –

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक सर्वसमावेशक कानून की आवश्यकता है। कल्याणकारी योजनाओं के लिए समुचित फंड देना चहिए। बजट में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी कार्यो के लिए पर्याप्त धन का प्रावधान रखना चहिए।

महिला कर्मचारी –

महिला कर्मचारी त्याग का एक प्रतीक है। उनके काम के अधिकार को भी महत्व पूर्ण माना जाना चाहिए।

हाल की ज्वलन्त समस्याऐं –

सरकार ने सरकारी कर्म चारियों के लिए छठे वेतन आयोग गठन करने हेतु अभी तक कोई निर्णय नही लिया है। सार्वजनिक प्रतिष्ठान के कर्मचारियों तथा बैंक कर्मचारियों का वेतन पुर्ननिधारण भी अभी रुका पड़ा है। टेलीकाम, विमानन्, बीमा क्षेत्र तथा अन्य कई संस्थानों मे विदेशी पूंजी निवेश से कर्मचारियों में अस्थिरता की स्थिति है। सी.आर.एस. एवं वी. आर. एस. द्वारा कर्मचारियों को काम छोड़ने हेतु मजबूर किया जा रहा है प्रबन्धकों का सरकार पर दबाव है कि औद्योगिक अधिनियम की धारा 5 बी को निकाल दिया जाए।

भारतीय मजदूर संघ के कार्यकार्ताओं को देखकर ऐसे नये क्षेत्र की खोज करनी होगी तथा वहां यूनियन बनाकर अपना झंण्डा फहराना होगा। भारत एक देश ही नही अपितु अपने आप में एक विश्व है, यहां अनेक भाषाऐ है, प्राकृतिक सौंदयर्ता है, खुब साधन है तथा वर्षा पुरानी संस्कृति आज भी कायम है। तथा हमारे वैज्ञानिकों तकनीकि योग्यता भी इतनी है कि वे भारत को सच में सुपर पावर बना सकते है।

उपसंहार

स्वदेशी, स्वाभिमान, स्वधर्म का नारा सैकडों करोडों भारतीय जनता तक, भारतमाता के हर सुपुत्र तक पहुँचाना भा.म.संघ का स्वप्न है। अपने कार्यक्षेत्र में सच्ची लगन से काम करने के लिए सारे कार्यकर्ता वचनबद्ध है। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, पतत्वेश कार्यो नमस्ते नमस्ते' इस उक्ती को सबने अपने जीवन में अहम् स्थान दिया है।

हमें पूरा विश्वास है, कि भा. म. संघ के संस्थापक श्रद्धेय ठेंगडी जी एवं कई अन्य मार्गदर्शक आज हमारे बीच में न होते हुए भी मन से आशीर्वाद दे रहे है। उनका अब तक मिला मार्गदर्शन, आशीर्वाद हमें सफलता के ऊँचे मकाम तक जरूर ले जाएगा।

यह प्रतिवेदन बनाने में जिन्होंने भी मुझे सहयोग दिया है उनको धन्यवाद देते हुए मैं भाषण का समापन करता हूँ।

दिल्ली — **उदय पटवर्धन**

दि. 3 अप्रैल 2005 — **महामंत्री**

'वंदे मातरम' 'भारत माता की जय'

परिशिष्ठ 1

प्रदेश व उद्योगों का प्रतिवेदन

प्रदेशों से व उद्योगों से मिले हुवे संक्षिप्त वृत्त का अंतर्भाव इस संकलन में किया गया है।

अण्डमान निकोबार द्विप समुह

भारतीय मजदूर संघ अण्डमान निकोबार द्विप समुह का गठन 25 नवंबर 2000 को किया गया। प्रांतिय कार्यालय एबरडीन मार्केट पोर्ट ब्लेअर में है। इस प्रदेश के दो जिल्हे है। एक अण्डमान और दुसरा निकोबार। भा.म.संघ से संबंधित 8 संगठन प्रदेश में काम कर रहें हैं। और 2002 के आधार पर सदस्यता 1346 है। नये 2 युनियन बने है किंतु पंजीयन नहीं हुवा है।

वर्ष 2003 में अ.भा. संगठन मंत्री मा. रामप्रकाशजी का पाँच दिवसीय प्रवास द्विप समुह में हुआ।

वर्ष 2003 और वर्ष 2004 के जनजागरण अभियान, स्थापना दिवस, एवं विश्वकर्मा दिवस मनायें गये। वर्ष 2003 में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक एवं शिक्षा वर्ग हुआ।

2005 के त्सुनामी लहर के संकट में भा.म.संघ के कई कार्यकर्ता घायल हुऐ। किन्तु साहस का परिचय देते हूए कार्यकर्ताओं ने राहत कार्य शुरु किया एवं आज भी सेवा भारती के माध्यम से सभी कार्यकर्ता सेवा कार्य में जुडे हुए है।

आंध्र प्रदेश

8, 9 एवं 10 फरवरी 02 को भा.म.संघके अ.भा. अधिवेशन में थिरुवानंतपुरम मे प्रदेश के 355 प्रतिनिधी थे। 8 मार्च 02 को विशाखापट्टनम में विश्व महिला दिवस का आयोजन हुवा।

17–18 अप्रैल 02 सर्व पन्थ समादर मंच का अ.भा.अधिवेशन हैदराबाद में हुआ। श्रद्धेय ठेंगडीजी, श्री अख्तर हुसैन एवं श्री उदयराव पटवर्धन जी ने मार्गदर्शन किया। (230)

25/2 से 29/2/02 भा.म.संघ के कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी मेले में सहयोग दिया।

29/9/02 विजयवाडा में भा.म.संघ एवं भा. किसान संघ की संयुक्त सभा हुई जिसमें श्री वेणुगोपाल एवं श्री सुब्बारावजी ने मार्गदर्शन दिया। उपस्थिती 6500 रहीं। 2/10/02 मे हैदराबाद में ऐसी ही साँझा सभा हुई जिसमें 12000 की उपस्थिती रही एवं पं. रामप्रकाशजी का मार्गदर्शन हुआ। उसी प्रकार दि.16/09/02 को सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान बंद रहें एवं वैश्विकरण के विरुद्ध 1/9/02 से 15/09/02 को प्रदेश के सभी जिलो में संगोष्ठी का आयोजन हूआ।

वर्ष 2002 में खेतिहर मजदूर, ठेका श्रमिक, हमाल आदी संगठीत क्षेत्र के श्रमिकों के प्रादेशिक अधिवेशन हूए। उसी प्रकार नगर परिषद, एन.जी ओ परिषद, ए.पी मेडीकल और हेल्थ मजदूर संघ, आदी महासंघो के प्रादेशिक अधिवेशन संपन्न हूए।

15/16 फरवरी के दो दिनों मे प्रदेश भा.म.संघ का 13 वा अधिवेशन संगारेड्डी (मेदक) में संपन्न हूआ। 1300 प्रतिनिधि थे। मा. वेणुगोपाल, मा.पी.टी.राव, ने संबोधन किया। रेल राज्यमंत्री श्री बंडारु दत्तात्रय, प्रदेश श्रममंत्री बाबू मोहन अतिथि थे। आंगनवाडी महिलाओं की अधिवेशन खम्मम में दि.29/02/03 को संपन्न हुआ। उपस्थिति 500 थी। श्री सुब्बाराव जी एवं सुश्री सुचित्राजी ने मार्गदर्शन किया।

7/3/03 को ए.पी.राईस मिल मजदूर संघने हैदराबाद में उद्योग की समस्याओं को उजागर करने हेतू रैली एवं आमसभा का आयोजन किया। 2500 श्रमिक उपस्थित थे। ए. पी स्टेट रोड ट्रांन्सपोर्ट ने हैदराबाद मुख्यालय पर कर्मिकों की समस्यां को लेकर दि. 17/03/03 को प्रदर्शन किया। उपस्थिती 500 थी। लीगल सेल के बेंगलूर कार्यशाला में आन्ध्र के 8 कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया।

23 जुलाई से 9 अगस्त 03 तक हुए आंदोलन एवं प्रदर्शन कार्यक्रम प्रभावी रहें। 648 ग्रामो में सभायें हुई एवं 1 लाख दस हजार परचे बाटें।

इ.पी.एफ के व्याज दर के बढ़ोतरी की मांग के लिये पुरे प्रदेश में दि. 20/9/03 को प्रदर्शन दिया। 14/09/03 डेयरी मजदूर का प्रादेशिक अधिवेशन श्रीशैल्यम में हूआ। (250) ठेला मजदूर एवं सब्जी विक्रेता संघ अधिवेशन हैदराबाद में (300)ऑटो (300), एवं सायकल रिक्षा (300) श्रमिकों को संघ द्वारा बिमा योजना प्रदान।

20,21 दिसंबर 03 को हैदराबाद मे लीगल सेल का प्रभावी एवं सफल कार्यक्रम हूआ। केन्द्रीय श्रममंत्री डॉ. साहिबसिंहजी, अ.भा.अध्यक्ष हसुभाई दवेजी उपस्थित थे। पिछले तीन

वर्षो में निम्न इकाईयों के चुनाव में सफलता प्राप्त हुई है। शिरपूर पेपर मिल, कागझनगर, प्रिमियर पेपर मिल, सिमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडीया, तांदूर, प्रिमियर मश्रुम फार्म, मेदक, हिंदुस्थान शिपयार्ड, विशाखापट्टनम जीत हूई। एवं प्रतिरक्षा के डी एल आर एल ने वर्क्स कमेटी के 8 सीटे जीते है।

पिछले तीन वर्षो में प्रदेश में – हैदराबाद, – अल्वीन ऑटो, अल्वीन वॉच आदी सार्वजनिक उपक्रम बंद हूवे। एवं कुछ चीनी मिलें एवं टेक्सटाईल मिलें बंद हूई या निजीकरण हुआ।

नये सरकार ने भी घोषणा की है की वह कुछ ओर उपक्रम बंद करेगी। इन सब स्थानों पर भा.म.संघ संघर्षरत है। ठेका श्रमिकों का एक केस डिफेन्स क्षेत्र में जितने के बाद ठेका श्रमिकों का धैर्य बढा हैं व वे संगठीत हो रहें है।

पूर्वोत्तर

(अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपूर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड़, त्रिपुरा)

असम एवं पूर्वोत्तर राज्यो में भा.म.संघका काम गती से बढ रहा है। 2002 मे मणिपूर एवं मिजोरम मे काम फैल गया है।

आंदोलन के बाद मणीपूर सरकार से आंगनवाडी महिलाओं का मान देय रु. 100/– एवं सहायीका के लिये रु. 50/– बढवाया। एवं मणिपूर स्पिनींग मिल्स के श्रमिकों को 50 माह के लॉक आऊट का वेतन दिलवाया।

स्थापना दिवस के सिलचर में तीन कार्यक्रम हुए। 23/07/2002 को सभा (150), 30/07/2002 की सभा (250),एवं 7/08/2002 की सभा (500)। केंद्रीय कार्यक्रमो की कड़ी मे प्रादेशिक प्रदर्शन कार्यक्रम 30/09/2002। गुवाहाटी एवं 02/10/2002 सिल्चर मे संपन्न हुए। श्री. एम. पी. पटवर्धन प्रमुख वक्ता थे। प्रदर्शन प्रभावी रहा, एवं काफी प्रचार भी हुआ।

3, 4, 5 मई 2003 – त्रैवार्षिक अधिवेशन, बी.आर.पी.एल. कॉम्प्लेक्स बोगईगांव(300) में हुआ। पं. रामप्रकाशजी एवं उदयरावजी ने संबोधन किया। महिलाओं की प्रभावी उपस्थिती रही। 2003 के स्थापना दिन के उपलक्ष्य में दो आमसभाओं का आयोजन सिल्चर

में 23 संगठनों ने स्थापना दिवस मनाया।

एम्फाल (मणिपूर) में 17/08/2003 को सभा हुअी। (4000), चौरचांदपूर की सभा 18/08/2003 को हुअी। (500), 17/08/2003 –इम्फाल– धरना– आंगनवाडी –मणिपूर। 07–08 सितंबर 2003 –एच.पी.सी. धरना– विनीवेशके खिलाफ। दिसंबर 03 –एन.एच.पी. सी. –लोकतॉक –300 श्रमिक निष्कासीत – विवाद ट्रिब्युनल में।

जुलाई 2004 –पूर्वोत्तर प्रदेशों की संयुक्त बैठक । असम मे कई नये संघटन बन रहे है और काम बढ रहा है। नये संगठन – करिमगन्ज शिक्षक संघ, मणिपूर, पान विक्रेता सिलचर, पोर्टर्स मजदूर संघ। चाय बगानो मे श्रमिकों की वेतन, काम उपलब्धी, ठेका आदी समस्याएँ गंभीर हो रही है। एवं अपने आंदोलन जारी है। चाय बगान के ट्रिन्ब्युनल के 3 फैसले श्रमिकों के पक्ष मे आए। एवं 3 वेतन समझौते हुए है। तब से चाय बगानो का काम बढ रहा है। स्थापना दिवस के कार्यक्रम 23–7–04 से एक सप्ताह मे 30 स्थानों पर हुए है। औसत उपस्थिती 200 रही है। असम प्रदेश मे सर्व पन्थ समादर मंच की स्थापना हुई है।

बिहार प्रदेश

बिहार के विभाजन के बाद 36 जिलो में से 26 जिलो में इकाइयाँ बनी है। बिहार की औद्योगिक स्थिति खराब है। तथा कई इकाईयाँ बरसों से बंद स्थिति में है। भ्रष्ट एवं निकम्मे प्रादेशिक सरकार के चलते उद्योगों की हालत गंभीर है। परिवहन निगम पुरा ठप्प पडा है। बिजली, बैंक, बीमा, आंगनवाडी, पोस्ट, एन टी पी सी, आदी उद्योगों में फिर भी प्रभाव बना है और काम बढा है।

केन्द्रीय कार्यक्रम के तहत 16 अप्रैल को बिहार के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक बीमा उद्योग एवं सार्वजनिक क्षेत्र पुरे बंद थे। इसी कडी के अगले चरण में बिहार में सितंबर एवं अक्तुंबर में भा.म.संघ, किसान संघ, एवं स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हूए। यात्राऐं निकली एवं आम सभाए, ग्रम संपर्क आदी अभियान हूए।

दि. 02/10/02 को पटना में पूरे प्रदेशसे 5000 श्रमिकोने सॉझा कार्यक्रममें सहभाग दिया। कार्यक्रमको बैजनाथ रायजी (अ.भा.मंत्री) ने संबोधित किया। बेरोजगारी, वैश्वीकरण की समस्याओ को उजागर किया गया।

दि. 26/04/03 को दरभंगा में प्रदेश का त्रैवार्षिक अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में पं. रामप्रकाशजी एवं श्री. बैजनाथ रायजी उपस्थित थे। अधिवेशन में प्रादेशिक उद्योगों की बदहालत पर प्रस्ताव हूए है। दि. 23 जुलाई 03 (स्थापना दिन) से 9 अगस्त 03 (भारत छोडो दिवस) के पखवाडे में प्रदेश में श्रमिकों की समस्याएं लेकर 12 स्थानों पर धरने, रैली, प्रदर्शन हूए। कुल 15000 श्रमिकों ने सहयोग दिया। 09/08/03 को जिला मुख्यालयों पर डब्लु.टी.ओ.के विरोध में धरने हूए।

दि.23–25 जून 03 को पटनामें प्रदेश स्तरीय अभ्यास वर्ग असंगठीत क्षेत्रका हूवा। दि. 15/11/03 को भागलपूर में प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता वर्ग हूवा।

दि.19/20 जून 04 को बिजली उद्योगके महासंघका प्रादेशिक अधिवेशन पटनामें संपन्न हूवा। (175)

आंगनवाडीका प्रदेश स्तरीय महासंघ बन गया है तथा 22 फरवरी 04 को समस्तीपूर में महासंघका अधिवेशनभी संपन्न कराया गया है। 2004 मे एन टी पी सी कहलगाँव के चूनाव हूए जिसमें अपना संगठन विजयी हूआ है।

छत्तीसगढ

प्रदेश के 16 जिलों मे सभी स्थानों पर अपनी इकाईया बनकर सूचारु काम कर रही है। असंगठीत क्षेत्र, बनवासी क्षेत्र, आंगनवाडी निर्माण, दैनिक वेतनभोगी आदी क्षेत्रो मे काम बढ रहा है। एवं राज्यशासकीय, बिजली, परिवहन, बालको, एनटीपीसी, रेल, कोयला उद्योगो में काम गती से बढ रहा है। सबसे तेज बढत कोयला उद्योग के संघटन ने प्राप्त की है। तिरुअनंतपुरम के अधिवेशन के बाद प्रदेश मे काम बढाने के अथक प्रयास हुए है।

23 जुलाई 2002 से ग्रामसभा, प्रवास, जुलूस, पर्चियाँ बाँटना आदि कार्यक्रमो द्वारा डब्लु.टी.ओ. वैश्विकरन, बेरोजगारी इन समस्याओ पर पूरे प्रदेश मे जनजागरण का काम हुआ । मई 2002 को रायपूर मे कडकती धूप मे असंगठीत क्षेत्र का प्रदर्शन हुआ। तब से 2 अक्तूबर 02 की अंतिम सभा तक यह सहयोग बढता गया। भा.म.संघ, भा. किसान संघ एवं एस.जे.एम. के साँझे कार्यक्रम मे रायपूर मे 02–10–02 को हजारो श्रमिकों ने अपनी आवाज बुलंद की। मा. रमणभाई शाह पूर्व अध्यक्ष ने संबोधन किया।

18–19 जनवरी 03 को स्वायत्त शासी महासंघ की स्थापना एवं अधिवेशन रायपूर में

संपन्न हुआ। एवं आंगनवाड़ी महिला सम्मेलन 19–5–03 को प्रदेश मे हुआ। 600 की अच्छी उपस्थिती रही। भा.म.संघ प्रदेश का त्रैवार्षिक अधिवेशन 17–18–19 मई 03 को कोरबामें संपन्न हुआ। (650) दि. 23 जुलाई 2003 से 9 अगस्त 2003 के दिनों मे सैकडो सभाएँ हुई। दि. 12 दिसंबर 03 को बाबू गेनू स्मृती दिन के चार कार्यक्रम प्रदेश मे हुए।

इन प्रयासों से प्रदेश मे वनवासी कृषी श्रमिक, भारतीय संविदा मजदूर महासंघ, मेडिकल रिप्रेझेंटेटीव्ह संघ आदी नये महासंघ भी बने है। बिजली निजीकरन विरोधी धरना रायपूर मे 14–04–04 को हुआ। 4–06 को एनटीपीसी मे द्वारसभा हुई। दि. 22–7–04 को बालको मे भा.म.संघ के नेतृत्व मे सफल हडताल हुअी है। बालको विनिवेश के खिलाफ आज भी आंदोलन चल रहा है। भारतीय श्रम परिषद मे बालको समस्या को उजागर करने वाली पर्चिया भा.म.संघ ने बँटवाई। 13/08 को इ.इ.सी.एल. कोयला कंपनी के 6000 कार्मिकों की रैली एवं धरना किया। दि. 20/09/04 को जिला मुख्यालयों पर माँगपत्र एवं धरने के कार्यक्रम प्रभावी हुए है। 1 जुलाई 04 को रायगढ़ मे शिक्षा वर्ग संपन्न हुआ (70) इसी प्रकार जुलाई 04 मे आंगनवाड़ी के और दो वर्ग संपन्न हुए विश्रामपूर (80), भिलाई (30) प्रदेश मे कोयला एवं एन. टी. पी. सी. के दो वर्ग संपन्न हुए है। भा.म.संघ की 106 वी केंद्रीय कार्यसमिती बैठक दि. 21/22 फरवरी 05 को रायपूर मे संपन्न हुई है।

दिल्ली प्रदेश

गत् 3 वर्ष (2002–03–04) दिल्ली प्रदेश द्वारा स्वर्ण जयन्ती वर्ष में होने वाले 14 वें अखिल भारतीय अधिवेशन की तैयारी में बीते, तो भी प्रदेश में यूनियनों द्वारा भी अनेकों अच्छे प्रभावी कार्यक्रम / आंदोलन किये गये। लेकिन जिन आंदोलन एवं कार्यक्रमों ने अपनी कोई विशेष छाप छोडी एवं उपलब्धि प्राप्त की लगभग ऐसे ही कार्यक्रम इस प्रकार है :

वर्ष 2002

- 14 जनवरी को डीटीसी के कार्यकर्ताओं ने संस्थान की सदबुध्दि के लिए आई.पी. मुख्यालय पर महायज्ञ का आयोजन किया। (3000)
- 18–19 जनवरी को 13 कार्यकर्ताओं ने स्कूटर यात्रा करके आगरा में हुई स्वदेशी जागरण मंच के सम्मेलन में भाग लिया।

- भा.म.संघ के 13 वें राष्ट्रीय अधिवेशन में दिल्ली से 98 कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्रम में भाग लिया। 14 मार्च को दिल्ली में इंटक को छोडकर सभी केन्द्रीय श्रम संगठनों का आंदोलन हुआ। (400) 16/04/02 को सार्वजनिक क्षेत्र की हडताल के समर्थन में जंतर मंतर पर धरना दिया। (350) डी टी सी के कार्यकर्ताओं ने एक दिन का धरना दिनांक 21 जून को आई पी मुख्यालय पर दिया। (3500) 22 जून को डेसू मजदूर संघ का निजीकरण के विरोध में जंतर मंतर पर धरना। (800)
- 15/7/02 से दैनिक भोगी कर्मचारीयों की मांगो को लेकर क्रमिक अनशन आई पी मुख्यालय पर 31 दिन चलकर 22/8/02 को समाप्त हुआ। 22/8/02 से ही अनिश्चित्कालीन भूख हडताल शुरु हुई जो कि मांगो को सफलतापूर्वक मनवाने के उपरांत 46 दिन (1104घंटे) चलकर दि. 7/10/02 को समाप्त हुई। दिनांक 19/7/02 को डीटीसी के 2000 कार्यकर्ताओं की विशाल रैली तथा 1/08/02 को 5000 कर्मचारियों ने केवल कच्छा पहनकर जुलूस निकाला।
- 25/9/02 को स्वदेशी जागरण मंच तथा भा.किसान संघ के साथ विशाल रैली हुई। कार्यक्रम 23 जुलाई से प्रारंभ हुआ तथा इस मध्य कुल छोटी.बडी 62 सभाएं संपन्न हुई।
- 18/10/02 को ग्रुप 4 वेलफेअर कर्मचारी संघ का विशाल धरना। (2000)
- 12/12/02 को एन ओ बी डब्ल्यू के 1500 कार्यकर्ताओं ने ओ बी सी कनाट प्लेस शाखा पर प्रदर्शन किया।

वर्ष 2003

- 4 फरवरी 03 को भारत सरकार को धन्यवाद देने प्रधानमंत्री निवास पर लगबग 1200 महिला कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ।
- 9 फरवरी 03 को भा.म.संघ, दिल्ली प्रदेश का त्रैवार्षिक अधिवेशन केन्द्रीय कार्यालय के भवन निर्माण स्थल, दिनदयाल मार्ग पर संपन्न हुआ। (200)
- 27 फरवरी 03 को एनडीएमसी कर्मचारी श्रममंत्री भारत सरकार से मिलें।
- दि. 1/1/03 से शुरु होकर 47 दिनों तक दि.न.नि.सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगो को लेकर धरना दिया।
- दि. 29 अप्रैल को स्वदेशी जागरण मंच के साथ दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने राजघाट से राजघाट तक संघर्ष यात्रा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 125 दुपहिया वाहनों पर कार्यकर्ता सवार थे।

- दि. 8 जुलाई को दिल्ली की आंगनवाडी कर्मचारियों ने राजघाट से दिल्ली सचिवालय तक प्रदर्शन एवं धरना दिया। (600)
- दि. 23 जुलाई से 9 अगस्त तक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। दिनांक 7 अगस्त को दिल्ली के सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिन का धरना प्रदर्शन हुआ। (400)
- दि. 2 सितंबर को स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित डब्लु.टी.ओ. के विरुद्ध महाधरना में 2800 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

वर्ष 2004

- 27 फरवरी 04 को वित्त संस्थाओं के 200 कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के विरुध्द आई टी ओ सचिवालय पर विशाल प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन, होली, जन्माष्टमी तथा रामनवमी की छुट्टियां समाप्त करने के विरोध में किया गया था।
- 16 मार्च को दिल्ली जलमल कर्मचारी संघ ने उपराज्यपाल, दिल्ली को ज्ञापन दिया तथा 13 अप्रैल को जंतर मंतर पर सद्बुद्धि महायज्ञ किया। 28 अप्रैल को दिल्ली जलमल कर्मचारी संघके तत्वाधान में आईटीओ तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया।
- दि 10/3/04 से 27/4/04 तक डीटीसी के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगो को लेकर आंदोलन छेडा। प्रबंधनने 50 प्रतिशत डी.ए. मर्जर का आदेश तो तुरंत ही लागू कर दिया।
- दि. 1 जून से 21 जून तक 21 दिनों की 3500 किलोमीटर की यात्रा ग्रुप 4 स्टॉफ वेलफेअर कर्मचारी संघ के 21 कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकलो पर की।
- डीटीसी प्रबंधन ने अपनी मनमानी करते हुए कर्मचारियों से जबरन 23.31 रु. वेतन से काटने के आदेश किये जिसका संघ ने पुरजोर विरोध किया। 17228 कर्मचारियों ने विरोध पत्र भरें, फलस्वरूप प्रबंधन को यह आदेश वापिस लेना पडा।
- दि. 21 अगस्त को ग्रुप 4 सिक्योर्टाज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों व प्रबंधन के बीच एक शानदार समझौते के तहत यूनियन की मान्यता तथा उनकी अन्य मांगो को माना गया।
- 26 अक्तुंबर 04 को एमटीएनएल मे युनियन की मान्यता हेतू मतदान हुआ। एमटीएनएल कर्मचारी संघ इस चुनाव में विजयी रहा।

गोवा प्रदेश

1. भा.म.संघ गोवा प्रदेश का काम मार्च 1989 मे शुरू हुआ। पोंडा मे जब पहला अधिवेशन हुआ तब सदस्यता 400 थी।
2. तब से अब तक काम बढकर पहले क्रमांक पर आया है। 18 पंजीकृत संगठन है एवं 2002 तक 76870 सदस्यता है। पिछले तीन वर्षो मे हिंदुस्थान लीवर अॅडव्हान्स ओरल केअर, ग्लेन्मार्क फॉर्मा, बेटस् इंडिया, वेरणा आदी नये संगठन बनाए है।
3. वामपन्थी संगठनों को छोडकर कुछ संगठन भा.म.संघ से जुड गये है। जैसे जेनो लॅब एम्प्लॉ. युनियन, अॅडेल लॅब एम्प्लॉ. युनियन, जीएएआई वर्कर्स युनियन, नेवलसिव्ही, एम्प्लॉ. युनियन.
4. शेतकरी कामगार संघ के रूप मे असंगठीत क्षेत्र मे काम का विस्तार हुआ है। 46 गावों से 2500 किसानों ने राजधानी पणजी मे दि.15–12–2003 को प्रदर्शन दिया। रेली मे मुख्यमंत्रीजी का संबोधन हुआ। सरकार ने किसानों की जमीन उन्हे वापस करनी चाहिये, यह माँग सरकार ने मानी है। विवाद सर्वोच्च न्यायालय मे लम्वित है।
5. कुछ महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ एवं समझौते निम्नप्रकार से है।

   अ) सितंबर 2003 मे दामोदर अॅण्ड कंपनी से समझौता हुआ (1850/– से 950/– प्रतिमाह)

   ब) रॅनबक्सी कंपनी ने 3 वर्षके लिये 2150/– प्र.म. का समझौता 3 वर्ष के लिये किया।

   क) माण्डवी पॅलेटस् कंपनी जो सितंबर 02 मे बंद हुअी थी, वह फिर से दिसंबर 03 मे खुलवाई। 1850 से 1150/– वेतनवृद्धी का समझौता हुआ।

   ड) पेंग्वीन अल्को प्रा. लि. कारखाना जो 2001 से बन्द था, नवंबर 04 से फिर खुलवाया समझौता हुआ।

   इ) पंचाट द्वारा सात श्रमिकों को नौकरी फिर से बहाल हुअी।

   फ) दामोदर मंगलजी खदान युनिट सीटू को छोडकर भा.म.संघ से जूड गया।

गोवा के सभी तहसीलो मे एवं प्रमुख सभी उद्योगो मे जैसे खदान, इंजिनिअरींग, टेक्स्टाईल, एस.एस.आय., औषधी, पोर्ट, किसान, इलेक्टनॅनिक्स मे भा.म.संघ का अग्रणी काम है।

गुजरात प्रदेश

गुजराथ कुल 19 जिले है। जिनमे से 17 जिलो मे अपनी समिती गठीत है। असंगठीत एवं संगठीत दोनो क्षेत्रो मे काम पिछले 3 वर्षो मे गती से बढा है। स्वायत्तशासी, परिवहन, बिजली, बीडी, आंगरीयाँ, आंगनवाडी आदी कुछ कामो मे प्रदेश ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदेश का अधिवेशन 19 जनवरी 2003 को राजकोट मे संपन्न हुआ। (536) स्वामी नारायण पन्थ के प्रमुख स्वामीजी ने उद्घाटन किया। रोजगार की योजना की माँग करने वाला मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया।

2003 के वर्ष मे कार्य विस्तार के विशेष प्रयास से प्रदेश मे नये संगठन बने है। जैसे माधव फूड, एल.जी.एम., मॉडर्न पेटन फाईल्स, ठेका मजदूर, वडोदरा, एअरपोर्ट, ज्वेल ब्रेशेस आदी. बीडी महिला आदि संगठन भी बन रहे है।

भा.म. संघ के स्थापना पखवाडे मे 14 कार्यक्रम 2003 मे हुए। सबसे बडा कार्यक्रम वडोदरा मे हुआ जिसमे धरना रैली एवं प्रदर्शन किया गया। वैश्विकरन एवं डब्ल्यू.टी.ओ. के विरुद्ध जनजागरण किया गया।

12 दिसंबर को स्वदेशी दिवस मनाकर पाँच कार्यक्रम किये गये। 1600 की उपस्थिती रही। महिला होमगार्ड का शिक्षावर्ग किया गया।

2004 मे भा.म.संघ के अनेक प्रदर्शन के कार्यक्रम हुए। दि. 18–5–04 को परिवहन कार्यकर्ता द्वारा अहमदाबाद मे प्रदर्शन किया गया। दि. 20–5–04 को बिजली उद्योग का प्रदर्शन राजकोट मे हुआ। 11–9–04 को वेरावल मे रेऑन इंडस्ट्री के श्रमिकों की समस्या को लेकर प्रदर्शन हुआ। 16–9 को आंगनवाडी महिला श्रमिकों का विशाल प्रदर्शन वडोदरा मे संपन्न हुआ। बिजली महासंघ का अधिवेशन भावनगर मे संपन्न हुआ।

सुरक्षा एवं पर्यावरण मंचके कार्यक्रम वडोदरा, अम्बाजी, अंकलेश्वर एवं हिम्मतनगरमे हुए है।

प्रतिवर्ष जुनागढमे होनहार बच्चोंको सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम होता है, एवं विशेष सहायता दी जाती है।

हरियाणा

हरियाणा के कुल 19 जिले है। उसमे 15 जिला समितीयाँ काम कर रही है। पिछले तीन वर्षों मे प्रदेश मे काफी प्रभावी प्रदर्शन भी हुए है। तथा नये संगठन भी काम मे जूडे है। असंगठीत क्षेत्र जैसे भवन निर्माण, अनाजमण्डी, राजमिस्त्री, लकडी उद्योग नये से जुडे है। आंगनवाडी का काम भी प्रभावी बना है। इसी के साथ बैंक, बीमा, ग्रामीण बैंक, आदि क्षेत्रों मे भी नया काम शुरू हुआ है।

14 अप्रैल 02 से स्वदेशी संपर्क यात्रा प्रदेश मे शुरु हुअी। जो दो माह तक चली, एवं पुरे प्रदेश मे सभी प्रमुख स्थानों पर गावो, कसबो मे पहुँची। जिसमे भा.म.संघ का काफी योगदान रहा। 26 सितंबर 02 को चंड़ीगढ मे 15000 कार्मिक एवं मजदूरो ने वैश्विकरन के विरुद्ध और रोजगारकी माँग के लिये भारी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन मे बडी संख्या मे महिलाएँ थी। स्व. राजकिशन भगतजी ने मार्गदर्शन दिया ।

वर्ष 2003 मे भी इसी प्रकार से प्रभावी कार्यक्रम हुए। 30 अप्रैल 03 को चंडिगढ मे महिलाओं का भारी प्रदर्शन हुआ। जिसमे 11 जिलोंसे 3200 बहने शामिल हुअी। चौटाला सरकार की श्रमा विरोधी नीति की निंदा की गयी।

25 जून 03 को अम्बाला मे ओरिएन्टल इन्शुरन्सका प्रभावी कार्यक्रम हुआ।

स्थापना दिन के पखवाडेके कार्यक्रम पुरे प्रदेश मे अत्यंत प्रभावी हुए। 15 जिलो मे कार्यक्रम हुए। 105 बैठके भी हुअी। ग्रामस्तरीय 50 कार्यक्रम हुए। 2003 मे प्रदेश का त्रैवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। 2 सितंबर 03 की दिल्ली रैली मे 2000 श्रमिक रहे।

वर्ष 2004 मे कई आन्दोलन सफल हुए। बहादूरगढ में हिंदुस्थान वायर्स कंपनी मे इंटक के श्रमिक विरोधी समझौते के विरुद्ध 8 जून 04 से दस दिन की हडताल हुअी। समझौता निरस्त हुआ एवं श्रमिक हितैषी समझौता हुआ। दि. 20–5–04 को डाक सचिव का घेराव अम्बाला मे हुआ। माँगे मानी गयी। फरीदाबाद मे 20–5 से 2 जून तक न्युकॅम कंपनीमे हडताल हुअी। समझौते के बाद हडताल वापस हुअी। करनाल मे 20 स्पिनींग मिलो मे 1 जून से 8 जून तक सफल हडताल हुअी। माँगे मानी गयी। हजारो श्रमिक सहभागी हुए।

2004 के स्थापना दिवसपर पुरे प्रदेश मे माँग पखवाडा मनाया धरने, जुलूस, प्रदर्शन किये गये। कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद एवं हिसार मे जुलूस हुए। मिनी बैंक कर्मियोंके आंदोलन मे

राज्यसरकार को हजारो निषेध पोस्ट कार्ड भेजे गये, काली फिता लगाई गयी ।

विश्वकर्मा जयंती राष्ट्रीय श्रम दिवस पर प्रदेश मे 17 स्थानों पर सर्वसाधारण माँगो को लेकर धरने दिये गये।

28–9 को आंगनवाडी महिलाओंका विशाल धरना हुआ। जिसमे 2000 बहने रही । पंजाब नॅशनल बैंकमे 400 नये सदस्य बने।

हिमाचल प्रदेश

प्रदेशके 12 जिलोमें से 10 जिलो की विधीवत कार्यसमितीयाँ गठीत है। शेष में कार्यचल रहा है। पिछले तीन वर्ष की कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकारसे है।

14 मार्च 02 को शिमला में विधानसभा पर सभी संघटनों को लेकर साँझा प्रदर्शन। 16/4/02 को केंद्रीय योजनानुसार सार्वजनिक क्षेत्र पुरा बंद कराया।

प्रादेशिक सरकार से बात करके 23 जुलाई को 1148 पदपर, 17 सितंबर 02 को 1291 पदपर, 06 फरवरी 03 को 2072 अस्थायी श्रमिकों को प्रदेश में स्थायी कराया है। 10 अक्तुं 02 को मुख्यमंत्रीजी से प्रदर्शन के बाद वार्ता हूई, और शेष समस्याओं को निपटाया गया। जिससे सरकारी उपक्रमों मे कूल 30000 कार्मिक स्थायी हूए।

13/14 अप्रैल 03 को प्रदेश का अधिवेशन सोलन में हूआ (200) 14 जुलाई 03 को प्रदेश महामंत्री एवं प्रदेश वित्तमंत्री को नयी प्रादेशिक सरकार ने द्वेवशपूर्ण भावना से सरकारी विभागके नौकरी से 6 माह तक निलंबीत किया। किन्तू सच्चाई समाने आयी और सरकार को फिर से दोनो का निलंबन वापस लेना पड़ा।

आंगनवाडी महिलाओं के मानधन वृद्धी में प्रादेशिक सरकार ने कटौती करी। उसके विरुद्ध 1000 महिलाओंका 2 सितंबर 03 को शिमला में प्रदर्शन हूआ।

11 जून 04 को कोलडॅम संगठन के महामंत्री पर हमला हूआ। बाद में माँगो को लेकर 14/7 से 25 दिन तक हडताल चली। एन.टी.पी.सी. सरकार एवं अन्य संगठनों ने सॉझा मोर्चा बनाकर कूचलने का पूरा प्रयास किया गया। किंतू संगठन अडिग रहा। अक्तु 04 को कांगडा में 154 एवं बिलासपूर में 45 मजदूरो की छटनी आंदोलन के बाद रोकी। संगठन बढा।

मण्डी के निजी दंतवैद्यक माहविद्यालय के कार्मिकों ने 97 दिनों की हडताल की, महामार्ग पर धरना दिया। जिलाधीश हस्तक्षेप से माँगे मिली आंदोलन वापस हूआ।

2004 मे शिमला में प्रदेश का नया कार्यालय बना है।

जम्मू–कशमीर प्रदेश

प्रदेशमे 14 जिले है और सभी जिलो मे काम है, पिछले तीन वर्षो मे प्रभावी आंदोलन हुए तथा काम लगभग दुगुना हो गया है।

वृत्त 2002

1 आंदोलन :

सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों पर दि. 25–9 से 2–10–02 के काल मे रैलीज हुअी, और सरकार के श्रमिक विरोधी नितीयों को स्पष्ट किया गया। कुल पांच हजार श्रमिकों ने सहभाग दिया।

2 अधिवेशन :

भिलवाडा वर्कर्स युनियन, सिंगवी वूड वर्कर्स युनियन, तावी बिस्कुट वर्कर्स युनियन, उत्तम प्लास्टिक वर्कर्स युनियन, त्रिवेणी पेन्सील वर्कर्स युनियन के अधिवेशन हुए। एक हजार श्रमिकों ने सहभाग दिया। श्रीनगर मे अप्रैल 2002 मे बी.एस.एन.एल. मजदूर संघ की सर्कल कॉन्फरन्स हो गयी।

3 21 जुलाई 02 को जम्मू जिला अधिवेशन हुआ। 4. ग्रामिण बैंक अधिकारी संगठन की सर्वसाधारण सभा संपन्न हुअी। 5. फिल वर्कर्स युनियन पंजीकृत हुअी। भारत स्माल आर्मस् वर्कर्स युनियन यह पुराना संगठन भा.म.संघ से संबद्ध हो गया। 6. स्थापना दिवस एवं विश्वकर्मा दिवस के कार्यक्रम हुए।

वृत्त 2003

1 भा.म.संघ जम्मू कश्मिर प्रदेश का त्रैवार्षिक प्रादेशिक अधिवेशन 20–4–03 को जम्मू मे संपन्न हुआ। 300 प्रतिनिधी थे। जिसमे 40 बहने थी।

2 स्थापना दिवस से भारत छोडो दिवस के काल मे प्रदेश मे 20 स्थानोंपर कार्यक्रम हुए। 50 से लेकर 200 तक संख्या थी। रैली, रोड शो, बैठके द्वार सभाएँ ऐसे कार्यक्रम हुए।

28 अक्तुबर 2003 को जम्मू मे बडी सभा हुअी। जिसमे हजारो किसान और मजदूर थे। जिनमे 300 बहने भी थी। इस प्रकारका यह पहला कार्यक्रम था। कार्यक्रम प्रभावी रहा।

3 महाधरने मे सहभाग देने जम्मू से 50 प्रतिनिधी दि. 2 सितंबर 03 को दिल्ली पहूँचे थे।

4 25–12–2003 को विजयपूर मे आंगनवाडी श्रमिकों की रैली हुअी। प्रदेश के सभी स्थानों से 600 बहने आयी थी।

वृत्त 2004 (आंदोलन)

1 लेबर कमिशनर के कार्यालय पर 300 श्रमिकों ने अपनी माँगे लेकर प्रदर्शन दिया ।

2 10 मार्च 2004 को आंगनवाडी महिलाओं ने जम्मूमे धरना दिया। जिसमे 400 बहने आयी थी।

3 20 जनवरी 04 को साम्बा सी.डी.पी.ओ. के आतंक के विरुद्ध प्रदर्शन किया जिसमे 200 श्रमिक सहभागी थे। मा. मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।

4 आंगनवाडी वर्कर्स वेलफेअर असोसिएशन को पंजीयन प्राप्त हुआ।

5 दि. 27–9–04 को आंगनवाडी कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवसपर सम्मेलन किया। 500 बहने आयी थी।

6 अप्सरा वूड फॅक्टरी के 300 श्रमिकों ने अपनी मांगो को लेकर हडताल।

7 ठेका वर्कर्स युनियन की सिंगवी वूड वर्कर्समे हडताल हुअी।

8 ग्रामीण बैंकके कर्मिकोने नॅशनल बैंक बनाने की मांग को लेकर धरना दिया ।

9 इ.एस.आय. के अस्पतालमे सुधार की माँग को लेकर प्रदर्शन हुआ।

10 प्रदेश की समस्याओं का ज्ञापन श्रममंत्रीजी को सौपा गया।

उपलब्धीयाँ

1 केसी फूड वर्कर्स युनियन और फिल वर्कर्स युनियनने मांगपत्र दिया। और समझौता हुआ। 200 श्रमिक लाभान्वित हुए।

2 इस वर्षमे 5 नये संगठन पंजीकृत हुए।

3 प्रदेश अभ्यासवर्ग दि. 3–5 सितंबर 04 को जम्मू मे हुआ (65)।

4 सर्व पन्थ समादर मंच का कार्यक्रम हुआ।

झारखंड प्रदेश

झारखण्ड प्रदेशके कुल 22 जिले है और सभी जिलो में अपना काम है। पिछले तीन वर्षों मे अपना काम अधिक सक्रीय एवं सर्वस्पर्शी हो गया है।

कोयला, इस्पात, बिजली, खदान, बीडी, बीमा, आंगनवाडी, ग्रामिण बैंक आदी क्षेत्रो मे अपना काम प्रभावी हो रहा है। पिछले तीन वर्षोंमे जनसंपर्क के एवं उद्योगशः आन्दोलन के काफी प्रभावी आंदोलन हुए है। केंद्रीय योजना के अनुसार प्रदेशस्तर के प्रदर्शन के लिये किसान और श्रमिकों ने एक साझाँ कार्यक्रम किया। वर्ष 2002 के स्थापना दिवस से जनजागरण शुरू हुआ। दि. 30 सितंबर 2002 को रांची मे हजारो श्रमिक किसानों ने संयुक्त सभा, रैली, करके प्रदर्शन दिया। जुलूसमे सात हजार से अधिक महिलाएँ थी। वैश्विकरन, विश्व व्यापार संगठन, सरकार की श्रमिक नीती, श्रमकानून परिवर्तन, प्रस्ताव, बेरोजगारी आदी विषयोंपर वक्ताओं का संबोधन हुआ।

दि. 27 फरवरी 03 को कोयला मजदूरो ने हजारो की संख्या मे सीसीएल मुख्यालय पर धरना दिया और माँगे मनवाकर उसे सफल बनाया।

21–5–03 को इ.पी.एफ. व्याजदर मे वृद्धी की माँग को लेकर प्रदेश स्तर के चार कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्रीजी को ज्ञापन सौपा गया।

21–22 जून को बोकारो जिला शिक्षा वर्ग एवं पांकुड जिला शिक्षा वर्ग हुआ।

23 जुलाई 2003 से एक पखवाडे मे 20 मुख्य स्थानों पर प्रदेश में कार्यक्रम हुआ। 145 ग्रामों मे ग्रामसभा, हाट सभा, सायकल रैली, गोष्टीयाँ आदी का आयोजन हुआ। कुल 2000 गावों से संपर्क हुआ है। 10,000 पुरुष एवं 2000 महिला कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम मे सहभाग रहा।

कार्यक्रम अत्यंत प्रभावी हुआ। प्रचार प्रसार भी अच्छा हुआ। स्वदेशी, विश्वव्यापार, बेरोजगारी आदी विषयों पर जागरण हुआ। साहेबगन्ज, रांची, हजारीबाग, चितरा, गुमला, लोहरदगा, बोकारो, धनबाद, सरायकला, पलामू, देवघर, गिरीडीह जिलो मे प्रभाव बना है । 18–10 को अभ्यासवर्ग देवघर और मेघाहातुबुरु में हुए 12–12–03 को प्रदेशमे चार कार्यक्रम स्वदेशी के हुए।

13–11–03 को आंगनवाडी का प्रदेश अधिवेशन रांची मे हुआ। (1800) 01 फरवरी 04

को प्रदेश का बनवासी श्रमिक सम्मेलन रांचीमे हुआ 450 उपस्थिती रही। 26 जनवरी 04 को पाकूडमे बीडी मजदूरों का प्रदर्शन हुआ (310)

23 जुलाई 04 के स्थापना दिवसपर देवघर में प्रभातफेरी कार्यक्रम हुआ (400)एवं 75 कार्यकर्ताओंका रक्तदान कार्यक्रम हुआ। वनवासी मेधावी छात्रो को शिक्षा सहायता प्रदान करनेका कार्यक्रम बरकाखाना मे हुआ। बोकारो मे अन्यान्य श्रम संगठनोंके पुराने कार्यकर्ताओंका सम्मान किया गया।

13–8–04 को कोयला कंपनीयोंके मुख्यालयोंपर प्रदर्शन हुआ। हजारो श्रमिक थे। 16–8–04 को साहेबगन्ज जिला मुख्यालयपर पथ्थर खदान उद्योगका भारी प्रदर्शन हुआ। 1000 श्रमिक विभिन्न स्थानोंसे आये थे। 20–9–04 को बोकारो स्टील कंपनीपर इपीएफ व्याजदरको लेकर प्रदर्शन।

25–9–04 जालाजोरी प्रखण्ड(देवघर) मे असंगठीत श्रमिकोंका प्रदर्शन हुआ। भारी संख्यामें श्रमिक पहुँचे।

कर्नाटक प्रदेश

कर्नाटक प्रदेशके 27 जिले है। जिनमेसे लगभग सभी में अपना काम है। प्रदेशमें धीरेधीरे काम मजबूत हो रहा है। केन्द्रीय आदेशके अनुसार भा.म.संघ के आवाहन पर 16 अप्रैल 02 को पुरे प्रदेशके बैक, बीमा एवं सार्वजनिक क्षेत्र बंद थे। भा.म.संघ, भा.किसान संघ एवं स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओंने वैश्वीकरन एलपीजी नितीयाँ, विश्व व्यापार संघ का दबाव आदी विषयोंको लेकर पूरे प्रदेश में मई 2002 से जागरण शुरु किया था। सितंबर 02 के माह में प्रदेश में भारी मात्रा में नुक्कड सभाएं ग्रामसभाएँ हूई। पर्चियाँ बटी, द्वारसभाए हूई।

02 अक्तुंबर 02 को प्रदेशके चार स्थानों पर स्थानिक कार्यक्रम उक्त बिन्दुओं को लेकर हूवे तथा बेंगलूर में हजारो कार्यकर्ताओं ने संयुक्त सभामें संबोधन सुना। कर्नाटक में इस साँझे कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद का भी सहयोग मिला। वृत्तपत्रो में अच्छी प्रसिद्धि मिली।

वर्ष 2003 में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रदेश में हूए है। 20 जनवरी 03 को मेंगलोर में प्रदेशका त्रैवार्षिक अधिवेशन संपन्न हूवा। 460 प्रतिनिधी 19 जिलो से आये थे। मा.प्रभाकरजी मुख्य अतिथी रहें।

8–9 मार्च 03 को लीगल सेल की क्षेत्रीय कार्यशाला बेंगलोर में संपन्न हूवी। 7 प्रदेशो से 45 कार्यकर्ता उपस्थित रहें। सर्वश्री सुब्बारावजी वेणुगोपालजी एवं सजी नारायणजी ने मार्गदर्शन किया। इन्ही दिनो पर बेंगलोर में असंगठीत क्षेत्र की समस्याए एवं महिला और बाल श्रमिक विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हूआ था।

1 मई 03 को बेंगलोर में महिला संम्मेलन हूआ। 150 से अधिक महिलाओं का सहभाग मिला था।

प्रदेशमें स्वदेशी संघर्ष यात्राके नाम से 16 जून से 23 जून 03 दिनोंमे प्रवास हूआ तथा प्रदेश के मुख्य 12 जिला केन्द्रो पर 20 कार्यक्रम हूऐ। दुसरे दौर में 17 अगस्त से 23 अगस्त तक अन्य 13 जिलोमें 16 स्थानों पर यात्रा निकाली गयी।

इसी बीचमें 06 जुलाई 03 को असंगठीत क्षेत्र के 32 कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय शिवीर शिमोगा में हूआ।

दिसंबर 26–27–28 के तीन दिनो में भा.म.संघ के 149 कार्यकर्ताओंका शिक्षावर्ग मैसूर में संपन्न हूआ। युवा कार्यकर्ता 110 थे। मा. अग्घीजी, मा. सुब्बारावजी का मार्गदर्शन हूवा।

पिछले तीन वर्षा में प्रदेश में कई आन्दोलन हूए तथा कई उपलब्धीयाँ मिली। प्रदेशमें उक्त काल में आठ नये संगठन बने।

प्रदेशमें सिप्ला कंपनीमें समझौता हूआ। (1300/–) शान्तला फोन्ड्रीज, मैनी मटेरीअल, जेमिनी स्टील, आशीर्वाद पाईपस्, कोनी बॅन्ड, ओम्नी मैट्रीक्स, आदी कम्पनीयोंके समझौते हूए।

मेंगलोरमें गुमास्ता श्रमिकोका आंदोलन हूवा। बीडी उद्योग के हजारो श्रमिक भा.म. संघके नेतृत्व में रोजगार के लिये संघर्षरत है। भोरुका टेक्स्टाईल कंपनी बंद हूई है उसका आन्दोलन चल रहा है।

विन्टेक फार्मा बेंगलूर कंपनी के आंदोलन में मजदूरों पर लाठीचार्ज हूआ है। आंदोलन चल रहा है।

2004 के वर्षमें स्थापना दिवस के पांच कार्यक्रम संपन्न हूए है।

केरल प्रदेश

केरल प्रदेश के कुल 14 जिले है, सभी जिलों मे अपना काम है और पिछले तीन वर्षो मे काम काफी आगे निकला है।

16 अप्रैल 02 को सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान भा.म.संघ के आवाहन पर बंद रहे थे। उसके बाद देशव्यापी कार्यक्रम के तहत प्रदेश मे 25 सितंबर 02 से 2 अक्तुबर 2002 के दिनोमे सभी जिला स्थानोंपर बडे कार्यक्रम किये।

15 स्थानों पर 'जीपजथा' नामसे वाहन यात्राएँ निकली। पदयात्राओं द्वारा जनसंपर्क अभियान 114 स्थानों पर हुआ । नुक्कड सभाएँ 126 स्थानोंपर हुअी तथा 1207 स्थानोंपर 'रोडशो' हुए। इन सभी कार्यक्रमों मे घरोंतक संपर्क करने की योजना बनी थी। जिसमे 2,46,020 घरोंतक कार्यकर्ताओं ने संपर्क बनाया और श्रमिक समस्या से उन्हे अवगत कराया। एवं 5,96,000 घरों मे पर्चीयाँ बाँटी। प्रचार माध्यमों ने एवं जनताने इन प्रयासों की खूब सराहना की।

9/11/02 – प्रदेशका महिला सम्मेलन कोझीकोड मे हुआ (265)। केरल राज्य सरकारी कार्मिकोंकी एक माह की हडताल मे भा.म.संघ अग्रभागी। ताडी, हेडलोड, राज्य परिवहन, निजी परिवहन, प्लँटेशन, निर्माण मजदूर, खेतीहर मजदूरों की मांगो को लेकर अलगअलग प्रदर्शन वर्ष 2002 मे हुए है।

5/1/03 – मुन्नार मे चाय बगान के बेरोजगार मजदूरो ने बडा जुलूस निकाला (4500)। 2–3–03 से 11–3–03 पदयात्रा करके 'इडुकी' की चाय बगान श्रमिकों की समस्या उजागर करने का प्रयास। 30,000 परिवार भूख व्याप्त हुए है। दि. 20–4–03 को मत्स्य प्रवर्तक संघ ने मछवारों की माँगो के लिये जुलूस निकाला (5000)। इसी दिन राज्य परिवहन का प्रदेश अधिवेशन संपन्न हुआ। 17–18 मई 03 को प्रायवेट मोटर फेडरेशन का अधिवेशन कोट्टायम मे हुआ 2800 की उपस्थिती थी। 25 मई 03 मेडिकल रिप्रेंझेटेटीव्ह असोसिएशन का 7 वा अधिवेशन कोल्लम मे संपन्न हुआ। 2400 संख्या थी। 1–7–03 कोझीकोड जिले मे मारट गांवमें मछवारों पर जानलेवा हमले की सी.बी.आय. जाँचकी मांग लेकर हजारो श्रमिकों ने जिलाधीश मुख्यालय पर धरना जुलूस निकालकर धरना दिया। 1–8–03 से 14–8–03 के पखवाडे मे जनजागरण हुआ। 23 अगस्त 03 को हेडलोड फेडरेशन का 7 वा अधिवेशन थिरुवानंतपुरम् मे हुआ। 5000 की संख्या थी। 30 अगस्त

2003 को कृषक फेडरेशन की स्थापना अदूर (पट्टनतिट्टा) मे हुअी। 10 जिलोसे 500 से अधिक प्रतिनिधी आये थे। 15 से 17 अगस्त 03 को निर्माणी मजदूरों के फेडरेशन का शिक्षा वर्ग पलक्कड मे संपन्न हुआ। 12 जिलों के प्रतिनिधी आये थे। इडुकी जिलेमे बेरोजगार बने चाय बगानों के मजदूरों को प्रदेश ने 1.96 लाख की राहत राशी जमा करी है।

9/12/03 को 'स्वदेशी दिवस' मनाया गया और 13 जिलों मे आमसभा एवं धरने हुए।

'मजदूर भारती' नामक मासिकपत्रिका के केरल मे सदस्य बनाने का अभियान चला और 10,000 सदस्य बने है।

केरलके प्रान्तीय कार्यकर्ता शिबीर मे 24–25–26 जनवरी 2004 को स्व. ठेंगडीजी उपस्थित रहे थे। 157 संख्या थी। थिरुवेल्लू मे प्रदेश के आंगनवाडी वर्कर्स हेल्पर्स संघ की स्थापना 19 जनवरी 04 को हुअी। 16 जनवरी 04 को रेअर अर्थ लि. के चुनाव मे भारी जित हुअी। 5–3–04 के चुनावमे आर्य वैद्यशाला मे तीसरा स्थान मिला।

18 जनवरी 04 को निर्माणी मजदूरों का राष्ट्रीय अधिवेशन कोट्टायम मे हुआ। 10 प्रदेशों से प्रतिनिधी जुलूस मे थे। आमसभा मे 5000 श्रमिकों ने सहभाग दिया।

18 अगस्त से 24 अगस्त 04 को युपीए केंद्रसरकार की श्रमविरोधी निति के विरुद्ध प्रदेशभर मे प्रदर्शन, मशालयात्रा, धरना, आमसभा आदी 84 कार्यक्रम किये। पीएफ व्याजदर, विरोधी निति, रबर आयातपर छूट, किसानविरोधी डब्ल्यू.टी.ओ समझौता, महंगाई, बोनस मर्यादा बढाने की माँग आदि विषय लिये थे।

स्थापना दिवस 23–7–04 के उपलक्ष्य मे प्रदेश मे 40 कार्यक्रम हुए। 19,841 कार्यकर्ताओ ने सहभाग दिया।

राष्ट्रीय श्रम दिवस के 243 कार्यक्रम हुए। जिसमे 27,505 कार्यकर्ताओ ने सहभाग दिया।

दि. 18–19 जून 2004 को प्लांटेशन उद्योग का पहला अखिल भारतीय अधिवेशन कमाली इडूक्की जिलेमे हुआ । 6 प्रदेशो से प्रतिनिधी आये थे।

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के कुल 61 जिलोसे से 57 जिलों मे काम है। एव प्रदेशके 16 विभाग है। प्रदेश का काम पिछले साल से काफी प्रगती कर रहा है। पिछले तीन वर्ष के गतिविधी का लेखाजोखा कुल इस प्रकार से है।

2002

केन्द्रीय योजना के अनुसार भा.म.संघ के अवाहन पर दि. 16/04/02 को सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद रहे।

दि. 25 सितंबर 02 से 2 अक्तूबर 02 के देशव्यापी 'डब्लु.टी.ओ. मोडो–तोडो–छोडो' कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेशमें सैकडो सभाए ग्रामोंमे एवं शहरो मे हुई।

दि. 26/09/02 को भा.म.संघ, भारतीय किसान संघ एवं स्वदेशी जागरण मंच का साँझा जुलूस भोपाल राजधानी मे निकला हजारो किसान, दस हजार मजदूर सहभागी हुए, तीन हजार महिलाएँ थी, नीलमपार्क में सभा हुई, पूर्व अध्यक्ष मा. रमणभाई शहा का उद्‌बोधन हुआ, कार्यक्रम सफल हुआ एवं अच्छी प्रसिद्धि मिली।

मलाज्जरवण्ड मे हिंदुस्थान कॉपर श्रमिकों मे भा.म.संघ के तत्वाधान मे निजीकरण के विरूध्द भारी एवं सफल प्रदर्शन दिया। परिसर के नगरजनो ने भी खूब साथ दिया. जबलपूर मे उच्च न्यायालय ने निजीकरण पर रोक लगाई फिर सरकार भी मान गयी। कामगारों ने खुशी में सभाएँ जूलूस, आदि कार्यक्रम किये। 22/9/02 को भेल यूनियन का भोपाल मे त्रैवार्षिक सम्मेलंन संपन्न हुवा (700) दि. 12/12/02 को स्वदेशी दिवस के भोपाल, उज्जैन एव इंदोर मे कार्यक्रम हुए।

2003

दि. 20/02/2003 को लंबीत वेतन, प्रवास भत्ता, आदी माँगे लेकर सरकारी कर्मचारीयोंने विधानसभा पर भोपाल में भारी प्रदर्शन दिया (2200) काले गुब्बारे छोडकर अभिनव भर्त्सना आंदोलन किया। हजारो दैनिक वेतन भोगी कार्मीकों के निष्कासन के खिलाफ भोपाल मे धरने हुए। इंजीनिअरिंग उद्योग एम.डी.आय.आर. कानुन की सुची से हटाकर, मुख्यमंत्री स्वयं पंचाट के न्यायाधिश बने थे । श्रमिकों के इन समस्याओं की पहल करने के लिये सुश्री उमाभारतीजी का अनशन भोपाल में हुआ था।

दि. 25/03/03 सर्व पंथ समादर मंच के कार्यक्रम भोपाल, उज्जैन, इन्दौर एवं जबलपूर मे हुए।

पश्चिम क्षेत्र के परिवहन इकाईयों का अभ्यासवर्ग दि. 18/19/20 नवंबर 03 में भोपाल में संपन्न हुआ।

भा. म. संघ म. प्रदेश का 16 वा. त्रैवार्षिक अधिवेशन रीवा मे दि. 15,16 जून 03 को संपन्न हुवा (650) 23 जुलाई से शुरू हुए पखवाडे मे स्थापना दिवस के कार्यक्रम 35 जिलो मे 12 महानगरों मे और 15 औद्योगिक क्षेत्रो में संपन्न हुए। हजारो कार्यकर्ता सहभागी हुए 1557 ग्रामो मे संपर्क हुआ। 500 से 5000 तक की उपस्थिती रही । पर्यावरण मंच के कार्यक्रम प्रदेश मे 10 स्थानो पर हुए।

2004

दि. 28/02/04 को महिला विभाग की बैठक उज्जैन मे संपन्न हुई। दि. 08/02/04 को रीवा मे प्रदेशका आगनवाडी सम्मेलन संपन्न हुवा उपस्थिती 180 थी। मई 2004 खरगोन (बडवाना) मे महिला जिला सम्मेलन हुआ 700 उपस्थिती थी।

दि. 6/06/04 को कृषी ग्रामीण मजदूरोंका अ. भा. अधिवेशन कुछती मे संपन्न हुआ आमसभा मे 200 महिलाए उपस्थित थी (5200)

दि. 18, 19 सितंबर 04 बिजली उद्योग का रजत जयंती अधिवेशन उज्जैन मे संपन्न हुवा (1300) प्रदेशमे इस वर्ष स्थापना दिवस के 40 कार्यक्रम हुए। म. प्रदेश सरकारने श्रमनिती बनाने के लिये म.प्र. श्रम कल्याण मंडल के चेअरमन श्री. शक्रवार की अध्यक्षता मे समिती बनायी हे जिसमे प्रदेश महामंत्री समिती सदस्य है।

विशेष विन्दु – बीडी मजदूरो का इपीएफ सुविधा के विस्तार हेतु बनी समिती ने प्रादेशिक सरकार को 19/02/05 को रिपोर्ट दी है।

राज्य कर्मचारीयों की समस्याओ के समाधान के लिये संयुक्त मोर्चा बना है। 25/02/05 को विराट प्रदर्शन विधानसभा पर दै. वेतनभोगी कर्मचारी एवं बीडी कर्मचारीयों का 15 मार्च 05 को विधानसभा पर प्रदर्शन। म.प्र. राज्य अधिकारी संघ का संगठन गठीत हुआ।

महाराष्ट्र प्रदेश

महाराष्ट्र प्रदेश में कुल 24 जिले है। सभी जिलो में अपना काम है। प्रदेशकी गत तीन साल की प्रगती अच्छी है।

16 एप्रिल 02 के सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद में भा.म.संघ अग्रेसर था। पुना तथा मुंबई शहर में भा.म.संघने नेतृत्व किया। प्रान्तो से 16 स्थान पर जूलूस, सभा का आयोजन हुआ था। मोर्चामें भा.म.संघ के 2500 कर्मचारी उपस्थित थे।

- 20 अगस्त 02 को भा.म.संघ, भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंचका मुंबई में अभ्यास वर्ग हुवा। (80)
- 2 अक्तुबर कार्यक्रम के तयारी के लिये 3 जीप यात्रा, अगस्त 02 में निकाली गयी 22 जिले एवं 48 तहासीलोंसे संपर्क किया। 1300 पत्रकों का वितरण किया। 107 द्वारसभा हुई।
- 2 अक्तुंबर 02 के कार्यक्रम को 24 जिलों के 187 तहसिलों के 220 शहर और ग्रामों से 40,000 सदस्य, आये थे। 4 घंटेका महामोर्चा और जाहिर सभा में मा.दत्तोपंतजी का मार्गदर्शन हुआ।
- 4 मार्च 03 राष्ट्रीय सुरक्षा दिन के कार्यक्रम पुना, मुंबई,जलगांवमें संपन्न हुए। (450)
- 16 जानेवारी 03 को पुणे शहर का मकरसंक्रमण पारिवारीक संमेलन हुआ। (325)
- 20 जनवरी 03 जिलेका पारिवारीक संमेलन हुआ। (800)
- 17–18 मई 03 को प्रदेशका 18 वाँ त्रैवार्षिक अधिवेशन मुंबई हुआ। (478)
- 23 जुलाई को जलगांव में 1700 श्रमिकोंका जुलूस हुवा। मा. ठेंगडीजीका मार्गदर्शन हुआ।
- 9/8/03 को नाशिक में 3500 कार्मिकों का मोर्चा और जनसभा का आयोजन हुआ था।
- 9/8/03 को औरंगाबादमें वाहन फेरी निकाली थी। 250 स्कूटर, मोटर सायकल, रिक्षायें थी।
- 9/8/03 को डब्लु.टी.ओ.के विरोध में पूना में मानवी शृखंला का आयोजन 600 उपस्थिती थी। (800)

- 8/8/03 को मुंबई के अगस्त क्रांती मैदान पर हुतात्मा अभिवादन का कार्यक्रम हुआ। मा. अग्घीजी उपस्थित थे।
- 12/12/03 को स्वदेशी दिन के अवसर पर हुतात्मा बाबू गेनूके प्रतिमा का पूजन मुंबई के कामगार मैदानपर किया। (350)
- सर्व पंथ समादर मंच की ओर से होली मिलन का कार्यक्रम पुना में हुआ। मा.अखतर हुसेन उपस्थित थे।
- 26–30 जानेवारी 04 कार्यकाल में कोल्हापूर जिले में दस तहसिलों के 325 छोटे गाँवमें जाकर भारत माता प्रतिमा पूजनके कार्यक्रम किये। 20 कार्यकर्ता 5 दिन प्रवास में थे।
- जनवरी, फरवरी 04 को अंबेजोगाई और ठाणे शहर में राज्य शासकिय कर्मचारीयोंके अभ्यास वर्ग संपन्न हुवे। (40)
- 31 अगस्त को भुमिहिन किसानोंकी माँगोको लेकर कोल्हापूरमें जूलुस निकाला गया। (480)
- 23 जुलई 04 को एकही दिन प्रदेश में स्थापना दिन के 40 कार्यक्रम हुए। कुल उपस्थिति 4200 तक थी। सुवर्ण महोत्सवी वर्षके उपलक्षमें प्रदेश अध्यक्ष दुरदर्शन पर प्रकट मुलाकात हुई।
- 16 जुलाई से 23 जुलाई तक राष्ट्रीय महामंत्री का प्रदेश के 7 नगरमें दौरा हुवा। वार्तालाप, जनसभा का विशेष आयोजन (8000)
- 22 अगस्त 04 को रायगड जिले का वर्षा सेर कार्यक्रम हुवा। (110)
- सतारा जिला के चाळकेवाडी ग्राममें पवन उर्जा क्षेत्र में प्रथम संघटना बनाने में सफलता मिली। 29 जुलाई से 20 अगस्त इतना 33 दिनका हडताल हुवा। वेतनवृध्दी सेवाशर्ते समझोता हुआ।
- 28 दिसंबर 04 में पुनाके सेंचूरी एंका कंपनी में रु. 2875/– प्रतिमाह वेतनवृद्धीका करार हुआ।
- महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ की ओर से नाशिक से मजदूर वार्ता, वार्तापत्र का नियमित प्रकाशन होता है। एन ओ आय डब्ल्यू का न्यज बुलेटिन मुंबई से प्रकाशित होता है।

नये संघटन :

- मछुआरों का नया संघटन जळगांव जिले में बना। दि. 24 सितंबर 04 को बिंद्री (जळगांव) ग्राम में मछुआरों का संमेलन हुवा। 20 गांव के 1200 मछुआरे उपस्थित थे।
- 12/12/04 को राज्य कर्मचारी संघ का प्रदेश अधिवेशन पुनामें हुआ। 19 जिला के 280 प्रतिनिधी उपस्थित थे।
- 11/12 दिसंबर को नगर परिषद कर्मचारी संघ का प्रदेश अधिवेशन पुना में संपन्न हुआ। (250)
- नोबो, महाराष्ट्र बँक कर्मचारी संघ, महाराष्ट्र बँक अधिकारी संघटना, भारतीय पोर्ट एवं शिपयार्ड मजदूर संघ महाराष्ट्र मोटर कामगार संघ, इन संघटनाओं के अ.भा.अधिवेशन महाराष्ट्र में हुए।
- फरवरी 2004 में एन ओ आय डब्ल्यू का अधिवेशन नांदेड में हूआ।
- सन 2004 को प्रदेश के महिला विभाग के 10 कार्यक्रम हुए। 700 तक महिलाओं का सहभाग था।
- अगस्त 04 को पुना के कारागृह में जाकर 500 कैदीयों को रक्षाबंधन किया।

विदर्भ प्रदेश

महाराष्ट्र राज्यके, भारतीय मजदूर संघ के कार्यकी दृष्टी से शुरु से ही 2 स्वतंत्र प्रदेश काम कर रहें है। प्रदेश में 11 जिलें आतें है। एवं सभी जिलों में अपनी इकाईयाँ गठीत है। विद्युत कोयला, प्रतिरक्षा, बीमा, बैंक, टेलिफोन, पोस्ट, रेल, बीडी, बनवासी, खेतीहर आदी सभी क्षेत्रो में अपना काम है। प्रदेश के गतीविधि का वृत्त इस प्रकार से है।

22,23,24 फरवरी को वीज कामगार महासंघ का प्रान्तिय अधिवेशन अमरावती में सम्पन्न हूआ। (2500)

8 मार्च को विश्व महिला दिन के अवसर पर नागपूर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। (80)

16 अप्रैल को सार्वजनिक उद्योगों के कामगारों की एक दिन की राष्ट्रव्यापी हडताल सफल।

3 मई को बैंक तथा बीमा कामगारों का प्रदर्शन नागपूर में आयोजित किया गया। (220)

5 मई 2002 को चंद्रपुर जिला में जुलूस निकाला गया । (300)

31 अक्टूबर 2002 को नागपूर में विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन के अवसर पर श्रमिक समस्या लेकर जुलूस हूआ। (700) वर्धा जिला में कार्यरत नोबेल एक्स्लोकेम नामक एन.जी.पर आधारीत बारुद निर्मिती करनेवाला कारखाना बंद करने का निर्णय केंद्र सरकार के आदेशानुसार लिया गया था । न्यायालयीन संघर्ष भी किया । फलस्वरुप कामगारो की छटनी नहीं हुई । कारखाना बंद नही हुआ ।

23 जुलाई को भा. म. संघ का स्थापना दिन सभी जिला स्थानो पर मनाया गया । नागपूर के कार्यक्रम उपस्थिती 300

दिनांक 13 अगस्त 2002 को स्टेट बैंक वर्कर्स ऑर्गनायझेशन की ओर से पारिवारीक स्नेहमिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

11 सितम्बर 2002 को स्व.एम.जी.बोकरे स्मृती दिन मनाया गया। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगडी कार्यक्रम में उपस्थित थे। (200)

21,22 सितम्बर 2002 को सर्वपंथ समादर मंच की अ.भा.बैठक नागपूर में आयोजित की गयी । श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगडी बैठक में उपस्थित थे । (40)

2 अक्तुंबर 2002 को नागपूर में प्रदेश की ओर से विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। अंदाजन 18000 कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच तथा लघु उद्योग भारती का इस कार्यक्रम में सक्रीय सहभाग रहा।

18/19 दिसंबर 2002 को प्रतिरक्षा मजदूर संघ की ओर से निजीकरण के विरोध में धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया(100)। 31 दिसंबर 02 से 2 जाने 03 तक पश्चिम क्षेत्र का अभ्यास वर्ग नागपूर में संपन्न हूआ। (120)

वर्ष 2003 :

प्रदेश अधिवेशन : विदर्भ प्रदेश का 13 वाँ प्रान्तीय अधिवेशन दि. 9/10 फरवरी 03 को भंडारा में संपन्न हूआ। 920 प्रतिनिधी इस अधिवेशन में उपस्थित थे। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगडी

की उपस्थिती यह इस अधिवेशन की विशेषता थी। 30 साल बाद वे भंडारा अधिवेशन में उपस्थित रहें। इस अवसर पर शोभा यात्रा तथा जाहीर सभा का आयोजन किया था। जाहिर सभा में श्रीदत्तोपंत ठेंगडीजी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

जिला अधिवेशन : इस वर्ष निम्न जिला अधिवेशन हूए।

यवतमाल 13 अप्रैल 03 (350) भंडारा 11 मई (150) चंद्रपूर 22 जून (350) अमरावती 22 जून (180) नागपूर 6 जुलाई (650) 13,14 अक्तुंबर 2003 को अमरावतीमें बीमा उद्योग का क्षेत्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ।

अभ्यास वर्ग : निवासी अभ्यास वर्ग नागपूर में 27,28,29 जून 03 को आयोजित किया गया। (142) 30 अप्रैल तथा 1,2 मई नागपूर में निवासी महिला अभ्यास वर्ग (120) नागपूर में दि. 8,9 नवंबर 03 को बिजली उद्योग का अभ्यास वर्ग हुआ (80)।

अन्य कार्यक्रम : 20 अप्रैल को विज कामगार महासंघ की ओर से निजीकरण के विरोध में धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। (60)

28 अप्रैल को निजीकरण के विरोध में भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ की ओर से धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। (340)

23 जुलाई 03 को भा.म.संघ का स्थापना दिन सभी जिला स्थानोंपर संपन्न हुआ। नागपूर में आयोजित कार्यक्रम (1400) चंद्रपूर जिला कार्यकर्ताओंका अभ्यास वर्ग 22 और 23 नवंबर 03 को चंद्रपूर में संपन्न हुआ। (80) 10 नवंबर को स्वर्गीय अबाजी पुराणिक स्मृती दिन मनाया गया (100)। 12 दिसंबर 03 बाबू गेनू शहीद दिन मनाया गया। (52)

वर्ष 2004 :

दि. 1 जनवरी 04 को सावित्रीबाई फुले जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया (40)।

20 जनवरी को मकर संक्रमण उत्सव संपन्न हुआ।(30)

15 फरवरी को वर्धा जिला अधिवेशन वर्धा में संपन्न हुआ (340)

13 मार्च को विश्व महिला दिन के उपलक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया गया। (22)

25 मार्च को सर्व पंथ समादर मंच की ओर से कार्यक्रम का अयोजन किया गया। नुर मेमोरियल अस्पताल के संचालक श्री जुगादे तथा सर्व पंथ समादर मंच के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सी बी फ्रंक उपस्थित थे। (70)

13 जून को अमरावती में महाराष्ट्र जलसेवा प्राधिकरण का प्रांतीय अधिवेशन हुआ। (250)

20 जून को चंद्रपूर में महिला अभ्यास वर्ग हुआ (21)

26 से 28 जून को स्वायत्तशासी कर्मचारीयोंका प्रांतीय अभ्यास वर्ग चंद्रपूर में संपन्न हुआ। (85)

10 अक्तुंबर 04 को यवतमाल मे महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। (142)

अ.भा. कोयला खदान मजदूर संघ द्वारा 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक 3 दिन की सफल हडताल की गयी।

नई संगठनाओं का गठनः

नई संगठनाओं का गठन करने का निरंतर प्रयास चल रहा हैं। वर्ष 2003–04 मे 12 नई संगठनाओं का पंजीकरन किया गया। अंगनवाड़ी क्षेत्र में अपना काम प्रारंभ हुआ है। भंडारा जिला में सिटू से संबंधित अंगनवाडी महिलाओं ने 22 नवंबर 2004 को भा.म.संघ में प्रवेश किया।

उडिसा प्रदेश

उडिसा प्रदेश भारतके पूर्वी तटवर्ती प्रदेश है। 6234 ग्राम पंचायत 314 विकासखंड एवं 30 जिले प्रदेशमें है। 1967 में भा.म.संघ के एक संगठन और 45 सदस्य थे। आज उक्त सभी स्थानों पर भा.म.संघ का काम पहूँचा है।

भा.म.संघ का काम संगठीत एवं असंगठीत क्षेत्रो में फैल रहा है। राउरकेला स्टील प्लाँट, महानंदी कोल फिल्ड, नालको, एचएएल, एन टी पी सी खदाने, इंडीयन रेअर अर्थ, हेवी वॉटर, आदी भारत सरकार के लगभग सभी उपक्रमों मे अपना काम है, और बढ रहा है।

भा.म.संघ के अनेक संगठन निजी क्षेत्रो में भी पंजीकृत है। जे के पेपर्स, सेवा पेपर्स, इंडियन मेटल ॲन्ड फेरो अलाईड, उत्कल गॅलवनायजर्स, एसीसी सिमेंट,आदी आदी

खदाने :– उडीसा खनीजो से समृद्ध है। भा.म.संघ की आयरन, मॅगेनीज, डोलोमाईट, आदी उद्योगों मे संगठन है।

सेवा क्षेत्र :– पोस्टल एवं टेलीकॉम उद्योगोमें अपना काम है। परिवहन में काम देर से शुरु हूआ है। परंतु मजबूती से बढ रहा है।

कटक के खरपूरीया एवं जगतपूर औद्योगिक बस्तीयों के छोटे उद्योगो में एवं मयूरभंज के रायरंगपूर में अपना काम बढ रहा है।

उडिसा आंगनबाडी महिला कार्यकर्ताओं का एसोसिएशन सबसे मजबूत संगठन है, प्रदेश के सभी ग्रामों मे इसकी शाखाएँ है। विकासखण्ड इकाईयों के बाद अब पंचायत स्तरीय समितीयाँ बनाने का प्रयास है। अंगुल जिला और देवगढ झारसुगुडा और संम्बलपूर के 75प्रतिशत देहातो में तथा मलकनगिरी के बीडी उद्योगों में उत्कल बीडी मजदूर संघ काम कर रहा है। अंगुल में बीडी श्रमिकों का प्रादेशिक तिसरा अधिवेशन 12 जनवरी 2005 को सम्पन्न हूआ। 600 प्रतिनिधी आये थे।

उडीसा ठेका मजदूर संघ का निर्माण जून 2004 में हूआ। कटक में 25/26 जून 04 को अ.भा.ठेका मजदूर महासंघ का पहला अधिवेशन हूआ।

उत्कल बुनकर संघ मार्च 2004 में पंजीकृत हूवा। काफी तेजीसे संघ बढ रहा है। कटक, केंझर, ढेनकानला, बरगार, बोलानगीर, सुबरनपूर में काम बढ रहा है।

उडीसा कृषी एवं ग्रामीण मजदूर संघ यह पूरे प्रदेश का महासंघ है, और धीरे–धीरे बढ रहा है।

अभ्यासवर्ग :–

1. प्रदेश स्तरीय वर्ग दि. 6,7,8 जूलाई 2002 को तालचेर में संपन्न हूआ (50). 2–3 मई 2003 को बालीगुडा में प्रदेश का वर्ग संपन्न हूआ (45). वर्ष 2002 में 18 जिलों मे शिक्षा वर्ग का आयोजन जूलाई से सितंबर के माह में किया गया। 700 कार्यकर्ता प्रशिक्षीत हूए।

2. 2003 मे 22 जिलो में 900 कार्यकर्ता प्रशिक्षीत हूए। महिला कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। 20–22 जून 2003 के दिनों में कटक में किया गया। (60) नालको नगर में दि. 18/19 जून 03 को बीडी, कृषी, ठेका, क्षेत्रके कार्यकर्ताओं का वर्ग हूआ। (45)

पूर्व क्षेत्रका शिक्षावर्ग दि. 15–17 अगस्त 04 को पूरी में संपन्न हूआ (115) उडिसा, बंगाल, बिहार एवं झारखण्ड से कार्यकर्ता आये थे।

जुलै 02 और सितंबर 02 के माहमें कोयला खदान महानंदी के कार्यकर्ताओं के वर्ग तालचेर में किये गये। (70)

विश्व व्यापार संघ की नितीयों के विरोध में आन्दोलन 25/09 से 2/10 के दिनोमें हूए। सभी 314 प्रखण्डो में जनजागरण का काम सभा, जुलूस एवं प्रदर्शन द्वारा किया गया। 45000 श्रमिकों का सहभाग रहा। बाद में 2 अक्तुंबर 02 को भा.म.संघ, किसान संघ एंव स्वदेशी जागरण मंच के हजारो कार्यकर्ता भुवनेश्वर की रैली में पँहूचे जिसमें भा.म.संघ के दस हजार कार्यकर्ता थे। भा.म.संघ के कार्यकर्ताओं ने तीन हजार पंचायतों को संपर्क किया था। वहाँ हजारो पर्चिया बाँटी एवं छोटी सैकडो सभाएँ हूई।

वर्ष 2003 में भा.म.संघ के आदेशपर जिला स्तरीय कार्यक्रम हूए। 23 जुलाई से 9 अगस्त 03 तक प्रदेश के 28 जिला मुख्यालयों पर 29000 श्रमिकों ने सहभाग दिया।

22 अप्रैल 03 को पी एफ व्याजदर की मांग लेकर भूवनेश्वर, राउरकेला, एवं बेरहमपूर में धरने हूए।

परिवहन मजदूर संघ ने दि. 21/04/03से तीन दिन की हडताल की। समझौते के बाद हडताल वापस हूई। 90 लाख की पी एफ बकाया राशी वसूल हूई।

12 फरवरी 2000 से 12 सितंबर 03 तक 42 महिनो तक दूरसंचार के अस्थायी मजदूरों का धरना भूवनेश्वर में चला। गैर कानूनी छटनी दूर करके 455 कर्मिकोंको स्थायी बनाने का समझौता हूआ। वामपंथीयों द्वारा प्रेरित कुछ श्रमिकों ने न्याय पालिका से स्थगन आदेश लेकर समझौता रोका है।

मार्च एवं अप्रैल 03 के माहोमें 5000 बीडी श्रमिकोंने 6 जिलो में भारी धरना एवं प्रदर्शन दिया। उसी प्रकार गृहनिर्माण की माँग लेकर वेलफेअर मुख्यालय पर 5000 बीडी श्रमिको ने दि.22/23 मार्च 03 के दिनोंमे भारी प्रदर्शन किया।

तरमकान्त चाय बगान के श्रमिकोने दि.19 से 29 मई 03 को हडताल की थी। सभी बनवासी मजदूर थे। जिलाधीश के हस्तक्षेप के बाद हडताल वापस हूई ।

नालको निजीकरण के विरुद्ध भा.म.संघ संघटन ने इस प्रकार से आन्दोलन किया की 8 अगस्त 03 को भारत के प्रधान मंत्रीजीने नालको निजीकरन वापस लेने का भूवनेश्वर में आश्वासन दिया।

कोरापूट जिले के सेवा पेपर्स के ठेका श्रमिक मार्च 04 में हडताल पर चले गये। समझौते के बाद हडताल वापस हूई।

सितंबर 04 में जे के पेपर मजदूर संघ ने हडताल की। बाद में प्रबंधन ने वार्ता शुरु की और निकाले गये 10 श्रमिको को काम पर बहाल किया एवं 750/– की वेतनवृद्धी वाला समझौता भी हूआ।

बारघर के इडकॉल सिमेंट प्रकल्प का प्रदेश सरकार ने निजीकरन किया उसके विरोध में मजदूर संघ ने जिला बंद का अभूतपूर्व आन्दोलन किया।

कोयला खदानों के 80 प्रतिशत श्रमिको ने ए बी के एम एस के आदेश पर 29–30 नवंबर 04 को हडताल की कार्यवाही की। आंदोलन प्रभावी रहा।

प्रदेश का 10 वा त्रैवार्षिक अधिवेशन 25/26 जनवरी 2003 को राउरकेलामें संपन्न हूआ। प्रदेश के श्रममंत्रीजी ने अधिवेशन का उद्घाटन किया।

6,7 दिसंबर 03 को एन.टी.पी.सी. मजदूर महासंघ का अधिवेशन तालचेरमें हूआ।

पॉडेचरी

पॉण्डेचरी में अपना काम वर्ष 2004 में तेजी से प्रारंभ हुआ है। जबकी 2002 में अपने केवल 2 संगठन थे। अब पॉण्डेचरी में पॉण्डी और करेकल स्थानों पर परिवहन, टेक्स्टाईल, निर्माणी मजदूर एवं असंगठीत क्षेत्र में काम शुरु हुआ है।

दि. 17 सितंबर03 को विश्वकर्मा दिवस के शुभ अवसर पर पॉण्डेचरी के करेकल में भा. म.संघ के काम की शुरुआत हूई।इसी प्रकार से 2004 में स्थापना दिवस एवं विश्वकर्मा दिवस के कार्यक्रम प्रदेश में हूए है।

पंजाब प्रदेश

प्रदेश में कुल सरकारी दृष्टीसे 17 जिले है। संगठन की दृष्टीसे 20 जिले है। एवं कुल 72 तहसीले है। कार्यकी दृष्टीसे प्रदेश को 8 विभागो में बाटाँ गया है। प्रदेश में 10 महासंघ गठीत है।

प्रदेश महासंघो की विशेष गतिविधी :–

1. पंजाब नॉन गॅझीटेट एम्प्लाईज ऑर्गनायझेशन पी एन जी इ ओ – पंजाब में वर्तमान सरकार की कर्मचारी नितीयो के विरोध में रोष प्रदर्शन दिनांक 21 जून 02 को सचिवालय चण्डीगढ मे किया गया। इसी तरह पंजाब के अन्य कर्मचारी संगठनों को साथ लेकर 19 जुलाई 02 से 26 जुलाई 02 तक काला मांग सप्ताह मनाया गया। इस आंदोलन से घबरा कर सरकार ने दि. 25 सितंबर 02 को सभी संगठनों की बैठक बुलाई जिसमें मुख्य मंत्री ने मोके पर ही मांग मान ली। पी एन जी ई ओ का प्रादेशिक अधिवेशन दिनांक 26/27 अक्तुंबर 02 को हाशियारपूर में संपन्न हुआ। प्रतिनिधी संख्या 200 रही। प्रदेश के 14 जिलो से प्रतिनिधी आये थे।
2. पंजाब नगर पालिका कर्मचारी महासंघ :– पंजाब मे सरकार द्वारा चुंगी समाप्त करने की घोषणा के विरोध में अन्य संगठनों को साथ लेकर आंदोलन शुरु किया गया। जिससे सरकार को यह घोषणा वापस लेनी पडी। वेतन का पक्का प्रबंध न होने की हालत में 9 मई 02 को सांकेतिक हडताल की धमकी से डरकर सरकार ने पक्के तौर पर हर महीने वेतन देने का प्रबंन्ध किया। 24 जुलाई 04 को महासंघ का प्रदेश अभ्यास वर्ग पटियाला में किया गया।(150)
3. पंजाब राज्य बिजली मजदूर संघ :– 20 अप्रैल 02 को सालाना अधिवेशन दसुहा में हुआ। प्रतिनिधी संख्या 200 रहीं। 16 अप्रैल 02, 16 मई 02, 4 मार्च 03 एवं 26 मार्च 03 को बिजली बोर्ड के निजीकरण करने व कारपोरेशन बनाने के विरोध मे सांकेतिक हडतालें की गयी।
4. टैकसटाईल कर्मचारी महासंघ :– पंजाब में टैकसटाईल उद्योग में कुल 17 युनियनें पंजीकृत है। इस उद्योग की प्रदेश में बहुत अच्छी हालत नहीं है। केन्द्रीय व सहकारी मिलें बन्द हो गयी है। फिर भी दो बडी कम्पनीयों में अपनी युनियनें मान्यता प्राप्त है। (1) जे सी टी मिल फगवाडा, (2) वर्धमान स्पीनिंग मिल लुधियाना। इन कंपनीयों ने

20प्रतिशत बोनस दिया । दो साल बाद 2004 में 5.50 रुपये प्रति कर्मचारी प्रति दिन वेतन में बढोतरी व 20 प्रतिशत बोनस दिलाया गया।

5. इंजिनिअरिंग कर्मचारी महासंघ, पंजाब :– इस उद्योग में इस समय कुल 25 युनियनें पंजीकृत है। इस उद्योग पर सरकार की गलत नितीयोंका असर हुआ है। जिस कारण अनेक उद्योग बन्द हो गये है। इस कारण अपना काम प्रभावित हुआ है। इन तीन वर्षो में विशेष रुप से डेराबस्सी, फगवाडा, लुधियाना, अमृतसर जालन्धर में काम बढा है। नयी युनियनें रजि. हुई है।

6. आंगनवाडी महिला एण्ड सहायक संघ, पंजाब :– इस महासंघ का काम पिछले तीन वर्षो में वडी तेजी से बढा हैं इस समय पटियाला, संगरुर, लुधियाना, गुरदासपुर, अमृतसर, बठिण्डा, आदि जिलों में काम है। 16 नवंबर 02 को प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय सम्मेलन लुधियाना में सम्पन्न हुआ। जिसमें 450 बहनों ने भाग लिया। 20 नवंबर 04 को लुधियाना में प्रदेश स्तरीय आंगनवाडी एवं महिला सम्मेलन हुआ।

7. पंजाब भठ्ठा मजदूर संघ, एफ सी आई मजदूर संघ, जंगलात कर्मचारी संघ, खेतीहर मजदूर संघ, पंजाब होटल व टुरिझम इन्डस्ट्रीज, कैमिकल व डिस्टलरिज, लैदर व रबड इन्डस्ट्रीज, रेल्वे, बैंक, बीमा, ग्रामीण बैंक, पोस्टल व प्राइवेट हस्पताल, स्पोर्टस्, फर्टीलाइजर, थर्मल प्लांटस्, डैम, हैडल प्रोजेक्ट, रिक्शा/रेहडी, वेल्डींग, कन्सट्रन्कशन, शुगर, साबुन, शाप, टेलरिंग, कलब, रोडवेज कारपोरेशन, सॉ मिल, माडल स्कूल, राइस शैलर आदि में अपना काम है।

8. विशेष कार्यक्रम :–

   1. विशाल रैली चण्डीगढ – केन्द्र के आहवान पर पंजाब में 25 सितंबर 02 को प्रदेश की राजधानी चण्डीगढ में विशाल रैली की गयी। सन्मा. राजकृष्ण भक्तजी का मार्गदर्शन मिला। रैली 17 सैक्टर बस अड्डा से शुरु होकर सरकारी कार्यालयों से होती हुई मटका चौक पंडाल स्थान पर जलसे के रुप में बदल गयी।
   2. प्रदेश अधिवेशन – पंजाब का प्रदेश अधिवेशन 30,31 मई तथा 1 जून 03 को फगवाडा में सम्पन्न हुआ। प्रतिनिधी संख्या 248 थी। जिसमे 50 बहनें थी।
   3. अभ्यास वर्ग – पंजाब का प्रदेश अभ्यास वर्ग नंगल में 24,25 एवं 26 सितंबर 04 को संपन्न हुआ। (120) विभाग अभ्यास वर्ग – 28 फरवरी 04 को बठिण्डा विभाग

(50) 13 मार्च 04 को पटियाला विभाग (150) 14 मार्च 04 को लुधियाना विभाग
(25) 16 मार्च 04 को कपूरथला विभाग (45) 27 मार्च 04 को अमृतसर विभाग
(57) 28 मार्च 04 को जालंधर विभाग (65)

9. स्थापना दिवस – इन तीन वर्षोमें स्थापना दिवस, माँग सप्ताह एवं जनजागरण अभियान के रुपमें, रैलीयाँ, जुलुस, एवं करपत्र बाँट कर मनाया जा रहा है।

10. राष्ट्रीय श्रम दिवस 17 सितंबर – इस दिन राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रुपमें संगठन बढाने की दृष्टी से कार्यक्रम होते है। अनेक संस्थानों में मई दिवस के स्थान पर मजदूर विश्वकर्मा पुजा को मान रहा है।

11. 25 मार्च – गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस एवं 12 दिसंबर स्वदेशी दिवस के रुप में कार्यक्रम आयोजित होते है।

12. प्रदेश की सर्वपंथ समादर मंच की इकाई गठीत हुई है।

राजस्थान प्रदेश

राजस्थान प्रदेश के 32 जिले है और सभी जिलों मे अपनी कार्यसमितीयाँ कार्यरत है। प्रदेशके 241 तहसील है और हमारी 171 तहसीलो में समितीयाँ गठीत हूई है।

16 अप्रैल 02 की हडताल पुरे प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्रमें सफल रही। उसके तुरंत बादही प्रदेशमें अक्तुबर 02 के कार्य्रमकी पूर्व तैयारीयाँ शुरु हुवी। पुरे प्रदेशके दो बार प्रवास हूए।

विश्व व्यापार संगठन, बेरोजगारी एल.पी.जी नितीयाँ आदीके विरुध्द जिला स्थानों पर एवं उद्योग इकाईयों में सैकडो सभाएँ और प्रदर्शन हूए।

भा.म.संघ, भारतीय किसान संघ एवं स्व.जा.मंच के साँझे प्रदर्शन प्रदेशमें 2 स्थान पर हूए।

दि.29/9/02 को जोधपूर में भारी प्रदर्शन हूआ। जिसमें 6000 किसानों ने सहभाग दिया। नारे, जुलुस एवं आमसभा हूई। प्रसिद्धी खूब मिली।

दि.2/10/02 को जयपूरमें ऐतिहासीक आम सभा हूई। वृत्तपत्रोंने अग्रलेख लिखे। दरमियान इस आन्दोलन की तैयारी के लिये 7 से 9 अप्रैल 2002 को उदयपूर में अभ्यास

वर्ग हूआ। (175) अगस्त 2002 को प्रदेश में ग्रामीण बैक अधिकारीयों का कोटा में प्रान्तीय अधिवेशन संपन्न हूआ। (400) नोबो का प्रान्तीय अधिवेशन 16/3/03 को जयपूरमें हूआ। प्रदेशका त्रैवार्षिक अधिवेशन 25–26 मई 03 को अजमेर में संपन्न हुआ। 650 प्रतिनिधी आये थे।

2003 के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशभर प्रदर्शन पखवाडा मनाया गया। सभी जिलो में भारी प्रदर्शन हुआ। जैसे भीलवाडा (700), अजमेर (1500), सिरोही (1100), उदयपूर (700), जयपूर डुंगरपूर, बॉसवाडा (500). इस वर्ष प्रदेश में नये संगठन भी जूडे। थडी ठेला मजदूर (300), असो अल्कोहोल बुअरीज (110) विद्युत, कपडा, खदान आदी.

आंगनवाडी का काम राजस्थान में खूब बढा। 4/06/03 को धरना कार्यक्रम हूवा। दि. 30/6/03 को मुख्यमंत्री आवस पर भारी धरना (4000) हुआ एवं ज्ञापन दिया। प्रधानमंत्री अभिनंदन कार्यक्रम में प्रदेश की 150 बहने गयी।

2004 में और नये संगठन जूडे। जैसे मोन्टो मोटर्स, थडी ठेला जयपूर, श्रीराम फलसब्जी विक्रेता, वनवासी कृषि सुरक्षा कर्मी, हलवाईयों का प्रदेशभर का संगठन भी बना है। एवं प्रदेशस्तरीय अधिवेशन भी संपन्न हूआ है।

एन.ई.आई. जयपूर उद्योग के चुनाव में सीटु को छोडकर सभी श्रमिक भा.म.संघ से जूड गये। चुनावमें भारी बहुमत प्राप्त हूआ। 17 जनवरी 03 को महत्वपूर्ण समझौताभी हूआ। सीटू का 11 लाख श्रमिकों को लौटाया।

28–29 दिसंबर 03 को विद्युत का प्रान्तीय अधिवेशन जयपूर में हूआ (4000)

2004 का पुरा वर्ष गतिविधीसे भरा हूआ रहा है। नये संगठन एवं उपलब्धी बिनानो सिमेंट में मान्यता, परसुराम पुरीया उद्योगमें सीटु श्रमिक विरोधी समझौता निरस्त किया। अन्नपूर्णा उद्योग से सीटूका विलय, गोईटेज इंडिया समझौता, भिलवाडा के इंटक को छोड 600 विद्युत श्रमिक भा.म.संघ में आये। जे के लॉन अस्पतालका संगठन जूडा (210) भिलवाडा के इझड वस्त्रोद्योग कर्मी (600) इंटक छोडकर शामिल हूए है। 45 दिन हडताल के बाद समझौता।

आंदोलन–1) सिंचाई विभाग उदयपूर के ठाट तबादले आंदोलन से निरस्त 2) कृषी मंडी जयपूर में 5 दिनकी हडताल के बाद समझौता 3) सीकर की 400 आंगनवाडी महिला

जबरन सेवा मुक्त किये। आंदोलन के बाद आदेश वापस हूआ। मोंटो मोटर्स अलवरमें ठेका श्रमिक आंदोलन कर रहें है।

आंदोलनों के बाद नये संगठन जुडे सफाई कामगार बीकानेर, पैरामाउंट सर्जीकेम, अलवर, गोदरेज मजदूर संघ अलवर, बिरला व्हाईट जोधपूर, रुची वीअर्स, इसूजी एक्स्पोर्टस्, जलदाय कर्मचारी, सवाई माधोपूर

अभ्यासवर्ग :– 9,10,11 अप्रैल 04 –प्रदेश स्तरीय शिक्षावर्ग बाँसवाडा (112) आमसभाका आयोजनभी हूवा।(3500)

अधिवेशन :– सिरोही जिला अधिवेशन 28/12/04 (6000)

उदयपूर संभाग सम्मेलन 9 अक्तुंबर 04 (4500)

कोटा संभाग आंगनवाडी 5 फरवरी 05 (2000)

जयपूर में उद्योग प्रशिक्षण संस्थानों के 72 स्थानों के 468 प्रतिनिधीयों का प्रान्तीक अधिवेशन दि.20/9/04 को हूवा।

विशेष वृत्त :– प्रदेश महिला विभाग का गठन हूवा है। राज्य परिवहन निगम के 5000 श्रमिको ने मुख्यमंत्री आवास पर धरना 18/2/05 को दिया। बाद में योजना बनी अब परिवहन मुनाफेमें। प्रदेश अध्यक्ष शंभुसिंह खमेसरा(84), उपाध्यक्ष ऋषीराज शर्मा(58), केन्द्रीय कार्य समिती सदस्य दामोदरजी शर्मा(रिल) कोटा का इस कार्यकाल में दु:खद निधन हूआ है।

तामिलनाडू प्रदेश

तामिलनाडू प्रदेशके 31 जिले है। उनमें से आधे से अधिक जिलों में भा.म.संघ की इकाईयाँ कार्यरत है। काम अहिस्ता से बढ रहा है, एवं ऐसे उद्योगों मे फैल रहा है, जहाँ पँहुच नही थी। उदा. संगठीत क्षेत्र में बिजली एवं असंगठीत क्षेत्र में मत्स्योद्योग।

16 अप्रैल 02 की हडताल सार्वजनिक क्षेत्रमें पुरी सफल हुवी। अप्रैल में द. क्षेत्रके प्रतिनिधीयोंकी बैठक हुई। भा.म.संघ की प्रेरणा से चलनेवाले ट्रस्ट के समस्याओंकी चर्चा इस बैठक में हूई। जून 02 में नागरकोविल जिलेका कार्यालय शुरु हुआ।

जुलाई 02 में परिवहन उद्योगके कार्यकर्ताओंका शिक्षा वर्ग कोईम्बतोर में हुआ। अगस्त 02 में चेन्नै में क्षेत्र की बैठक हुई। असंगठीत क्षेत्र के लिये मा. अग्घीजी का प्रवास अगस्त में एक हप्ते के लिये हुआ। सितंबर 02 में कोइम्बतोर में भा.म.संघ, भारतीय किसान संघ एवं स्वदेशी जागरण मंच की संयुक्त सभा एवं जुलूस का कार्यक्रम हूआ। मा. ठेंगडीजी का कोईम्बटुर में नवंबर 02 मे तीन दिन का प्रवास हूआ तथा केन्द्रीय संचालन समिती की बैठक भी हूई।

8/9 फरवरी 2003 को भा.म.संघ तमिलनाडू प्रदेश का अधिवेशन होसुर में हूआ। रैली हूई। प्रतिनिधी सत्र हूआ तथा आम सभा भी हूई।

श्रमिकीकरण पर मदुराई जिलेके थिरुवेदगम में विवेकानन्द कोलेजके विद्यार्थीयों का शिक्षावर्ग 15/2/2003 को भा.म.संघ ने कराया।

बेंगलूर के लीगल सेल की दि. 8/9 मार्च 03 के क्षेत्रिय कार्यशाला में प्रदेश के पदाधिकारी उपस्थित थे।

बिजली एवं राज्य परिवहन के कार्मिको का प्रदेशस्तरीय प्रदर्शन चेन्नैमें 12/3/03को हूआ।

प्रा. फंड क्षेत्रीय कार्यालय के सामने दि. 21/03 को प्रदर्शन हूआ। शेलेम जिले का अधिवेशन 10 मई 2003 को संपन्न हूआ। कन्याकुमारी का जिला अधिवेशन 18/5/03 को हूआ। प्रदेश के लिगल सेल की बैठक 8 जून 03 को हूई।

नागरकोविलमें राज्य परिवहन का शिक्षा वर्ग दि. 22 जून 03 को संपन्न हूआ।

जिला स्तरीय आन्दोलनों के तहत 15 दिन के स्वदेशी यात्रा का प्रदेशमें आयोजन किया था। दि. 28/8/03 को नागरकोविल से शुरु होकर यह यात्रा कोईम्बतोर में दि. 14 अगस्त03 में संपन्न हूई। 5000 से अधिक कार्यकर्ताओं का सहभाग रहा।

दि. 17 सितंबर03 को विश्वकर्मा दिवस के शुभ अवसर पर पॉण्डेचरी के कराइकतल में भा.म.संघ के काम की शुरुआत हूई।

दि. 16/12/03 को टेक्साटाईल श्रमिको का प्रदर्शन कोईम्बतोर में हूआ।

इ आर पी मिलस् के 18 श्रमिकोंको मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले से काम मिला।

जनवरी 04 में नेवेली में प्रदेश की कार्यसमिती बैठ हूई। एवं अन्य बैठके भी हूवी। जनवरी 04 में मा.अग्घीजीका कनकेयम एवं कोइम्बतोरमें असंगठीत क्षेत्रके लिये दौरा हूआ।

फरवरीमें पालघाट (केरल) में क्षेत्रीय बैठक हूई। प्रदेश महामंत्री, अध्यक्ष उपस्थित थे। उदुमालपेट (कोयम्बतोर) में टेक्सटाईल उद्योग शिक्षा वर्ग फरवरी 04 को हूआ।

आर वी सुब्बारावजी एवं उदयराव पटवर्धनजी का चेन्नै में कार्यक्रम हूवा। जून 2004 प्रदेश के तमिळनाडू मिनावती संघमकी शुरुआत हूई।

भारतीय रेल मजदूर संघ का त्रैवार्षिक अधिवेशन जून 04 में चैन्नेमें संपन्न हूआ।

अगस्त एवं सितंबर 04 के महिनोमें वेलपराय के एन इ पी सी इस्टेट के (400) श्रमिकोने एवं निलगीरी के बॅरी ॲग्रो इस्टेट गुडलूर के श्रमिकोने भा.म.संघ की सदस्यता ली।

टेक्स्टाईल ट्रान्सपोर्ट, इंजिनिअरींग के करीब 100 केस में प्रदेश ने न्याय दिलाया है।

रानीपेट के ग्रीव्हज कम्पनीके साथ रु 2000/– प्रतिमाह की वेतनवृध्दी समझौता हूआ। कोइम्बतोरमें रु.600/–, रु 800/– प्रतिमाह वृद्धी दिलानेवाले कई समझौते हूए है।

बिजली उद्योग के प्रदीर्घ कानूनी संघर्ष के बाद निगममें अपने संगठनको वार्ताओंमें बुलाना शुरु किया है।

उत्तर प्रदेश

प्रदेश में 6 संभाग, 15 क्षेत्र एवं 70 जिलेके सभी जिले कार्ययुक्त है। 58 जिलोमें जिला समितीओ में एवं 8 जिलों में जिला संयोजक है। प्रदेश में पूर्ण कालिक कार्यकर्ता 22 है। वर्ष में प्रत्येक छह माह के अन्तराल पर प्रदेश कार्यसमिती की बैठके 2 बार होती है। पूर्णकालिक कार्यकर्ता के 3 बैठक व पदाधिकारीओं के वर्ष मे 3 बैठके नियमित रुपसे होती है।

वर्ष 2002 :

कार्य का विस्तार : प्रतिवर्ष प्रदेशमें 15 से 20 युनियनोंका गठन नये उद्योगो में हो रहा है। गत अ.भा. अधिवेशन के पश्चात अब तक संगठन मे विस्तार निम्न तालिका से स्पष्ट है।

कार्यक्रम एवं आंदोलन : भा.म.संघ उत्तर प्रदेश द्वारा समय समय पर सफलता पूर्वक आंदोलन किये गये। जिनका विवरण निम्नवत है।

1. 14 मार्च 02 को कर्मचारीओं के समस्याओं के लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना व प्रदर्शन किया गया। 37 जिला केंद्रो पर 8637।
2. 16 अप्रैल 02 को प्रदेशमें समस्त वित्तीय संस्थाओं और केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानो में एक दिवसीय हडताल सफल रही।
3. जनजागरण अभियान : विश्व व्यापार संगठन विश्व बैंक एवं आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोश के विरोध में तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योंगोकी बंदी अथवा निजी क्षेत्रमें दिये जाने की नितीपर रोक लगाये जाने हेतू 17 सितंबर से 29 सितंबर 02 तक जनजागरण अभियान के अंतर्गत स्थान स्थान पर बैठके, गोष्ठीयों व पत्रकार वार्ताए कि गयी।
4. 30 सितंबर 02 लखनऊ विधान भवन पर आयोजित रैली भा.म.संघ अगुवाई में संपन्न हूई। भा.किसान संघ एवं स्वदेशी जागरण मंच के साथ संयुक्त रैली में लगभग 25000 की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिसमें लगभग दस हजार कार्यकर्ता भा.म. संघ के रहे।
5. 29 नवंबर 02 को तत्कालिन प्रदेश मंत्री द्वारा आयोजित श्रम पंचायतमें पांच प्रतिशत दर से मकान किराया भत्ता व 5 प्रतिशत दरसे चिकित्सा भत्ता पूरे प्रदेशमें क्षेत्रीय श्रम कार्यालयोंपर एक दिवसीय धरना दिया गया। 15 स्थान 7538 कार्यकर्ता
6. शिक्षा वर्ग – प्रदेश में कुल 6 स्थानों पर सहारनपूर, जगदीश पूर,(सुलतानपूर) आगरा, मुरादाबाद, गोरखपूर, इलहाबादमें तीन दिवसीय श्रमिक शिक्षा वर्ग (225)

वर्ष 2003:

1. डब्ल्यू टी ओ के विरोध में जनजागरण अभियान : विश्व व्यापार संगठनके विरोध में एवं स्थानिय समस्याओं को लेकर प्रदेश व्यापी जनजागरण व संपर्क अभियान चलाया गयां। भा.म.संघ स्थापना दिवस 23 जलाई 03 से 9 अगस्त तक बडी युनियनोंके बैनरतले द्वार सभायें बैठके जिला केंद्रो पर धरना रैलीओ का आयोजन किया गयां। 45 जिला केंद्रपर धरना एवं रैली 70 सभा 115 बैठके, 7 बडे केद्रो पर पत्रकार वार्ताए आयोजित कि गयी। जनजागरण अभियान पूर्णतः सफल। इसके पूर्व 14 अप्रैल03 से 2 मई तक विशेष जनजागरण अभियान चलाया गयां।

2. 2 सितंबर 03 दिल्ली धरना : स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले संपन्न धरने में भा.म. संघ उत्तर प्रदेश के कुल 1600 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
3. मांग सप्ताह : मकान किराया भत्ता व चिकित्सा भत्ता (5–5 प्रतिशत) अधिसुचना राज्य सरकार जारी करें इस निमित्त 5 नवंबर 10 नवंबर विभिन्न स्थानों पर बैठके, सभा, परचे वितरित किये गये। 11 नवंबर 03 को प्रदेशके सभी 15 क्षेत्रीय श्रम कार्यलयोंपर 1 दिवसीय धरना दे कर मुख्य मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन दिये गये।

वर्ष 2004:

1. कर्मचारियोंके वेतन पूर्नरिक्षण की मांग को लेकर भा.मसंघ के स्थापना दिवस 23 जुलाई से 17 सितंबर 04 (विश्वकर्मा जयंती) आंदोलन चलाया गया।
2. 6 सितंबर 04 को न्युनतम अधिनियम वेतन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन सलाकार बोर्ड की बैठक लखनऊ में संपन्न हुई। भा.म.संघ के प्रतिनिधीयो द्वारा न्युनतम वेतन को जो लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसी प्रस्ताव को बोर्ड में सभी श्रम संघोके प्रतिनिधीयों ने स्विकार करते हूवे श्रमिक पक्ष का प्रस्ताव घोषित करते हूए इसी आधारपर न्यूनतम वेतन रुपये 4200 किये जाने की मांग की गयी। भा.म.संघ का प्रस्ताव चर्चा का विषय बना और बोर्ड के सभी सदस्यों ने इसी आधार पर अपने अपने मन्तव्य प्रस्तुत किये गये। अन्ततः काफी लम्बी चर्चा व बहस के पश्चात अकुशल कर्मचारियों का न्यूनतम वेतना रु 3500/– प्रति माह की सहमति बनी और इस निर्णय की अनुशंसा शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
3. 22 नवंबर 04 को न्युनतम वेतन सलाहकार बोर्ड द्वारा शासन को भेजी गयी अनुशंसा पर अधिसुचना जारी किये जाने की मांग को लेकर लखनऊ विधान सभा भवन पर एक दिवसीय धरना दिया गया एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया।
4. 23 जुलाई 04 स्थापना दिवस पर समस्त जिला केंद्रोपर निर्णय के अनुसार प्रदर्शन 35 जिला केंद्रापर कार्यक्रम संपन्न हुवे। जिसमें 9537 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
5. 17 सितबर विश्वकर्मा जयंती पर कुल 38 स्थानोंपर भारी संख्या में कार्यक्रम संपन्न हुए।

वर्ष 2005

1. 19 जनवरी 05 को प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय श्रम कार्यालयों पर बडे पैमाने पर एक दिवसीय धरना दिया गया। प्रदेश में 15 स्थानोंपर संपन्न धरनों में कुल 18617 की संख्या रही।

2. 15 फरवरी 05 को अनुसुचित उद्योगोंके कर्मचारीओं द्वारा एक दिवसीय हडताल पुरे प्रदेश में सफल रही।

उपलब्धी :

विगत 3 वर्षो की प्रदेश में प्रमुख उपलब्धीयाँ निम्न वत है।

अ. कानपूर स्थित हारनेस फैक्टरीमें संपन्न वर्कस कमिटी चुनावमे सभी 10 स्थानोंपर भा. म.संघ संबंध युनियन के कार्यकर्ताओंको सफलता प्राप्त हुई। एवं प्रतिष्ठानमें लाल झँडे का वर्चस्व टुटा।

ब. प्रदेशके शुगर उद्योग मे कार्यरत कर्मचारीओं की वेतन पुर्नक्षण समझौता 15/2/05 संपन्न हुआ। (350 से 650 तक)

स. लाल इमली ब्रांच कानपूर में 25 जनवरी 05 को वेतन पुर्नक्षण समझौतेमें 350से 1200 की वेतन वृद्धी।

द. इंडकोट फुटवेअर कानपूर समझौते में 200 की वेतन वुद्धी।

रचनात्मक एवं विधाई कार्य :

रायबरेली में संपन्न भा.म.संघके 28वे त्रैवार्षिक अधिवेशन के अवसर पर स्वर्गीय रामनरेश सिंह (बडे भाई) स्मृती समिती की स्थापना कि गई। समिती के माध्यमसे कुछ रचनात्मक एवं विधाई कार्य किये जानेका निर्णय लिया गया। श्रध्देय दत्तोपंत ठेंगडीजीने समितीकी गठन के घोषणा के साथ उसके उद्देशोंपर प्रकाश डाला।

श्रमिक संघ दोराला डी सी एम श्री राम इंडस्ट्रिज लि, मेरठ के माध्यमसे प्रतिवर्ष विधवा महिलाओं को शिलाई मशीन एवं अल्पआय वर्ग कमजोर एवं निर्धन बच्चोकी शिक्षा हेतू पाठ्य सामग्रीका वितरण किया जाता है।

उत्तरांचल

उत्तरांचल राज्यके 13 जिले है। और सभी जिलों मे अपना काम है । 2002 के वर्ष मे प्रदेश केंद्र की योजना से बने आंदोलन के कार्यक्रम पूरे किये गये। 16 अप्रैल 2002 को प्रदेश के सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद थे। सभी जिलोमे संपर्क प्रवास करके डब्ल्यू.टी.ओ. के खिलाफ आंदोलन की तैय्यारीयाँ की थी। कार्यक्रम प्रभावी एवं सफल रहा।

7–8 जून 2003 को देहरादून मे प्रदेश अधिवेशन सफल संपन्न हुआ। 23 जुलाई से 9 अगस्त के पखवाडे मे 12 जिला स्थानों पर सभाएँ हुअी। एवं आंदोलन के कार्यक्रम हुए। तराई बीज निगम, पनाभानू विश्व विद्यालय, एचएमटी, बीएचईएल, आंगनवाडी, रोडवेज आदी उद्योगों पर बडी सभाएँ हुअी। एवं उद्योगों का प्रदर्शन हुआ।

नैनिताल उधमसिंहनगर, हलद्वानी, गदरपूर एवं किच्छा इस स्थानों पर प्रभावी प्रदर्शन हुए। रैली निकालकर ज्ञापन दिया।

आंगनवाडी का काम प्रदेश मे जोरसे बढ रहा है। सभा सम्मेलन एवं माँगो के लिये प्रदर्शन के कार्यक्रम 13 मे से सात जिलों मे संपन्न हुए है। पुरे प्रदेशमें अब काम फैल गया है।

देहरादूनमे प्रदेशद्वारा भारी प्रदर्शन दिया गया। एवं श्रमिकोंकी माँगपर सरकार द्वारा संयुक्त बैठक न बुलाने पर अपना रोष प्रकट किया।

प्रदेश के श्रममंत्री ही केंद्रीय श्रम संगठन इंटक के अध्यक्ष है, और भेदभाव एवं पक्षपात की राजनिती करते है। सदस्यता सत्यापन मे भा.म.संघ के सारे संगठन खारीज कराने का प्रयास भी सरकार कर चुकी है। इस उत्पीड़न के विरुद्ध प्रदेश मे श्रमिकों का क्रोध उबल रहा है।

पश्चिम बंगाल

प्रदेशके 18 जिले है और 13 जिलों मे समितीयाँ एवं 5 जिलों मे संयोजक है। 56 विभागों में से 28 विभागों में काम है।

उपलब्धीयाँ –

1. सीटू इंटक आयटक को छोडकर कस्टम, जी एस आई, एल आय सी, जूट, रेलवे और बीडी, हॅण्डलूम, खेतिहर मजदूर जैसे असंगठीत क्षेत्रके कई मजदूर/कार्मिक भा.म. संघसे जूडे।
2. बी एस एन एल के ठेका श्रमिकों के वेतन वृद्धी एवं काम की बहाली भा.म.संघ के प्रयास से हो पायी।

3. भारत का सबसे बडा बर्नपुर का इस्को स्टील प्लांट, भा.म.संघके प्रयाससे फिर जीवित हूआ है। अब वह ठीक चल रहा है एवं मुनाफामी कर रहा है।

4. 5/1/2000 एवं 8/1/2004 के दो श्रमिक विरोधी समझौते जूट उद्योग में सीटू, इंटक, आयटक आदी 12 संगठनों ने किये थे। जिसमे वेतन कटौती को स्वीकारा था। भारतीय जूट मजदूर संघ (भा. म. संघ) ने छोटी बडी हडताल करके समझौते लागू नही होने दिये। आन्दोलनमें 80: श्रमिक जूडा हूआ था।

वर्ष अनुसार गतिविधी 2002

17–19 मई 02–राज्य कर्मचारीयो का 7वाँ अधिवेशन मिदनापूर में हूआ।

23 जुलाई – स्थापना दिवस जिला स्तरपर/इकाईयों में संपन्न

17 सितंबर – विश्वकर्मा दिवस के एवं रक्षा बंधन के कार्यक्रम हूए।

27 सितंबर – सरकार की श्रमविरोधी नितीयोंके विरुध्द एक भारी जूलुस एवं सभा कलकत्ता में आयोजित की थी। 10000 श्रमिक पुरे प्रदेश से आये थे।

8 डिसंबर 02 को राज्य कर्मचारीयों ने शिक्षा वर्ग का आयोजन किया (40)

प्रदेशके पूर्व अध्यक्ष श्री सुनिल कुमार चटर्जी का दि. 22 अक्तुंबर02 को एवं केन्द्रीय संचालन समिती सदस्य श्री रासबिहारी मैत्र का 3/11/02 को दुःखद स्वर्गवास हूआ।

2003

दि. 15/3/03 को हॅण्डलूम श्रमिको के लिये सेमिनार का आयोजन नवद्विप में हूई थी।(150). दि. 19/20 अप्रैल 03 को चित्तरंजन में प्रदेशका त्रैवार्षिक अधिवेशन संपन्न हूआ। (700) 2003 के मई माहमें कोलकता में प्रदेशस्तरीय शिक्षावर्ग का आयोजन हूआ।

जुलाई एवं अगस्त 03 में विश्वव्यापार संघ की नितीयों का विरोध करने के लिये जिला स्तरीय सभा एवं जूलुस की आयोजना हूई। प्रदेश के 25 कार्यक्रमों मे 250 से 2500 की उपस्थिती रही।

12/8/03 को प्रदेश महिला विभाग की ओर से रक्षाबंधन का कार्यक्रम हूआ(80)

15/9/ से 19/9/03 कोलकोता में अभ्यास वर्ग हूआ (40) राष्ट्रीय श्रम दिवस ही श्रमिक दिवस है। इस संकल्पना पर संगोष्ठी का आयोजन दि. 16/9/03 को हूआ। कई संगठन सहभागी हूए।

प्रदेश के सर्व पंथ समादर मंच का अधिवेशन दि. 12/10/03 को मा. ठेंगडीजी ने संबोधित किया।

परितोष पाठक पूर्व क्षेत्र प्रभारीका दि.30/11/03 को दुःखद देहान्त हूआ।

2004

नडिया जिले के धुबुलीया में प्रदेश के महिला विभाग का अधिवेशन संपन्न हुआ। 2,3 मार्च 04 को भारतीय जूट मजदूर संघ का अ.भा.अधिवेशन संपन्न हूआ।(658)

टेक्साटाईल उद्योग का अधिवेशन कोलकतामें दि. 11/4/04 को संपन्न हूवा। अ.भा. हॅण्डलूम मजदूर महासंघ का अ.भा. अधिवेशन नवद्विप में संपन्न हूआ।

स्थापना दिवस पर मणिकतला के भा.म.संघ कार्यालय का भुमिपुजन समारोह हूआ(500) एवं रक्षा बंधन कार्यक्रमभी हूआ।

21/11/04 सरकारी कर्मचारीयों का द्विवार्षिक अधिवेशन कोलकतामें संपन्न हूआ।

31/12/04से 2 जनवरी 05 हुगळीमें प्रदेश शिक्षा वर्ग (नये 75 कार्यकर्ता)

भारतीय वस्त्रोउद्योग कर्मचारी महासंघ

भारतीय वस्त्रोद्योग कर्मचारी महासंघ देश के कपडा उद्योग में कार्यरत बहुमत प्राप्त श्रमिकों का अग्रणी संगठन है।

महासंघ का कार्य देश के 22 राज्यों में जिनमें आंध्रप्रदेश, बिहार, उडिसा, चण्डीगढ, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू–काश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, झारखण्ड, उत्तरांचल, विदर्भ, तामिळनाडू और केरल आदि में है।

महासंघ से संबंधित 31–12–2002 के आकडो के अनुसार देश में 272 रजिस्टर्ड इकाईयां है जिनकी सदस्य संख्या 4,39,426 है।

महासंघ की इस समय 12 प्रदेशों में प्रदेश इकाई गठित है, बाकी प्रदेशों में इकाई गठन का कार्य जारी है।

सरकारी आंकडों के अनुसार वस्त्र उद्योग की संख्या 1866 है। जिसमें 192 सार्वजनिक क्षेत्र में 159 सहकारी क्षेत्र में, एवं 1515 मिले निजी क्षेत्र में है इसमें 1588 स्पिनिंग मिले है, एवं 278 कम्पोजिट मिले है जिनमें से 30–9–2003 तक 521 मिले बन्द हो गई है।

भारत सरकार द्वारा 12 नवम्बर 2001 को एन.टी.सी. की 119 मिलो में से 53 चलाने एवं 66 मिले बन्द करने की घोषणा की गई थी। लेकिन इसमें कोई प्रगति नहीं हुई।

सरकारी वस्त्रनीति वर्ष 1985 में श्री आबिद हुसैन जी की शिफारिशों के तहत राष्ट्रीय वस्त्र नीती की घोषणा की, वर्ष 2000 में सत्यम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वस्त्र नीती की घोषणा की जो आज भी लागू है। आज देश के वस्त्र उद्योग में 92 प्रतिशत असंगठित श्रमिक हैण्डलूम पावरलूम, होजरी, गारमेन्ट, ऊन, सिल्क, खादी आदि में कार्यरत है लेकिन आज तक उनके बारेमें जिक्र तक नहीं किया। 30 अप्रैल 2003 को भारतीय मजदूर संघ के पहल पर सभी राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिनिधीयों को एक बैठक आयोजित कर सरकार पर त्रिपक्षीय बैठक बुलाने का दबाव बनाया गया था। 15 दिसम्बर 2003 में त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन हुआ।

श्रमिक हित में महासंघ के प्रयास

महासंघ द्वारा पिछले तीन वर्षों में श्रमिक हित की रक्षार्थ केंद्र व प्रदेशों में धरने देकर मांग पत्र दिये गये, प्रदर्शन किये गये, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को हजारों श्रमिकों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिये गये। कई बार कपडा मंत्री से मिलकर श्रमिकों की समस्या जिनमें प्रमुख नया वेतनमान निर्धारण करने, बन्द कारखानों को चालू करवाने, श्रमिको के बकाया का भुगतान करवाने, सभी वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस दिये जाने, भविष्यनिधी की व्याजदर 12 प्रतिशत करवाने मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आदि प्रदेशों में आई.आर. एक्ट को रद्द करने आदि समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया।

अभ्यासवर्ग :

महासंघ के प्रयास से केरल, तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल मे अभ्यासवर्ग (स्टडी क्लास) आयोजित किये गये।

नई यूनियनों का गठन

महासंघ द्वारा राजस्थान, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ में नई सात यूनियन रजिस्टर्ड करवाई है। महासंघ का त्रैवार्षिक अधिवेशन दि. 12–13 जून 04 को भोपाल के दीनदयाल परिसरमें संपन्न हुआ। नये वेज बोर्डकी माँग हुई, नयी वस्त्रनीती, सभीको बोनस, बन्द मिलोको खोलना, आदी प्रस्ताव अधिवेशन मे पारित हुए।

भारतीय ज्यूट मजदूर संघ

भारतमें ज्यूट की 73 फॅक्टरी है और यह उद्योग 7 राज्यों में फैला हूआ है। इसके अतिरिक्त सैंकडो छोटी छोटी इकाईयाँ काम करती है। बी जे एम एस की 56 युनियने है। एवं सदस्यता 60 हजार से उपर है। पश्चिम बंगाल में 85प्रतिशत उद्योग है। सभी केंद्रीय श्रम संगठनों कें युनिट इस उद्योग में चल रहें है। भा. म. संघ और अन्य चार छोटे संगठन वेतन समझौते का 2002 से विरोध कर रहें है जो त्रिपक्ष स्तर पर अन्य संगठनों ने किया था एवं वेतन घटाकर 175/– से उसे 100/– रुपया कर दिया। इसही बार इन्ही केंद्रीय श्रम संगठनों ने सरकार के साथ मिली भगत बनाकर एक समझौता दि.8/1/04 और 27/1/04 को बनाया। किन्तु इन पुरस्कृत संगठनों को सफलता नहीं मिली। भा.म.संघ ने लगातार हडताल आंदोलन आदी कर के उसे रोका है। इसलिए भा.म.संघ बढ रहा है और इस उद्योग का सबसे बडा संगठन है।

भारतीय ज्यूट मजदूर संघ का अखिल भारतीय अधिवेशन दि. 2–3 मार्च 04 को काकीनाडा (प.बं) में संपन्न हूआ। (950)

अखिल भारतीय इस्पात मजदूर संघ

महासंघकी 2002 के आधारपर 96,692 सदस्यता है। एवं 53 संगठन संबद्ध है।

महासंघकी कार्यसमिती की 2 बैठके 2002 मे हुई। 2003 मे तीन बैठके हुअी। 15–16 मई 04 को राऊरकेला मे (इस्पातनगर उडीसामे) बैठक संपन्न हुई। 4–5 सितंबर 04 को भिलाई मे बैठक हुअी। भिलाई एवं दुर्गापुर मे महासंघ का काम बढ रहा है।

आंदोलनः

7 अगस्त 2003 को महासंघ के आदेश पर बोकारो, दुर्गापूर, बर्नपूर, राऊर केला मे एक दिवस का प्रदर्शन हुआ। इसी तिथीको मेघाहातुबुरु, किरीबुरु, चिरीमा, गुवा, माईन्सपर एक

दिवसीय धरने का कार्यक्रम हुआ।

अधिवेशनः

महासंघका त्रैवार्षिक अधिवेशन दुर्गापूर मे दि 21–22 फरवरी 04 को संपन्न हुआ। देशभरमें 250 प्रतिनिधी आये थे।

अभ्यासवर्गः

दि. 8–9 जनवरी 2005 को मेघाहातुबुरू मे महासंघ का शिक्षा वर्ग हुआ (40)

समाजहित कार्यः

बर्नपूर (प.बंगाल) मे महासंघ के सौजन्य से समाजहित उद्देश्य की पूर्ती के लिये मई 03 से अगस्त 2004 के कालमे चिकित्सा शिबीर हप्ते मे 3 बार होता है। सैंकडो श्रमिक लाभान्वित हुए है।

भारतीय इंजिनिअरिंग मजदूर संघ

भा.म.संघके काम के पहले दशक में सात महासंघो का निर्माण हुआ था और उनमेंसे यह महासंघ भारतीय इंजिनिअरिंग मजदूर संघ नामसे काम कर रहा था। देशके सभी प्रदेशो में महासंघ का काम है। वर्ष 2002 के आधार पर महासंघ की इंजिअरिंग उद्योग में 3,39,605 सदस्य है एवं 402 युनियने पंजीकृत है। मेटल उद्योग की सदस्यता 12,934 एवं 26 संगठन भी इसी में जुडते है। वर्ष 2002 में केन्द्रीय श्रम मंत्रीजी ने महासंघ के अनुरोध पर उच्च स्तरीय त्रिपक्ष वार्ता कई वर्षों के बाद कराई है। वर्ष 2003 में महासंघ का अ.भा.अधिवेशन 5,6 जून 04 को (250) जयपूर में संपन्न हूवा। 8 प्रदेशों से प्रतिनिधी आये थे।

दि. 10 सितंबर03 को देशव्यापी स्थानीय धरनोंका कार्यक्रम हुआ। देशके हजारों कार्यकर्ताओंने सहभाग दिया। बोनस, न्युनतम वेतन निर्धारण, प्रति तीन वर्षो के लिए वेतन समझौता पुर्ननिर्धारण की व्यवस्था आदी मांगे लेकर यह धरना हुवा था। उ.प्र., बिहार, झारखंड, पं.बंगाल, उडिसा, हिमाचल, एवं दिल्ली में महासंघकी बैठके हुई।

स्थापना दिवस 2004 के कार्यक्रम महाराष्ट्र में बडे पैमाने पर हुए।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ

इस महासंघ की स्थापना 13 अगस्त 67 को दिल्लीमें हुई। तब महासंघ की 5 युनियने थी। अभी 250 संगठन है और 1,50,947 की सदस्यता है। इनमेसे 52 संगठनोंको वैधानिक मान्यता मिली है। शेष संगठनो ने भी अपनी मान्यता का दावा प्रस्तुत किया हूआ है। देशमें 29 स्थानों पर वर्कस् कमेंटीके चुनावोंमें बी पी एम एस ने औसत 60 सीटे जिती है। हार्नेस फॅक्ट्ररी कानपूर, आर्डनेन्स फॅक्ट्री अंबाझरी, गन कैरीज फॅक्ट्री जबलपूर में सभी सिटें जिती। 18 जुलाई 02 को महासंघ का मुखपत्र प्रतिरक्षा भारती इस मासिक पत्रिका के पहले अंकका प्रकाशन हूआ। विमोचन श्रध्देय ठेंगडीजी के करकमलो द्वारा पूणे में हूआ।

17 सितंबर 02 को अॅम्युनेशन फॅक्ट्री खडकी में विश्वकर्मा पुरस्कार वितरण हुआ।

25 सितंबर से 2 अक्तुंबर 02 के देशव्यापी आन्दोलन में सहभाग।12 मई 03 को रक्षा मंत्रालय से माँगोको लेकर वार्ताए हूई। 23 जुलाई से 9 अगस्त 03 देशव्यापी आन्दोलन में सहभाग। 9 अगस्त 03 को संसद भवन नई दिल्ली पर जुलूस हुआ।

15 सितंबर से 30 सितंबर 03 रक्षा प्रतिष्ठानों पर मांगो के संदर्भमें धरने एवं प्रदर्शन हूए। 50प्रतिशत डी ए मर्जर एवं 6वे वेतन आयोग बिठाने की माँगे प्रमुख थी। 9 अक्टुबर 03 को संसद सत्रकाल में संसद पर प्रदर्शन।

12 दिसंबर 03 को 50प्रतिशत मंहगाई भत्तेके मर्जर का लाभ लाखो केन्द्रीय कर्मचारीयोंको दिलाने हेतू संसदपर ऐतिहासीक प्रदर्शन हूवा। आन्दोलन सफल रहा। डी ए मर्जर मिल गया। चार वर्षीय रियायती यात्रा भत्ता दिलवानेमें भी सफलता मिली।

2 अप्रैल 04–ऑर्डनन्स फैक्ट्री बोर्ड कोलकता पर मांगो के संदर्भ में एक दिन का धरना दिया।

2 जुलाई 04–देशभर में माँग दिवस मनाया। मा. प्रधान मंत्रीजी को ज्ञापन भेजा।

4 अक्टु.04 से 9 अक्टु 04 –लंबीत माँगो के लिये माँग सप्ताह पुरे देश में मनाया। रक्षा सचिव को ज्ञापन दिया।

अन्य वृत्त :–

23 नवंबर 04 को खमरियाँ जबलपूरमें महासंघ का त्रैवार्षिक अ.भा.अधिवेशन संपन्न

हूआ। पूर्व प्रधानमंत्री मा.वाजपेयीजी मार्गदर्शन के लिये पधारे। (900)

ओ ई एफ कानपूरके 5 कार्यकर्ताओंका निलंबन समाप्त करानेमें सफलता।नेवल डाक यार्ड मुंबई में कार्यकर्ता उत्पिडनके विरुध्द संघर्षरत।

स्थापना दिवस के कार्यक्रम सभी इकाईयों पर हूए।

कार्यसमिती की बैठक इलाहाबाद में 22/23 मई 04, भण्डारा में 31/08/04, अंम्बाझरीमें 1,2 सिंतबर 04 संपन्न हूई।

क्षेत्रिय बैठके – बंगलोरमें 18 जून 04 को बैठक हूई। कोलकता में 21 जून 04 को बैठक हूई।

अप्रैल 2003 से जून 03 तक देशमें हैदराबाद, बेंगलोर, पूणे, कोलकता, वडमल, बोलनगीर, पठानकोट, इलाहाबाद एवं जबलपूरमें(9)वर्ग हूए।

जे सी एम सदस्योंका 2 दिवसीय वर्ग चांदामें हूवा।

पूणे के ॲम्युनेशन फैक्ट्री खडकी में विश्वकर्मा फुटबॉल प्रतियोगिता हूई।

अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ

अखिल भारतीय विद्युत महासंघ से संबंद्ध 23 प्रदेशों मे 133 पंजीकृत संगठन है। जिसकी सदस्यता 3,35,000 से अधिक है। महासंघ के वृंदावन में हुए 10 वे त्रैवार्षिक अधिवेशन पश्चात महासंघ की संचालन समिती तथा कार्यसमिती बैठकों का विवरण इस प्रकार है।

संचालन समिती :

जलगाँव (महाराष्ट्र) 17 मार्च 2002; भोपाल (मध्यप्रदेश) 17–18 अगस्त 2002; अमरावती (विदर्भ) 21–22 दिसंबर 2002; वडोदरा (गुजरात) 3–4 अगस्त 2003; चेन्नई (तामिलनाडु) 14–15 फरवरी 2004; भावनगर (गुजरात) 26–27 जून 2004;

कार्यसमिती :

उदयपूर (राजस्थान) 7 से 9 अप्रैल 2002; आनंदपूर साहिबा (पंजाब)13–14 नवंबर 2002; कोटा(राजस्थान)27–28अप्रैल 2003; वाराणशी (उत्तरप्रदेश)19–20 अक्तूबर 2003;

नागपूर (विदर्भ) 17–18 मार्च 2004 ; भावनगर (गुजरात) 10–11अक्तूबर2004

कोरबा (छत्तीसगढ)10–11 दिसंबर 2004; आगरा (उत्तरप्रदेश)

पदाधिकारी बैठक; 27–28 फरवरी, एवं 1 मार्च 2005

महासंघ का 11 वा त्रैवार्षिक अधिवेशन भावनगर (गुजरात) में 10–11 अक्तूबर 2004 को संपन्न हुआ। प्रतिनिधी संख्या 950 थी।

महासंघ के अखिल भारतीय स्तर तथा प्रदेश स्तर के अभ्यास वर्गोंका विवरण

अखिल भारतीय स्तर :

उदयपूर (राजस्थान) 7–9 अप्रैल 2002; 137 (सभी पंजीकृत संबद्ध संगठनोंके अध्यक्ष, महामंत्री तथा कोषाध्यक्ष संमिलीत)

प्रदेश स्तर :

गया (बिहार) 20 से 30 अगस्त 2003 (48) ; पुणे (महाराष्ट्र) 27 से 29 जुलै 2002 (208); शिरपूर (महाराष्ट्र) 26 से 28 दिसंबर 2003(154); महावीरजी (राजस्थान) 29–30 जून 2003 (80); कोरबा (छत्तीसगढ) 10–11 दिसंबर 2004 (100)

महासंघ प्रदेश अधिवेशनका विवरण:

महाराष्ट्र,नागपूर (विदर्भ)24 अगस्त 2003 (230); छत्तीसगढ, रायपूर,9फरवरी 04 (1500)

गुजरात,अंबाजी,15 नवंबर 2003(2000) राजस्थान, जयपूर 28–29 दिसंबर 2003(4000); बिहार,मुझफरपूर 19–20 जून 2004 (210)

मध्यप्रदेश,उज्जैन 18–19 सितंबर 2004 (1000); महाराष्ट्र, अमरावती (विदर्भ) 22 से 24 दिसंबर 2002(2500); राजस्थान,कोटा (उत्पादन निगम) 21 जुलाई 2002 (414)

महासंघ के कुछ प्रमुख आंदोलनोका विवरण

1. उत्तर प्रदेशमे निजिकरण के विरोधमे साँझा आंदोलन दि. 18 अप्रैल, 24 अप्रैल एवं 29 अप्रैल 2003.

2. मध्यप्रदेशमे 8 प्रमुख माँगो को लेकर 7 से 23 जुलाई 2003 के पखवाडमे रैलियॉ, सभा, प्रदर्शन.

3. बिहारमें 9 प्रमुख माँगो को लेकर 23 जुलाई 2003 को सामूहिक अवकाश एवं पटना में धरना कार्यक्रम, निजिकरण के विरुद्ध में प्रदर्शन।

4. गुजरातमें क्षेत्रिय कार्यालयोंपर 23 जुलाई 2003 को सफल धरना।

भारतीय रेलवे मजदूर संघ

भा. म. संघके सबसे पूराने महासंघोमें से एक यह महासंघ रेल उद्योगमें पिछले चार दशकोसे काम कर रहा है।

नये क्षेत्र :

पिछले तीन वर्षोमें भारतीय रेलवे मे सात नये झोन बने है। पश्चिम मध्य क्षेत्र, उत्तर मध्य क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, पूर्व मध्य क्षेत्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, तटवर्ती पूर्व क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रोके संघटन पंजीकृत हूए है।

शिक्षा वर्ग :

महासंघके एक्झीक्यूटीव्ह बोर्ड की पटीयाला बैठकमें दि. 8/9 अप्रैल 02 को यह तय हुआ की महासंघ की कार्यशाला रायपूर (छत्तीसगढ) में होगी। उस प्रकारसे रायपूरमें दि. 23/24 अक्तुंबर 02 को यह कार्यक्रम महाराष्ट्र मंडल भवन में संपन्न हुआ।

सुप्रिम कौन्सील बैठक :

महासंघकी सुप्रिम कौन्सील की बैठक तीन वर्ष में एक बार और अधिवशन के पहले होती है। इस रिवाज के अनुसार सुप्रिम कौन्सील की बैठक दि. 15/16 अक्तुंबर 03 को इरण्णा मंगल कार्यालय, सोलापूर में यह कार्यक्रम हूआ।

सभागृहने रेल कार्मिकों की महत्वपूर्ण समस्याओं पर अपने प्रस्ताव पारित किये। 1. छटे वेतन आयोग की स्थापना, 2.50प्रतिशत डीए मर्जर, 3. रेलके निजीकरण का विरोध, 4. हडताल का अधिकार, 5. नयी पेन्शन योजना का विरोध

क्षेत्र स्तरीय शिक्षा वर्ग :

दिनांक 7/8 जून 03 को एम आर के एस, पी आर के पी, पी एम आर एम एस और यू पी आर के. एस संघटनाओंके कार्यकर्ताओंका शिक्षा वर्ग मुंबई में संपन्न हुआ। दि.3/4 डिसें 03 को चेन्नई में डी एम आर के एस, डी आर के एस, एन आर एम एस और आय

सी एफ कार्यकर्ताओंका शिक्षा वर्ग संपन्न हुआ। दि. 28/29 फेब्रु. 04 को जगाधरी में तिसरा वर्ग संपन्न हुआ।

सुनामी पिडीतों की सहायता –

महासंघ से संबध्द आय सी एफ कर्मचारी संघ ने सुनामी पिडीतों की सहायता हेतु तुरंत और उत्सुर्त योजना बनाई। पीडीतोंकी राहत के लिये 100 क्विंटल चावल, 50 क्विंटल दाल, एक लाख रुपयों की दवाईयाँ, 500 नये बरतन एवं 5 लाख रुपया नगद, ऐसी सहायता एनोरे और शिरुबोटीअर के 400 परिवारों को तामिलनाडु में मुहया करायी है।

प्रधानमंत्री सहायता कोष को इसके अलावा 1 दिन का वेतन भी भेजा है।

आंदोलनात्मक कार्यक्रम :

कारखाना बचाव आंदोलन–महासंघ ने दि. 2/6/03 से 6/6/03 तक यह आंदोलन देशभर में चलाया। वर्कशॉप और सभी उत्पादन इकाईं पर दि. 6जून को विशाल धरना हुआ। निजीकरणका विरोध, छटनी का विरोध, श्रमिकों को पर्याप्त काम, प्रशिक्षण आदी मांगे उठायी है।

रेलवे के सभी वर्कशॉप एवं उत्पादन इकाईया पर भारी धरने, द्वारसभायें, जूलुस आदी कार्यक्रम हुए।

जागरण पखवाडा :

दि. 15/9 से 30/9/03 के 15 दिनों मे महासंघ ने जी ई एन सी के निर्देशानुसार प्रदर्शन, द्वारसभा, आदि का आयोजन मंडल स्तर एवं शाखा स्तर पर किया था।

संसद पर प्रदर्शन :

दि. 12 दिसंबर 03 को संसद पर महासंघ ने विशाल धरने का कार्यक्रम जी ई एन सी के निर्देश पर आयोजित किया।

उपलब्धी :

50प्रतिशत डी ए विलय की मांग मा. प्रधानमंत्रीजी ने तत्काल स्वीकार कर ली।

भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ

इस महासंघके 17 प्रादेशिक परिसंघ संबंध्द है। पिछले तीन वर्षासे इस महासंघकी सदस्यता तेजीसे बढ रहीं है। 226 संबंध्द संगठन और 4,68,711 सदस्यता के साथ काम करने वाला यह महासंघ देशका सबसे बडा परिवहन उद्योग का महासंघ है। महासंघके प्रदेशस्तरीय संबद्ध परिसंघो के वित्त सचिवों का शिक्षा वर्ग दि. 17,18 जुलाई 02 को संपन्न हुवा। भा.म.संघके देशव्यापी वर्ष 2002 के आंदोलन में महासंघ सक्रीय था। 18,19 जुलाई 2002 को कार्यसमिती की बैठक हैदराबाद में संपन्न हुई। अगली कार्यसमिती की बैठक 28 जनवरी 03 को बंगलूर में हुई।

28,29 फरवरी 04 को उत्तर प्रदेशके झाँसी में त्रैवार्षिक अ.भा. अधिवेशन संपन्न हुवा। अधिवेशनमें 1727 प्रतिनिधी थे। श्री चेतन देसाई महामंत्री बने। इसी वर्ष में कुछ प्रदेशों के अधिवेशन हुए। 18,19 जनवरी 04 महाराष्ट्र का अधिवेशन शिर्डी में हो गया। (800) 18,19 जुलाई 04 को आन्ध्र प्रदेशका अधिवेशन एवं 27,28दिसंबर को गुजरात के सुरतमें अधिवेशन हुवा। (600) 8 अगस्त 04 को तमिलनाडू प्रदेश का अधिवेशन नागरकोवील में संपन्न हुवा। इस वर्ष तमिलनाडू में काम तेजी से बढा है।

महासंघके चार क्षेत्रोंके वर्ग वर्ष 04 में संपन्न हुए। योजनानुसार दक्षिण क्षेत्र का वर्ग एन एल आय नोएडा में दि. 26/9/ से 1/10/04 तक संपन्न हुआ।

4/11 को महासंघकी कार्यसमिती बैठक नागरकोवीलमें संपन्न हुई। 21/12/को गुजरात एस टी कार्मिकोंकी समस्या के लिए अहमदाबाद में रैली हुई। 35,000 की उपस्थिती थी। तुरंत प्रदेश सरकारने बुलाकर निजीकरण वापस लिया एवं नई बसे खरीदने के लिए पचास करोड रुपया दिये।

2/1/05 को मध्य प्रदेश सरकारने रा.प.निगम बंद करनेकी घोषणा की। साँझा मोर्चा बनाकर धरना दिया। दिनांक 23 जनवरी को मा. मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधी मंडल को बुलाकर सुझाव मांगे एवं सुझाओं पर अमल करने का आश्वासनभी दिया।

झारखण्ड पथ परिवहन श्रमिक संघ के नाम से प्रदेश में दि.9 जून 04 को पंजीयन हुआ है एवं काम तेजी से बढ रहा है।

अखिल भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ

इस महासंघ की स्थापना 1978 में हुई है। पिछले कुछ वर्षो में इस महासंघ के सदस्यता 894155 (वर्ष 2000) से बढकर 1583303 (वर्ष 2002) तक पहुंची है। मध्य प्रदेश के सुखाआकाल स्थिती से पीडीत खेतीहर मजदूरोंकी समस्या लेकर झाबुआ में प्रदर्शन हुआ है।(2500) 10,11 अप्रैल 03 को नागपूर में प्रदर्शन हुआ। इसी के साथ विदर्भ प्रदेश का अधिवेशन भी हुआ। 10,11 मई 03 को बरेली में, 13 मई झारखण्ड में, 15 मई को बिहार में और 17,18 मई को कटकमें बैठके हुई। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रादेशिक धरने हुए। केरल में जिला स्तरीय आंदोलन हुए तथा झारखण्ड में 5 शिक्षा वर्ग हुए।

5,6 जून 04 को कुक्षी मध्य प्रदेशमें महासंघ का त्रैवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। 9 प्रदेशोंसे प्रतिनिधी आये थे।

दि. 25 से 29 अक्तुंबर 04 को मुंबई में महासंघका शिक्षा वर्ग हुवा। भूमि विवाद वनउपज का अधिकार आदी महत्वपूर्ण विषयोंपर अधिवेशनमे पारित प्रस्तावों को महासंघ कार्यान्वित कर रहा है।

सैलाना जिल्हा रत्लाम (मप्र) परियोजनापर बैठक हुई। पिडित श्रमिकोंका बडा जुलूस निकला।

अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ

भारतके कोयला खदानों के संगठनों का यह महासंघ है। इसकी सदस्यता 2002 के आधार पर 273608 है एवं 32 संबंध्द संगठन है। कोयला निजीकरण बिल वर्ष 2000 से संसद में रोकनेका दबाव बनानेका ऐतिहासिक काम महासंघ ने किया है। वैश्विकरण के विरोध में 2002 एवं 2003 में हूए भा.म.संघके केंद्रीय एवं प्रादेशिक कार्यक्रमों मे महासंघ का सक्रिय सहयोग रहा है।

9/10 जनवरी को राणीगंज में कार्यकर्ताओं का अ.भा.शिक्षा वर्ग हूवा (200) 6,7 अक्तुंबर 03 को सीसीएल का शिक्षा वर्ग हूआ (110)। दि. 28/4/03 को कोल बिल 2000 को रोकने हेतू महासंघने संसद पर भारी प्रदर्शन दिया। दि. 17/12/03 को कोल इंडिया के मुख्यालय पर विशेष प्रदर्शन हूआ। 31 मई 04 के प्रदर्शन एवं विशाल सभा के बाद महा प्रबंधक को ज्ञापन प्रस्तुत किया।

वेतन समझौते को नकार कर 29/30 नवंबर 04 को ए बी के एम एस ने देशव्यापी हडताल अकेले की जिसमें अच्छी सफलता मिली।

पिछले 3 वर्षमें सभी संबध्द संगठनोके अधिवेशन संपन्न हूवे जैसे 28/1/03 वर्धा, 28/2/03 जबलपूर, 2/3/03 पाथाखेडा, 11/3/04 सिंगरौली आदी।

महासंघ का त्रैवार्षिक अधिवेशन दि 12–14 फरवरी 04 को सिंगरौलीमें संपन्न हूआ (1400)। श्री बजेंद्रकुमार राय जी नये महामंत्री बने।

अखिल भारतीय खनिज धातू मजदूर संघ

कोयला छोड के अन्य खनिज वस्तू खदानों से निकालने वाले श्रमिकों का यह महासंघ है। इसमें पत्थर की खदाने भी जूडी हुवी है। पुरे देश में 76 संगठन 130123 सदस्यता महासंघ के पास है। 21/12/02 को गुरदरी खदान बंद हुई। उसे कार्यान्वित करने की मांग को लेकर हिंडालको मुख्यालय लोहारदगा (झारखण्ड) पर भारी सफल प्रदर्शन हुवा। दि. 30 दिसंबर 02 को अवैध खननके विरुध्द बॉक्साईट कार्मिकों का उपायुक्त कार्यालय, गुमला, झारखण्ड के सामने भारी प्रदर्शन।

9/10 जनवरी 03 राजगागपूर क्षेत्र में सीटू के संगठन को छोडकर श्रमिकों ने महासंघ में प्रवेश किया। मेराल गाम स्टेशन के 400 लोडींग श्रमिक महासंघ के प्रयास से भा.म.संघ के साथ जूडे है। 28/29 मार्च 03 को खदान ठेकेदारी के खिलाफ छत्तीसगढ के समीर क्षेत्र में श्रमिकों का विशाल प्रदर्शन हुआ। पांच नये संगठन बने है।

2004 में लोहारदगा के महासंघके कार्यालय पर असामाजिक तत्वोने हमला करके अखिल भारतीय अध्यक्ष को घायल किया। महासंघ के बढते प्रभाव को रोकने के लिए खदानों के मालिक अब गुंडा गिरी पर उतर आये है। महासंघ इन परिस्थितीयों का मुहतोड जबाव दे रहा है।

महासंघ का त्रैवार्षिक अधिवेशन दि. 30 मई 04 को रायपूर छत्तीसगढ में संपन्न हूआ। (500) पी एल चंद्राकर, (कोरबा) महामंत्री चूने गये। तीन पहाड वडहरका, सतना, पांकुडी, मालपहाडी, पकाडीया खदान, एवं बस्तर के इलाके में महासंघ का काम बढ रहा है। बालको की समस्या लेकर महासंघ सतर्क है एवं मान्यता कानून से उद्योग हटाकर बहुमत वाले भा.म.संघ के संगठन को मान्यता दिलाने की मांग महासंघने छत्तीसगढ सरकार से की है। गोवा प्रदेश के खदानों मे भा.म.संघ की सदस्यता सबसे ज्यादा है।

अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ

पिछले कुछ सालों से यह ग्रामीण कर्मचारी महासंघ विशेषतः आदीवासी क्षेत्र में काम कर रहा है। जिसकी अथक प्रयासों से अब यह काम लगभग 11 राज्यों में प्रारम्भ है। महासंघ ने शुरु में ही 1.10 लाख की सदस्यता संख्या दर्ज की है। इसका पहला अधिवेशन मध्य प्रदेश के कुंक्षी में 5,6 जून 2004 को हूआ जिसमें 11 राज्यों से लगभग 200 कार्यकर्ता उपस्थित थे। एक जुलूस भी निकाला गया जिसमें लगभग 5000 वनवासी कार्यकर्ता शामिल थे।

पुर्नवास –

रतलाम जिलेमें सैलाना में एक बैठक प्रोजेक्ट इंम्प्लीमेंटेशन कमिटी गठित हुई। जिसमें 3 राज्योंसे लगभग 10 प्रोजेक्ट तज्ञ और 1000 तक वनवासी शामिल थे।

1 दिसंबर 04 में 6 तज्ञोंकी समिती भोपालमें तय की गयी

वनवासी ग्राम बिलखेडी के संपूर्ण विकास के लिए मध्य प्रदेशमें काम शुरु है।

कुर्ला में अक्तुंबर में हुए अभ्यास वर्ग मे 17 कार्यकर्ता उपस्थित थे।

डूप क्षेत्र –

नन्नाडा प्रोजेक्ट के पिडीत देहातीयों के लिए एक समिती गठित हुई और उनके लिए चर्चा सत्र भी हुए। जिसमें लगभग 3000 पिडीत बनवासी उपस्थित थे।

विदीशा –

समसाबाद जिलेमें एक संगठन खडा हुआ जिसका काम शुरु है, जिसमें सभी जगहो से लोग आके मिल रहें है। जो अपनी जमीन के बारें में और विहित न्याय अधिकार के लिए लड रहें है।

रतलाम, धार, झाबुआ, बैवानी जिलो में 5 – 5 ग्रामीण उर्जा विकास निगम के तहत सौर उर्जा से बिजली निर्माण की गयी है।

मध्य प्रदेशके 10 जिलो में ग्रामरक्षक ओर कोतवाल संघ के संघटन भी किए गये है।

अखिल भारतीय शुगर मिल मजदूर संघ

इस महासंघका काम देशके 12 प्रान्तोमें चल रहा है। महासंघ से 157 संगठन संबध्द है एवं महासंघ के सदस्यता 136715 है। मारतके चिनी उत्पादक 2 प्रदेशोमे – (उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र) उद्योगकी स्थिती संकट की है। उद्योगकी बिमारी, सहकारी कारखानों का दिवालियापन, चिनी आयात का संकंट, भ्रष्टाचार एवं राजनेताओं का पग पग पर हस्तक्षेप आदीके चलते श्रमिकों के वेतन समझौते ठिक नहीं हो रहें। वेतन नियमित रुप से नहीं मिल रहा एवं कारखाने चलाने के दिनभी घट रहें इसके कारण से अस्थायी एवं ठेका श्रमिक पर्याप्त वेतन नहीं ले सकते। गन्ना कटाई श्रमिक भी इस उद्योग से संकट से ग्रस्त है। उत्तर प्रदेश में 2 मई 03 को आंठ चिनी मिले बंद करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव के विरुध्द प्रदर्शन सफल रहा। 20 मई 03 को आन्ध्र में वेतन वृध्दीका नया समझौता हुआ।

अखिल भारतीय अधिवेशन उत्तरप्रदेश के अलिगढ में दि. 13/14 मार्च को हुवा। (1070) अधिवेशन में उक्त विषयों पर प्रस्ताव पारित हुए। श्री जगदीशचंद्र शर्मा नये महामंत्री बने।

दि. 5 दिसंबर 03 को चिनी उद्योंगोंकी मांग लेकर दिल्लीमें जंतर मंतर पर महासंघने धरना दिया।

भारतीय सिमेंट मजदूर संघ

देशके सिमेंट उद्योग के 64 संगठन महासंघसे संबंधित है और महासंघकी सदस्यता 23575 (2002) है। महासंघका त्रैवार्षिक अ. भा. अधिवेशन 15, 16 जून को आन्ध्रप्रदेश के तांदूर में संपन्न हूआ। (200) वेतन पुर्ननिर्धारण समझौते के लिये केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करना चाहिए एवं द्विपक्ष वार्ताए तुरंत शुरु हो जानी चाहिए यह महासंघ की मुख्य मांग है। देशके अन्य पांच मुख्य महासंघो ने बी सी एम एस के साथ तालमेल बनाकर चालीस सुत्री मांग पत्र दि. 1 मार्च 04 को प्रबंधकों को प्रस्तुत किया है।

दि. 11 अगस्त 04 को दिल्ली में सांझा धरना हुआ। 19 सितंबर को दिल्ली में संयुक्त सभा का आयोजन हुआ। दि.24 सितंबर को केंद्रिय श्रम मंत्रीजी से वार्ता हो गयी तब से वेतन समझौते की वार्ताए प्रगती पथ पर है।

महासंघ की बैठके गुजरात, पं. बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं आन्ध्र प्रदेश में हुई है। कार्मिकों की मांगे लेकर 25/9 से 2 अक्तुंबर 03 के सप्ताह में उत्तर प्रदेश, राजस्थान हिमाचल प्रदेश आदी प्रदेशों में प्रदर्शन के कार्यक्रम हुए।

सी सी आय कार्मिक संघ, तांदूर (आन्ध्र) में चुनाव द्वारा महासंघ की मान्यता हूई है। हिमाचल में काम तेजी से बढ रहा है।

आंठ प्रदेशोंके 35 कार्यकर्ताओं का शिक्षा वर्ग मुंबईमें 13 से 17 सितंबर 04 को संपन्न हूआ।

अखिल भारतीय कस्ट्रन्क्शन मजदूर संघ

देशके निर्माणी काम में लगे लाखो मजदूरों का प्रतिनिधीत्व करनेवाला यह महासंघ कुछ वर्षो सें कार्यरत है। देश में महासंघ के 310332 सदस्य है और 110 संगठन है।(2002) केंद्र सरकार ने कंस्ट्रन्क्शन मजदूरों के लिए कानून पारित किया है और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। इसी कानून को सक्रिय करने हेतू महासंघ के प्रयास महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान मे चल रहें है। मध्य प्रदेशमें कस्ट्रन्क्शन श्रमिकों के लिए प्रादेशिक सरकारने बोर्ड का गठन किया है। 2003 मे महासंघकी बैठके केरल, आन्ध्र, मध्यप्रदेश, दिल्ली एवं महाराष्ट्र में संपन्न हूई है। 2003 में चार नये संगठन जूडे है।

17/18 जनवरी 04 को केरल के कोट्टायम में महासंघ का अधिवेशन संपन्न हूआ। आम सभा एवं शोभायात्रा में 5000 श्रमिकों का सहभाग रहा।

अखिल भारतीय बीडी मजदूर संघ

बीडी देशका पूराना उद्योग है। धुम्रपान विरोध, विदेशी कंपनीयों के सिगरट के आक्रमण के कारण से वेतन चोरी करनेवाली मालिकों के कारण से बांगलादेश आदी पडोसी देशों से विडी की तस्करी होने के कारण से एवं बिडी मजदूरों की विखरी हूई शक्ति आदी से उद्योग संकट में है। अपने महासंघके 44 संगठन इस समय कार्यरत हैं एवं लाखो की सदस्यता अपनी है।

त्रिपक्ष वर्ताए पारदर्शी हो एवं सरकारके निर्णय सभीकी सलाह से हों यह बात महासंघके दबावके कारण केन्द्रीय श्रममंत्रीजी ने अक्तु 02 मे मानी है।

दि. 21/08/03 को प्रतिनिधी मंडलने मात्र श्रममंत्रीजी को ज्ञापन सौपा। वेलफेअर विभाग में नौकर भरती करानेकी एवं दावोंका निपटारा करनेकी समयबध्द रचना हो यह मांगें भी की गयी।

गृहनिर्माण सहायता रु 40 हजार तक बढवायी है। जनवरी 05 में उडिसा में बीडी श्रमिक मेला हूआ है और काम तेजी से बढ रहा है।

महाराष्ट्र और आन्ध्रमें स्वास्थ चिकित्सा अभियानमें हजारो बीडी कार्मिक लाभान्वित हूए है।

भारतीय स्वायतशासी कर्मचारी महासंघ

महापालिका, नगरपरिषद, नगरपालिका एवं कैटोनमेंट बोर्ड में काम करने वाले देशभर के कार्मिकों का यह महासंघ है। महासंघ के 1,43,000 सदस्य 21 राज्यो में और 273 संगठनो में फैले हुए है। महासंघ का 7वाँ अ.भा.अधिवेशन भावनगर गुजरात में 29,30 मई 04 को संपन्न हुआ (425)। दैनिक श्रमिकों को स्थायी बनाना, अनुकंपा भरती, ठेकेदारी प्रथा समाप्ती, 12 प्रतिशत बोनस, चुंगी फिर से लागू करना और 6वे पे कमिशन आदी महत्वपूर्ण विषयोंपर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हूए। महासंघ की अ.भा.बैठक हर 6 महा में होती है। तथा निम्न बैठके हूई है जोधपूर, हैदराबाद, उज्जैन, वडोदरा, और हरिद्वार।

उपलब्धी : महासंघ ने महाराष्ट्रमें एक रिट अर्ज दायर कर के मांग की थी की म्युनिसिपल कार्मिकों को नियमित वेतन भूगतान हो एवं उन्हे सरकारी कर्मचारी माना जाय। रिट अर्ज मंजूर हूआ है और सरकार को उचित हिदायत दी गयी है।

दि. 12, 13, 14 सितंबर 04 को वडोदरा गुजरात में शिक्षावर्ग संपन्न हुआ।

संसद के सामने 6वे वेतनआयोग की मांग लेकर हुए दि. 18/2/05 के प्रदर्शन में महासंघ ने सहभाग दिया।

भारतीय पोस्टल एम्प्लाईज फेडरेशन

देशमें महासंघ की 10 युनियनें है। 2003 में एक नया संगठन पंजीकृत हुवा है। महासंघकी कुल सदस्यता 196162 है। मान्यता के लिये वर्ष 2000 में संगठनों के बिच चुनाव हुए। जिसमें महासंघ का तिसरा क्रमांक आया। दि. 5/9/04 को फेडरल

एस्कीक्युटीव्ह बैठक हो गई है। महासंघ का त्रैवार्षिक अधिवेशन दि. 19 दिसंबर 04 को मध्य प्रदेशके विदीशा में संपन्न हुआ। महासंघसे संबध्द सात परिसंघो के 1000 प्रतिनिधी उपस्थित थे। श्री. विद्याधर पाठक नये महामंत्री बने है। देश के लाखो कार्मिको की समस्या लेकर उद्योग के बी पी इफ एवं अन्य दो महासंघ सॉझे आंदोलन की तैयारी में है। गिता कृष्णन् समिती की निजीकरण आदी शिफारीशों पर सरकार अमल कर रहीं है। पिछले कुछ वर्षो में कार्मिकों की संख्या 80 हजार से घट गई है। इसके चलते कार्मिकों का कामका बोज बढ रहा है। इ डी कार्मिकों की सेवा शर्तो में कोई सुधार नहीं है कि उक्त समस्याओं पर पोस्टल कार्मिक फिर से एक बार जंग छेडने तैयारी कर रहे है।

भारतीय टेली कॉम एम्प्लाईज फेडरेशन

पिछले तीन वर्ष के कार्यकालमें भारतीय टेलीफोन एम्प्लाईज फेडरेशन की गतिविधी इस प्रकार से है।

दि. 21/22 मार्चको बी टी ई एफ के नये पदाधिकारीयों का चयन हूआ।

4 जूनको–बी एस एन एल आफीसर्स असो. का पंजीयन हूआ। पंजीयन क्र. 4942

दि. 7 अगस्त 02 को बी एस एन एल का वेतनवृध्दी समझौता हूआ। 3.31 लाख कार्मिकों को रु.1500/– से रु 3232/– प्रति माह वृध्दी मिली।

दि. 27/11/02 को देश के सभी सी जी एम मुख्यालयों पर बी एस एन एल मजदूर संघ का प्रलंबीत 25 मांगो को लेकर धरना हूआ।

दि. 18/12/02 एम टी एन एल का संगठन भा.महानगर टेली निगम कर्मचारी संघ के एम टी एन एल मजदूर संघ में विलय का फैसला हूआ।

दि. 11 फरवरी 03 – रेगूलेटरी ॲथोरिटी के फैसले के विरुध्द प्रदर्शन

दि. 18 फरवरी 03 एम टी एन एल का जी एम मुख्यालयों पर धरने का कार्यक्रम (दिल्ली)

दि. 4 मार्च 03 – एम टी एन एल के इ डी कार्यालय पर रैली दिल्ली

29 मार्च 03 भा.म.संघ दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजीत संघर्ष यात्रा में सहभाग

10/11 मई 03 मुजफफरनगर (उत्तर प्रदेश) में बी टी इ एफ का शिक्षा वर्ग (120)

18 जून 03 एम टी एन एल अफसर्स असो. का पंजीयन हूआ। पंजीयन क्र. 4977

दि. 23/7 से 9/8 /03 डब्लु.टी.ओ. के विरुध्द जनजागरण के दिल्ली प्रदेशके कार्यक्रम में सहभाग।

1/9/03 – सी एम डी बी एस एन एल दफतर, नयी दिल्ली में हजारों कार्मिकोंका धरना। चेक आफ, पेंशन, श्रम संघोंके अधिकार आदी बिंदू

2/9/03 को रामलीला मैदान पर हूए महाधरनेमें सहभाग

15/9 से 30/9 – मांगोको लेकर जनजागरण सप्ताह, द्वारसभा, पर्चियाँ बाँटना आदी कार्यक्रम हूए।

19/9/03 को एम टी एन एल के हजारो कार्मिकोंका टेलीकॉम के केन्द्रीय मंत्रीजी के कार्यालय पर प्रदर्शन

1/11/03 को बी एस एन एल अधिकारीयों का मांगो के लिये काम आंदोलन

17/5 से 21/5/04 को मुंबई शिक्षा वर्ग के लिये 15 कार्यकर्ता गये।

9/10 से 11/10/04 को बी एस एन एल मजदूर संघ का भरुच, गुजरात में अ.भा. अधिवेशन संपन्न हूआ।

22/7/04 को एम टी एन एल मजदूर संघ द्वारा इ.डी. कार्यालय पर धरना।

26/10/04 – तीसरे सदस्यता सत्यापनमें एम टी एन एल दिल्ली इकाई में एम टी एन एल मजदूर संघ को मान्यता मिली है।

1/12/04 को बी एस एन एल के दूसरे मान्यता सत्र में बी एस एन एल मजदूर संघ तिसरे क्रमांक पर आया है।

18/19 दिसंबर 04 को बी टी इ एंफ फेडरल कौन्सील की सभा संपन्न हूई। (150)

8 फरवरी 05 सरकार की टेलीकॉम उद्योग में 74 प्रतिशत एफ डी आय लाने के घोषणा के विरोध में बी एस एन एल एवं एम टी एन एल का साँझा प्रदर्शन।

18 फरवरी 05 संसदपर जी. ई. एन. सी. प्रदर्शन में सहभाग

नॅशनल ऑर्गनाजेशन ऑफ इन्शुरन्स वर्कर्स

एन ओ आय डब्ल्यू की बढती ताकत –

अधिवेशनके कार्यकालमें एन ओ आय डब्लयू ने संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास किया है। संघटनके सात नये युनियन बने है। चेन्नै, कटक, कोट्टायम, भोपाल, तंजावर और लखनऊ में एन ओ आय डब्ल्यू के प्रयास से प्रथम श्रेणी अधिकारीयो का संगठन नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ इन्शुरन्स ऑफीसर्स बना है और गतीसे बढ रहा है। बननें के 20 माह के अन्दर ही 20 फरवरी 05 को जीवन बिमा निगम के प्रबंधनने मान्यता प्रदान की है। पेंशन धारकोंका संगठन नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ इन्शोरन्स पेशनर्स 2004 मे निर्माण हूआ है तथा पेंशन धारकोकी समस्याए उठा रहा है।

गतिविधी –

एन ओ आई डब्ल्यू ने आंदोलन हडताल ऐसे कई कार्यक्रम उक्त कालमें माँगो के लिये किये है।

1 जनवरी 2003 में वडोदरा एवं अमरावती के कार्मिकों ने मॉगो के लिये हडताल की उससे आगे बढी वेतन वृध्दी वापस दिलाने में सफलता मिली।

2 फरवरी 03 मे श्री बी के सिन्हा मंत्री एन ओ बी डब्ल्यु का तबादला किया गया। आंठ माहके आन्दोलनके बाद उत्पिडन थम गया तबादला खारीज हूआ।

3 जून 03 में जीवन बीमा निगमकी स्थिती को लेकर भ्रम फैलाने के प्रयास हूए थे। वित्त राज्यमंत्रीजी ने भी बयान दिया था। इसलिए श्वेतपत्रिका निकालने की माँग की थी।

4 एन ओ आई डब्ल्यू का 12 वाँ त्रैवार्षिक अधिवेशन 2,3,4 फरवरी 04 को नांदेड (महाराष्ट्र) में हूआ। श्री एम.पी.पटवर्धन अध्यक्ष, श्री ए.डी.देशपांडे महामंत्री एवं श्री उमेंश प्रसाद संगठन मंत्री बने।

अभी वेतन वृध्दी का आंदोलन चल रहा है। प्रबंधन ने ठेका प्रथा एवं तबादलो की पूर्व शर्त जैसे श्रमवरोधी प्रस्ताव रखे है। युपीए सरकार विनिवेश की उनकी सोच बना रही है। महासंघ डटकर मूकाबला कर रहा है।

नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक ऑफीसर्स

1977 से यह महासंघ कार्यरत है एवं इसके 4 अखिल भारतीय यूनियन संबध्द है। तथा उनके अधिवेशन संपन्न हुए है। बँक ऑफ महाराष्ट्र ऑफीसर्स ऑर्गनायझेशन, 8/1/05 मुंबई (600); यु.वे. बँक ऑफीसर्स ऑर्ग. 25/1/04 इंदौर (800); कॅनरा बँक ऑफीसर्स ऑर्ग. सितंबर 03; सिंडीकेट बैंक ऑफीसर्स ऑर्ग. 25/2/05 (उडीपी) (200)

कम सदस्यता एस बी आई, करपोरेशन बँक, धनलक्ष्मी बँक मै है।

बडोदा बैंक, सेंटन्ल बैंक, विजया बैंक में युनिट बनाने का प्रयास हो रहा है। सहकारी बैंको में भी नोबो के युनिट हैं।

नोबो का त्रैवार्षिक अधिवेशन दि. 6,7, मार्च 04 को पुणे में संपन्न हूवा(350)। श्री एस एन (बापू) जोशी महामंत्री बने है। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, एवं आन्ध्रमें नोबो के प्रादेशिक संघटन है।

वेतन समझौता 2002 से प्रलंबित है और अक्तुंबर 2002 में साँझा, माँग पत्र दिया है। वार्ता के दस दौर हुए है। पेंशन यह विवाद का मुख्य बिंदु बना है।

युपीए की केन्द्र सरकार ने एक तरफ बैंकोके विलय नितीकी घोषणा की है। इसका सभी संगठन विरोध कर रहें है तथा बैंक अधिकारी युध्दस्थिती में है।

उपलब्धी: बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बोमू युनिट पिछले तीन वर्षो में बहुमतवाला बना है। बोमु के महामंत्री श्री पी एन देशपांडेजी भा.म.संघ से, पहलें अफसर संचालक मनोनित हुए है।

नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक वर्कर्स

भारत की सरकारी, व्यापारी, ग्रामीण, सहकारी, आदी सभी बैंको के संगठनोंके परिसंघ का यह महासंघ है। महासंघकी सदस्यता 177846 है एवं 358 संगठन है। (2002) । वेतन वृध्दी की मांग लेकर बैंक क्षेत्रके सभी संगठनो ने साँझा मोर्चा यु एफ बी यु के नामसे बनाया हैं। तथा प्रबंधन को मांग पत्र दिया है। समझौता वार्तामें एन ओ बी डब्ल्यु शुरु से सदस्य है एवं वार्ता के 20 दौर हो चूके है। तबादले एवं ठेका प्रथा को एन ओ बी डब्ल्य पुरजोर विरोध कर रहा है। तथा वार्ता में पेंशन विकल्प को लेकर एक अहम् भूमिका भी अदा कर

रहा है। दि. 25 सितंबर 02 को मांगे मानवाने हेतू दिल्ली में आय बी ए कार्यालयपर धरना कार्यक्रम हुवा। मुंबई में भी 2003 में इस प्रकारसे धरना हूआ। उसके पहले प्रमुख कार्यकर्ताओं का सातारा में शिक्षा वर्ग हुआ।

एन ओ बी डब्ल्यू का अधिवेशन दि. 8–9 जनवरी को बंगलोर में हुवा। पेजावर मठके पु.स्वामीजी विश्वेश्वर तीर्थजी आशिर्वाद देने पधारे एवं वित्त राज्य मंत्री श्री अडसुलजी ने उद्घाटन किया। अधिवेशन में कर्मचारी भर्ती, पेंशन का दुसरा विकल्प, तबादलों का विरोध, अनुकंपा भरती आदी नौ विषयोंपर प्रस्ताव पारित हुए। श्री. के आर पुंजा (बंगलोर) महामंत्री बने। अधिवेशनके बाद कार्यसमितीकी दो बैठके हुईं। 5,6 जुलाई 04 को पहली बैठक पुणेमें एवं दुसरी बैठक 7,8 जनवरी 05 को बंगलोर में हुई। बैंकिंग डिव्हीजन के सामने दिल्ली में दि. 25/2/05 को धरना हुआ।

वेतन समझौते की वार्ता में एन ओ बी डब्ल्यू अग्रणी है एवं सक्रिय है।

भारतीय पोर्ट डाक ॲन्ड शिपयार्ड मजदूर संघ

भारतके बंदरगाह एवं डाकयार्ड के श्रमिकोंके समस्याओं की चिंता करनेवाला यह महासंघ देश के सभी प्रमुख स्थानों को प्रतिनिधीत्व कर रहा है।

इस महासंघ का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। दुसरा एवं तीसरा अधिवेशन विशाखापट्टणम् में हूआ था। अब चौथा अधिवेशन 18–19 दिसंबर 2004 को मुंबई में हुआ। भारतके 12 बंदरगाहो में से महासंघ का काम 9 स्थानों पर है। पंजीकृत संगठन 10 है।

दि. 26/10/04 को विशाखापट्टणम में हूई कार्यसमिती बैठक में यह तय हूआ की शिपयार्ड भी महासंघ के तत्वाधान में काम करेंगे तथा महासंघ का नाम अब भारतीय पोर्ट ॲण्ड शिपयार्ड मजदूर संघ रहेगा। मुंबई में संपन्न चौथे अधिवेशन में 5 मे से 2 शिपयार्ड के एवं 12 मे से 9 पोर्ट के प्रतिनिधी आये थे। शिपयार्ड में 5 स्थानों मे से 3 स्थानों पर भा. म.संघ का पंजीकृत संगठन है।

महासंघ की मान्यता गुप्त मतदानसे चुनाव, एल पी जी नितीयोंका कु– प्रभाव, व्ही आर एस की तरफ ले जानेवाले वैश्विकरण, पोर्ट एवं शिपयार्ड की स्वायतता, संगठन के काममें गतिरोध आदी महत्वपूर्ण विषयोंपर अधिवेशनमें चर्चाएँ हूई।

2002 से 2004 तक महासंघ की बैठके भिन्नभिन्न युनिट में हूई थी। शेष स्थानों पर संगठन शुरु करनेके विषयमें विमर्श हूआ।

कार्यसमिती बैठके :–दि. 25/26 जनवरी 03 को कोलकता में बैठक हुई। दि. 5/6 अप्रैल 03 को न्यु मंगलोर में 21/22 सितंबर 03 को विशाखापट्टणममें और 19/12/04 को मुंबई में बैठकें हुई।

देशके सभी प्रमुख पोर्ट एवं डॉक कार्मिको को वेतन वृध्दी दिलाने हेतू गठीत वेतन समझौते की द्विपक्षीय वेतन वार्ता समितीसे पीछली सरकारने अपने महासंघ को निरिक्षक के स्थान से केवल इसलिये हटाया की मान्यता प्राप्त चार संगठन विरोध कर रहें थे।

भारत सरकार के साथ महासंघने पत्राचार करके महासंघ को अपने स्थान पर पुनः स्थापित करने की गुजारीश की, किंतु सरकारने कुछ नहीं किया और महासंघ के संबध्द संगठन गतिरोध का अनुभव कर रहें है।

बोनसके माँगको लेकर 2004 में अन्य सभी संगठनो जैसी महासंघ ने हडताल नोटीस जारी की। इसलिये महासंघ एवं उसके संबंध्द संगठनों को सरकार ने कन्सीलिएशन को बुलाया था।

मुंबईके अधिवेशन में शिपींग मंत्रालय द्वारा घोषित बंदरगाह नितीपर विस्तृत चर्चा हूई। जिसमें बंदरगाह एवं शिपयार्ड के भविष्यकी योजनाएँ अनुस्युत है। इस निती पर सभी केन्द्रीय श्रम संघो से चर्चा के बादही निती लागू कीजाय इस प्रकार की माँग अंततोगत्वा महासंघ ने प्रस्ताव द्वारा पारित की है। सरकार से यह भी अनुरोध एक प्रस्ताव द्वारा किया गया की संगठन एवं फेडरेशनों की पोर्ट एवं शिपयार्ड में मान्यता की कोई ठोस नितीका निर्माण हो।

अखिल भारतीय आंगनवाडी कर्मचारी महासंघ

तिरुअनंतपूरम अधिवेशन के पश्चात ग्यारह प्रदेश में शाखा गठित हुई। 22 प्रदेशों में महासंघ का काम है। सदस्य संख्या तिनलाख पांच हजार है।

अभ्यास वर्ग :–

महिलाओं की नेतृतव विकास के लिये अखिल भारतीय स्तरपर 8से 12 सितंबर को मुंबई में अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया था। जिसमें बारह प्रदेशोंसे 42 प्रतिनिधी उपस्थित थे। महासंघ का त्रैवार्षिक अधिवेशन 15,16 मई 04 को वडोदरा में संपन्न हुआ है।

आंदोलन :–

अंगनवाडी काय्रकर्ताओं की माँगों को लेकर प्रदेश स्तर पर आंदोलन किये गये। 12/4/02 को रायपूर में (3000), 21/3/03 को भुवनेश्वर (5000), 28/5/03 को

अहमदाबाद मे (3000), 30/6/03 को जयपूर में (5000), 7/7/03 को दिल्ली (1000) 17/9/03 ईम्फालमें (3000), 13/11/03 रांचीमें (3000), 28/9/04 को चंडीगढ़में (4000),

उपलब्धीयाँ –

केंद्र सरकार द्वारा आँगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायकों मानधन दुगुना किया गया। (21/4/02)

प्रदेश सरकार द्वारा उठाये गये कदम :–

दिल्ली प्रदेश सरकार द्वारा अतिरीक्त मानदेय 500/–(कार्यकर्ताओंको), 300/– (सहायिकाओं को) वृध्दी की गयी।

झारखण्ड प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त मानदेय 250/–(कार्यकर्ताओंको), 100/– (सहायिकाओं को) वृध्दी की गयी।

मणीपूर व उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त मानदेय देने का घोषणा हुई है।

राजस्थान सरकार द्वारा अंगनवाडी कार्यकर्ताओं को सुपर वाइझर पदवी में नियुक्त किया गया है।

फरवरी 2003 में मा. प्रधानमंत्रीजीके निवासपर 9 प्रदेशोंकी 1200 आंगनवाडी महिलाओं द्वारा मा. प्रधानमंत्री अभिवादन कार्यक्रम में सहभाग सांसद निधी से आंगनवाडी स्कूल बनाने की महासंघ की माँग और मा.प्रधान मंत्रीजी ने सराहना की।

अखिल भारतीय केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान मजदूर संघ

केन्द्रीय सार्वजनिक उद्योगो की यूनियनों का यह महासंघ है। फेब्रु. 02 के बजट में एल.टी.सी. पर रोक लगी थी। महासंघ के प्रयास से 14/3/02 को फीर से बहाली हुई। 20/21 अक्तु 02 को मथुरा में राष्ट्रीय कार्यसमिती की बैठक हुई। जिसमें निजिकरण की नितीयों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला हुआ।

25 से 27 सप्टें03 को महासंघ की ओर से विशाखापट्टणम् में भा.म.संघ की 102 वी राष्ट्रीय कार्यसमिती बैठक का आयोजन हुवा। 16 अक्तुं 03 को – वेतन विवाद को लेकर दिल्ली बी.एच.ई.एल. मुख्यालय पर विशाल धरना हुवा।

महासंघके अंतर्गत निम्न उद्योगों के परिसंघ गठीत है। एन.टी.पी.सी. पॉवर ग्रीड, बीएचईएल, एन.एच.पी.सी., आदी। परिसंध की बैठकें 13 जुलाई 04 भोपाल एवं 29/8/04 कों हरिद्वार 14/7/04 को झाँसी में हुई। महासंघ ने 25 कार्यकर्ताओं का वर्ग 24/7/ से 28/7/04 को मुंबई में किया। — परिसंघ का अधिवेशन 7,8,9 दिसंबर 03 को तालचेर (उडीसा) में हुआ। तथा 5,6,7 मई 02 को टांडा (उत्तर प्रदेश) एवं 15,16,17 अगस्त 04 को कोरबा (छत्तीसगढ)में शिक्षा वर्ग हूए।

29/9/04 को झांसी मे महासंघ का 8 वाँ अ.भा.अधिवेशन संपन्न हुवा। नवनिर्वाचित पदाधिकारीओं की बैठक दि. 31 अक्तुं 04 को दिल्ली में हुई।

विशेष उपलब्धी : केंद्र सरकारने 25/5/01 को आदेश जारी किया और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्मिकों को मिलने वाला अनुलाभ आयकर के दायरे में ले लिया। महासंघने इसके विरुध्द याचिका क्र.166/02 उच्चतम न्यायालयमें दायर कि है। याचिका स्विकृत हुई और अंतिम सुनवाई शीघ्र ही होने वाली है। इस केस में वर्तमान वित्तमंत्री श्री. पी. चिदंबरम् जी श्रमिकों के अधिवक्ता बनकर प्रतिनिधीत्व कर चुके है।

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ

यह परिषद देशके केंद्रीय एवं राज्य सरकारी कार्मिकों का प्रतिनिधीत्व करता है एवं इसमें सात महासंघ जूडे है।

परिसंघ की ओर से सरकारी कार्मिकों की प्रलंबित मांगो के लिये दि. 4/3/02 से 9/3/02, 18/11/02 से 23/11/02 और 17/2/03 से 22/2/03 से मांग सप्ताह मनाये गये। हड़ताल का अधिकार, डी.ए.मर्जर, छटे वेतन आयोगका निर्माण, पुरानी पेन्शन योजना जारी रखना, आदी मांगो का समावेश था।

आंदोलन के दुसरे चरणमें प्रादेशिक राजधानीयोमें दि.9/8/03 को धरना आयोजित किया गया। तिसरे चरण में दि.12/12/03 को जंतरमंतर, दिल्ली पर एक विशाल धरनेका आयोजन हुआ। भारत सरकार पर दबाव बनाकर पचास प्रतिशत डी.ए.मर्जर का लाभ लाखो सरकारी कार्मिकों को परिसंघने दिलवाया और एक बडी सफलता हासील कर दी।

प्रधानमंत्रीजी के श्रमहितवादी फैसले पर बधाईयाँ देने हेतू प्रधानमंत्री आवास पर

परिसंघ ने दि. 21/2/04 को कार्यक्रम किया।

परिसंघ के घटक महासंघो के अधिवेशन संपन्न हूए ये इस प्रकार : राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ 7,8 फेब्रुवारी04 कोटा (500); भारतीय कॉईन करन्सी ॲन्ड कर्मचारी संघ 13,14 फेब्रुवारी 04 नाशिक रोड (300); भारतीय रेल्वे मजदूर संघ 19,20 जून 04 चेन्नई (1200); भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ 23,24,25 नोव्हें 04 खमरिया (जबलपूर) (1200); केंद्रीय कर्मचारी महासंघ 9 अक्तुंबर 04 दिल्ली; भारतीय टेलीकॉम एम्प्ला.फेडरेशन 11 दिसंबर04 दिल्ली; भारतीय पोस्टल एम्प्लाईज फेडरेशन 19,20 दिसंबर 04 विदीशा (म.प्र) (400)

सी ई सी बैठक 10/10/04 को नई दिल्ली में संपन्न हूई। 14 से 18 फेब्रुवारी 05 को मांगसप्ताह मनाया एवं 18/2/05 को जंतर मंतर नई दिल्ली पर प्रदर्शन हुआ।(400)

भारतीय करन्सी ॲण्ड कॉइन्स कर्मचारी महासंघ

महासंघ की दि. 23–2–02 से 28–2–05 के काल की गतिविधी का वृत्त

महासंघ के महामंत्री श्री. बी. के जग्गीजी ने आय जी मिंट, सिक्युरिटी एवं करन्सी प्रेस और एस.पी.एम. का संगठनात्मक दौरा किया.

दि. 26–2–02 से 2–3–02 तक मैसूर, हैदराबाद, दि. 9–9 से 20–9 हैदराबाद, देवास एवं भोपाल, दि. 25–26 नवंबर 02 को मुंबई, दि. 28–29 नवंबर आय.एस.पी. कॅम्प, नासिक रोड, दि. 15 से 23 अप्रैल 03 – मुंबई, नासिक रोड, होशंगाबाद, देवास दि. 14 से 17 सितंबर 03 – कोलकता, दि. 25–26 सितंबर – हैदराबाद दि. 9–14 फरवरी 04 – नासिकरोड, दि. 16–17 फरवरी मुंबई।

महासंघ की कार्यसमिती बैठके :

उक्त बैठके निम्न स्थानोंबर हुई। 23 फरवरी 02 – थिरुवानंतरपुरम्; 23–24 जनवरी 03 – होशंगाबाद; 24–25 दिसंबर – कोलकता; 23 फरवरी 04 – नासिक रोड, 14–15 अगस्त – मुंबई।महासंघ की पुणे बैठक मे दि. 8–9 नवंबर 03 को अध्यक्ष एवं महामंत्रीजीने सहभाग दिया।

केंद्रीय वित्तमंत्री श्री. जसवंत सिंहजी को दि. 24–05–03 को डीएसओ स्टाफ के स्थानपर सीआयएसएफ लाने का आयएसपी/सीएनपी नासिक रोड के योजना का विरोध एवं रिफार्म कमिशन रिपोर्ट के विरोध मे अपना ज्ञापन दिया। दि. 21–02–04 को मा. प्रधानमंत्री को मिलकर ज्ञापन दिया की वित्तमंत्री इआरसीकी रिपोर्ट रोक दे। महासंघ का तिसरा अधिवेशन 11–12 फरवरी 04 को नासिक मे संपन्न हुआ। श्री. बी. के जग्गी (अध्यक्ष) श्री. ए. के. देशपाण्डे (महामंत्री) श्री. ओमप्रकाश (वित्तमंत्री) चुने गये। 6 वे वेतन आयोग की माँग करने वाला माँग सप्ताह सभी युनियनों ने मनाया।

अखिल भारतीय मत्स्य मजदूर महासंघ

भारत के तटवर्ती प्रदेशोमें समुंदर में मछली पकडने वाले एवं उस उद्योग से संबंधीत कर्मिक मजदूर मछुवारे करोडों की संख्या में है।

उसी प्रकारसे अन्य प्रदेशोके मीठे पानी से मछली पकडने वाले भी बडी मात्रा में है।सरकारकी नितीके तहत विदेशी ठेकेदारोंको समुंदर में मछली पकडने का ठेका देना एवं मीठे पानी की झील /तालाब, नदीयों में भी इसी प्रकार से ठेका देना इसके कारण से एवं वन्य जीव सुरक्षा के उपक्रमों के अंतर्गत मछली पकडने पर पुरी पाबंदी लगाना आदी के कारन से उद्योग संकट में है।

समुंदरी यातायात से एवं तेल रिसाव के प्रदुषण से पानीमें प्रदुषण फैलानेके कारण से जीवचक्र में असंतुलन आया है, यह भी चिंताका विषय है। इन समस्याओं के निराकरण हेतू इस क्षेत्रमें काम करने वाले संगठनों को भा.म.संघ ने अ.भा.स्तरपर महासंघ के तहत जोडने का निर्णय किया।

इस नये महासंघका निर्माण 12/13 सितंबर 04 रामेश्वरम् मे हूवा। इस प्रथम अधिवेशनको देशके पांच प्रदेशोंसे सैकडो प्रतिनिधी आये थे।

श्री.ओ बी रविंद्रन अ.भा.अध्यक्ष; श्री एन एम् सुकुमारन महामंत्री चुने गये है। केरल का मत्स्य प्रवर्तक संघ प्रभावी काम कर रहा है और सुनामी पीडीतो की काफी सहायता भी कर रहा है। तमिलनाडू के तमिलनाडू मीनावती संघम् इस महासंघ का प्रादेशिक अधिवेशन भी संपन्न हूआ है। 2000 सुनामी पीडीतोंको सहायता यह महासंघ कर रहा है। 2004 में महाराष्ट्र के जळगांव जिलेमें यह काम शुरु हूआ है।

भारतीय ठेका मजदूर संघ

भारतीय ठेका मजदूर महासंघ का प्रथम अधिवेशन दिनांक 26,27 जून 2004 को कटक (उडीसा मे) संपन्न हुआ। जिस में नई कार्यकारिनी का गठन किया गया। 27 जून 2004 को खुला अधिवेशन हुआ जिसमें सैकडो ठेका श्रमिको ने भाग लिया, ठेका श्रमिकों का काम अभी 14 प्रदेशों मे है, जिस मे 50 यूनियन कार्यरत है। जम्मू–काश्मीर, उडीसा, बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराँचल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, विदर्भ, बिहार, कर्नाटक, आंध्र व केरला आदि मे यूनियन कार्यरत है। अधिवेशन मे प्रस्ताव भी पास किए गए।

ठेका मजदूरों का देश मे बहुत शोषण होता है। कानून का भी लाभ नही मिलता व नौकरी की सुरक्षा भी नही है, और उन्हे काम भी नही मिलता। इसलिये कानून मे बदलाव व सुधार ठेका श्रमिकों के लिए बहुत आवश्यक है। ठेका श्रमिक (मय) अधिनियम 1970 मे तुरन्त संशोधन, सुधार अथवा निरस्त किया जाये।

उडीसा व आंध्र–प्रदेश मे ठेका श्रमिकों के संगठन बने है, और भा.म.संघ से जुडे है। जम्मू–काश्मीर, उडीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ, बंगाल मे ठेका श्रमिक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे है। साथ ही कानूनी लडाई भी लड रहे है। अभी नया संगठन बना है और भविष्य मे प्रभावशाली संगठन बनेगा । इस दृष्टी से संपर्क एवं प्रवास की योजना बन रही है।

भारतीय हॅण्डलूम मजदूर संघ

महासंघ का दूसरा त्रैवार्षिक अधिवेशन प. बंगाल के नडिया जिलेमे नबद्वीप धाम मे दि. 15–16 मार्च 03 को संपन्न हुआ। अधिवेशनमे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए है। धागे पर लगाई 1: एक्साईज ड्युटी को खारीज करना, इपीएफ, वृद्घत्व पेंशन, चिकित्सा एवं अपघात से सुरक्षा आदी की माँगे की गयी।

कपडा नीतीके तहत आज की रचना मे हैंडलूम की भी गिनती होती है। इससे हैडलूम क्षेत्र का नुकसान है। इसलिये टेक्स्टाईल से इसे अलग करना चाहिये ऐसी भी माँग अधिवेशन मे उठाई ।

पावरलूम एवं टेक्स्टाईल का आक्रमण न हो इस हेतू से हैण्डलूम क्षेत्रमे परंपरा से चलते आये डिझाईन को सुरक्षा मिलनी चाहिये।

भारत सरकार द्वारा पारित हैण्डलूम एक्ट के तहत हॅण्डलूम द्वारा उत्पादीत 11 उत्पादनों को सुरक्षा प्रदान की गयी है। इस सुरक्षा के प्रवाधान का कडाईसे अंमल हो यह माँग की गयी है।

भारतीय प्लांटेशन मजदूर महासंघ

(भा.प्ला.म.म.संघ) महासंघ का काम केरल, तामिलनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, आसाम, त्रिपुरा, प.बंगाल, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश इन 9 प्रदेशों मे है।

महासंघ का प्रथम अधिवेशन केरल के इड्डीकी जिले मे कमली गाँव मे दि. 19–20 जून 04 को हुआ। करीब 200 प्रतिनिधी त्रिपुरा, असम, पं. बंगाल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू, केरल इन प्रदेशोसे आये थे। पूर्वोत्तर प्रदेशो से 39 प्रतिनिधी आये थे। बंद हुअी चाय बागानों को फिर खोलना, बीमार बगानों को ठीक बनानेका उपाय खोजना, चाय की आयात पर रोक, कॉफी रबड, मसाले आदि पदार्थों की आयातपर रोक। निर्यात बढाना। त्रिपक्षीय केंद्रीय एवं प्रादेशिक समितीयों मे महासंघ को स्थान की मांग, समितीयों का ठीक संचालन हो।

टी बोर्ड, काफी बोर्ड, मसाले बोर्ड, वेतन समझौता समिती, प्रॉ. फंड पर उचित प्रतिनिधीत्व की मांग आदी इन सभी विषयों पर प्रस्ताव पारित हुए है। अधिवेशन के खुले सत्रमे इडुक्की जिले के हजारो श्रमिक सहभागी हुए थे।

असमके नोगांव जिलेके 22 चाय बगानों के सभी श्रमिक भारतीय चा मजदूर संघ के सदस्य बने है। टाटा चाय कंपनी एवं असम चाय कंपनी ने साप्ताहिक वेतन के बजाय पाक्षिक वेतन देने का समझौता इंटक के साथ किया। इसका श्रमिकों मे रोष है। श्रमिकों की ओर से भा.म.संघ ने कार्यवाही शुरू की है। और विरोध दर्ज किया है।

भारतीय कागज उद्योग कर्मचारी महासंघ

भा.म.संघ का यह महासंघ राष्ट्रीय स्तर का एक मात्र महासंघ है। कागज उद्योग के अलग वेज बोर्ड की मांग को लेकर महासंघ ने दि.7/9/04 को दिल्ली में प्रदर्शन दिया। बोनस कानून में सुधार की मांग को लेकर हजारो श्रमिकों का हस्ताक्षरीत ज्ञापन महासंघने महामहिम राष्ट्रपतीजी को भेजा है तथा स्थानिक मांगोको लेकर महासंघ संघर्षरत है। महासंघ के 35 पंजीकृत संगठन है। और दस हजार से ऊपर सदस्यता है। श्रीपूर कागज नगर (आन्ध्र) में इंटुक को आसानी से महासंघ ने चुनाव में परास्त किया है।

महासंघका अखिल भारतीय त्रैवार्षिक अधिवेशन दि.1,2, जून 04 को गोंदिया (विदर्भ)में संपन्न हूआ।

परिशिष्ठ 2

सदस्यता सत्यापन

State	1980	1989		1997		2002	
	Members	**Unions**	**Members**	**Unions**	**Members**	**Unions**	**Members**
Andaman& Nicobar				4	932	8	1 346
Andhra Pradesh	14 565	383	5 74 017	407	8 92 734	392	15 91 242
Arunachal Pradesh		1	175	1	310	1	309
Assam	49 280	18	75 080	24	1 45 209	29	1 63 596
Bihar	1 59 843	174	3 29 830	221	7 19 695	125	4 17 903
Chandigarh		15	5 000	14	6 016	14	6 417
Chattisgarh*						59	2 65 258
Delhi	1 20 937	101	4 57 811	112	6 44 793	117	5 26 571
Goa		6	3 029	9	20 602	15	73 253
Gujrath	10 436	87	20 216	93	1 95 739	105	2 11 369
Haryana	27 606	132	51 064	163	1 78 940	151	1 58 136
Himachal Pradesh		66	40 131	77	51 429	129	94 657
Jammu & Kashmir		30	16 342	31	26 508	41	30 324
Jharkhand**						117	3 98 637
Karnataka		118	59 178	123	68 280	110	66 307
Kerala	3 276	152	28 618	186	95 755	209	2 02 154
Madhya Pradesh	67 810	198	1 68 759	454	6 86 126	388	7 98 516
Maharashtra	1 76 554	257	2 03 000	218	4 38 382	275	5 72 226
Vidarbha		69	1 10 330	70	1 16 845	103	2 09 687
Manipur				1	208	3	5 663
Meghalaya				1	1 320	1	1 102
Mizoram						4	5 159
Nagaland		1	250				
Orissa	7 583	28	6 218	102	94 049	136	5 38 450
Pondichery		2	104	1	98	1	98
Punjab	65 835	210	1 19 797	241	1 99 725	287	2 75 149
Rajasthan	86 958	250	2 29 036	467	4 80 291	395	5 98 976
Tamilnadu	5 710	26	26 542	53	67 279	79	1 00 506
Tripura		1	450	8	3 713	8	4 006
Uttar Pradesh	2 60 984	488	4 50 826	656	6 93 349	661	6 53 661
Uttaranchal***						90	1 09 101
West Bangal	90 987	156	1 41 521	220	2 22 308	183	2 38 569
Total	**11 48 364**	**2 969**	**31 17 324**	**3 957**	**60 50 635**	**4 236**	**83 18 348**

* New state came in existence after sub division of Madhya Pradesh
** New state came in existence after sub division of Bihar
*** New state came in existence after sub division of Uttar Pradesh

परिशिष्ठ 2

सदस्यता सत्यापन

Sr.	Industry	Unions	Members
1	Textiles	236	3 36 717
2	Clothing	36	1 02 709
3	Jute	54	83 586
4	Iron and Steel	53	96 692
5	Metals	26	12 934
6	Engineering	402	3 39 605
7	Defence	183	94 236
8	Electric, Gas and Power	133	3 34 021
9	Transport Railways	22	8 94 448
10	Water Transport / Waterways	5	2 048
11	Roadways	226	4 68 711
12	Air Transport	4	2 070
13	Plantations	34	1 36 843
14	Coal Mining	32	2 73 608
15	Mining of Minerals other than Coal	60	63 880
16	Quarrying	16	66 243
17	Agriculture and Rural workers	132	15 83 303
18	Sugar	157	1 36 715
19	Cement	64	23 575
20	Chemicals	215	59 954
21	Building Constructions	110	3 10 332
22	Food and Drinks	197	1 19 990
23	Tobacco	42	7 06 351
24	Tanneries and Leather goods manufacturers	17	12 639
25	Paper and Paper Products	64	17 259
26	Printing and Publishing	56	21 056
27	Local Bodies	243	1 50 223
28	Glass and Potteries	25	7 374
29	Petroleum	25	36 027
30	Salaried Employees and Professional workers	338	3 19 155
31	P And T Workers	10	2 65 162
32	Hotel, Restaurants, Tourism and Others	55	69 555

33	Hospitals and Disp., Medical and Health Services	71	74 217
34	Personal Services	95	1 72 021
35	Financial Institutions	358	1 77 846
36	Ports, Docks and Maritime	15	8 778
37	Coir	2	800
38	Brick Kilns / Tile Manufacturing	19	95 821
39	Wood, Plywood and Wood Products	24	30 506
40	Rubber Products	34	5 842
41	Pencil Industry	3	1 374
42	Soaps and Detergents	4	1 060
43	Self Employees	44	55 469
44	Miscellaneous	346	5 47 593
	Total	**4 287**	**83 18 348**

फिर से दिल्ली की ओर –

विश्व व्यापार संगठन की हॉगकॉग मे डिसेंबर 2005 में परिषद होगी। विकसनशील देशोंमे खेती के लिए अनुदान और पेटंट के मुद्दे इस परिषद में उठनेवाले है।

दोहा तथा कानकून परिषदों मे जो मुद्दे उठाये गये थे उसपर यु पी ए सरकारने कोई गौर नही किया परिणामतः युरोपियन देशों से अनुदान कम करने के लिए समय की सीमा तय नहीं हो पायी।

अगर हाँगकाँग परिषद में इन मुद्दोंपर गंभीर परिणाम होने की संभावना है (विशेषतः खेती मजदूर, छोटे किसान)।

इसके खिलाफ लडने के लिए भा.म.संघ कटिबध्द है। इन से बाहर निकलने के लिए 'स्वदेश व स्वदेशी' का विचार होना आवश्यक है।। भा.म.संघ का अगला कदम है– लोंगो मे जागृती लाकर उनको एकत्रित कर दिल्ली में बहुत बडी रॅली का आयोजन करना। इस रॅली के जरिये यु पी ए सरकार का ध्यान इस गंभीर स्थितीपर आकृष्ट करना।

भा.म.संघका 14 अधिवेशन दिल्ली में संपन्न हो रहा है। भा.म.संघ मानो एक सघनवृक्ष है–हजारों युनियन्स से इसकी टहनी बनी है और पत्ते है लाखो सदस्य।

संविधान संशोधन
Constitution Amendments

On 14th All India Conference on 3, 4, 5 April 2005, Delhi.

14वाँ त्रेवार्षिक अधिवेशन 3, 4, 5 अप्रैल 2005, दिल्ली

धारा 10 के (अङो) में निम्नानुसार संशोधन करना:–

पदाधिकारी

उपाध्यक्ष – 10 से अधिक नही।
मंत्री – 10 से अधिक नही।

Clause 10 (E)

Office Bearers

Vice President - Note more than 10

Secretaries - Note more than 10

शत नमन माधव चरण में, शत नमन माधव चरण में ।।धृ.।।

आपकी पीयूष वाणी शब्द के भी धन्य करती, आपकी आत्मीयता थी, युगल नयनों से बरसती।
और वह निश्छल हँसी जो गूँज उठती थी गगन में।।1।।

ज्ञान मे तो आप ऋषिवर, दीखते थे आद्य शंकर, और भोला भाव शिशुसा, खेलता मुख पर निरन्तर।
दीन-दुखियों के लिए थी, द्रवित करुणा धार मन में।।2।।

दु:ख-सुख निन्दा-प्रशंसा, आपको सब एक ही थे, दिव्य गीता-ज्ञान से युत, आप तो स्थितप्रज्ञ ही थे।
भरतभू के पु उत्तम, आप थे युग पुरूष जन्मे ।।3।।

मेरु गिरिसा मन अडिग था, आपने पाया महात्मन्, त्याग कैसा आपका वह, तेज साहस शील पावन।
मात्र दर्शन भस्म कर दे, घोर षड्रिपु एक क्षण में ।।4।।

सिन्धु-सा गम्भीर मानस थाह कब पाई किसी ने, आ गया संपर्क में जो, धन्यता पाई उसी ने।
आप योगेश्वर नये थे, छल-भरे कुरुक्षेत्र रण में ।।5।।

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्।
सुजलां सुफलां मलयजशीतलां।
शस्य श्यामलां, मातरम्।। वन्दे मातरम् ।।1।।
शुभ्र-ज्योत्सनां पुलकितयामिनी,
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनी,
सुहासिनीं सुमुधर भाषिणीं
सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम् ।।2।।

कोटि-कोटि कंठ-
कलकल-निनाद-कराले
कोटि-कोटि भुजैर्धृतखरकरवाले,
अबला केनो माँ एतो बले
बहुबल धरिणीं, नमामि तारिणीं
रिपुदलवारिणीं, मातरम्। वन्दे मातरम् ।।3।।

तुमि विद्या, तुमि धर्म।
तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वं हि प्राणाः शरीरे।
बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदये तुमि माँ भक्ति,
तोमारइ प्रतिमा गड़ि
मन्दिरे मन्दिर। वन्दे मातरम् ।।4।।

त्वं हि दुर्गा, दशप्रहरण-धरिणीं
कमला कमल-दल-विहारिणीं,
वाणी विद्या-दायिनी नमामि त्वां
नमामि कमलां, अमलां, अतुलां,
सुजलां, सुफलां, मातरम्। वन्दे मातरम् ।।5।।

श्यामलां, सरलां, सुस्मितां, भूषितां
धरणीं, भरणीं मातरम्। वन्दे मातरम्।। वन्दे मातरम् ।।6।।